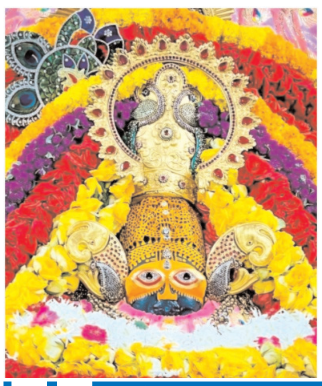

RNI No. GUJHIN/2010/35230

महानगर मेट्रो

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र

कार्यालय :- सी-8 रिची हाउस, स्वामी नारायण मंदिर के सामने मणिनगर अहमदाबाद गुजरात-380008

महानगर मेट्रो
राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, प्रेस नोट एवं विज्ञापन के लिए कार्यालय पर सम्पर्क करें
सरबजीत माकन
+91-9638877700
mahanagarmetro7@gmail.com

वर्ष :15 । अंक:359। पेज:।12 mahanagarmetro7@gmail.com || अहमदाबाद, 20 अगस्त 2026 (गुरुवार) || सम्पादक - सरबजीत माकन (9638877700)।। मूल्य :- 1.50 रु.-/

सार-समाचार

नौकरी खत्म करने के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों अभ्यर्थी

'न्याय दो या फांसी दो' के नारे के साथ प्रदर्शन

रांची (एजेंसी)। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों और नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार शाम से ही सैकड़ों की संख्या में जुटे सफल अभ्यर्थी और प्रभावित कर्मचारी प्रोजेक्ट भवन (झारखंड मंत्रालय) के मुख्य द्वार पर जमे हुए हैं और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर सुरक्षा घेरा पार किया और प्रोजेक्ट भवन परिसर के भीतर प्रवेश कर गए। प्रदर्शनकारियों ने 'इंसाफ दो या फांसी दो' के नारे लगाए। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और कर्मचारी रातभर प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे रहे। उनका कहना है कि सरकार के फैसले से उनकी नौकरी और भविष्य दोनों पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति में अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: दो चरणों में होगा मतदान

9 और 11 सितंबर को वोटिंग

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के विस्तृत कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तारीखों का ऐलान किया। 14 सितंबर को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के संबंधित निकाय क्षेत्रों में 'आदर्श आचार संहिता' तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। दो चरणों में संपन्न होगी मतदान प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे:

पहला चरण: प्रथम चरण के लिए 9 सितंबर 2026 को मतदान करवाया जाएगा।

दूसरा चरण: द्वितीय चरण के तहत 11 सितंबर 2026 को वोट डाले जाएंगे।

कोलकाता एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन के मामले में सौगत राय ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

कोलकाता(एजेंसी)। कोलकाता हवाई अड्डे के बाहर मंगलवार को अपने वाहन को घेरकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किए जाने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भाजपा के दो विधायकों अरिजीत बक्सी और सौरभ शिकदार को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल, सौगत राय मंगलवार को कोलकाता हवाई अड्डे की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट निदेशक के कार्यालय पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही वह अपने वाहन में बैठे, प्रदर्शनकारियों ने वाहन को घेर लिया और 'चोर-चोर' के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने जूते से वाहन के बोनट पर भी प्रहार किया। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच से किसी तरह सौगत राय के वाहन को बाहर निकाला।

टिकरी कलां में सीएनजी स्टेशन पर गैस टैंक फटा

तीन की मौत, कई लोग घायल

सभी घायलों को मुंडका के सीबी ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में बुधवार को एक सीएनजी स्टेशन पर वाहन में गैस भरते समय उसके गैस टैंक में जोरदार विस्फोट हो गया। समाचार एजेंसी के मुताबिक, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट की चपेट में आने से पास में खड़े छह लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा को घटना की सूचना अपराह्न 3.37 बजे मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए और स्थिति को नियंत्रण में किया। घायलों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

'भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है जम्मू-कश्मीर'

अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान, घाटी को बताया खूबसूरत जगह

एजेंसी

श्रीनगर। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा चेतावनी को लेकर बड़ा संकेत दिया। सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका समय-समय पर अपनी यात्रा चेतावनियों की समीक्षा करता है। उन्होंने कहा कि वह आज कोई बड़ा एलान नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका इस चेतावनी पर विचार करेगा। गोर ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने की दिशा में शानदार कदम उठाए हैं। इसलिए अमेरिका यह देखेगा कि उसकी ओर से जारी यात्रा चेतावनी को कम किया जाना चाहिए या नहीं। गोर ने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एक खूबसूरत क्षेत्र है और उन्हें लगता है कि कई अमेरिकी यहां आकर इसकी खूबसूरती और यहां मौजूद अवसरों को देखना पसंद करेंगे।

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा हुई। खास तौर पर इस बात पर बातचीत हुई कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ पुराने मुद्दे हैं, जिन्हें समय के साथ सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आगे भी यह बातचीत जारी रहने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे की बातचीत सर्जियो गोर और अमेरिका के बीच भी होगी। वहीं, वह खुद नई दिल्ली में भारत सरकार के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ेगा।

'बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बढ़ती उम्र का मतलब अपमान-असुरक्षा नहीं

हाईकोर्ट का फैसला पलटा

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण-पोषण या सुरक्षा में बाधा बन रहा है, तो वह उन्हें अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं।' जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं हैं। सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लखनऊ के रवि कांत गुप्ता से जुड़े मामले में सुनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमे अपने बेटे और बहू को घर से निकालने के SDM और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था।

लखनऊ के मकान से जुड़ा है मामला

रवि कांत गुप्ता लखनऊ के विकास नगर में रहते हैं। उनकी 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहना पड़ा था। आरोप था कि उनके बेटे यानी गुप्ता के पोते ने उन्हें घर में रहने नहीं दिया। आरोप था कि उसके बेटे ने ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। इसके बाद SDM ने 15 नवंबर 2022 को बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को इस आदेश को बरकरार रखा और बेटे-बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा था- कानून में बेदखली का अधिकार नहीं

बेटे और बहू ने एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों आदेश रद्द कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है।

प्रयागराज में बारिश की मार...!

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गौस नगर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद रामबाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए।

'मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे'

ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले- पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा

एजेंसी

मुंबई । मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा, जिनके पास मराठी का 'वर्किंग नॉलेज' यानी कामचलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में एक महीने तक चलेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा।

आरटीओ की टीमें जांच करेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी

मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस एक महीने के अभियान की निगरानी करेंगे। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वॉड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेंगी और नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगी। जांच के दौरान वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

वर्किंग नॉलेज का मतलब साफ नहीं, ड्राइवरों में चिंता

सेवा सारथी ऑटो-रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता डीएम गोसावी ने कहा कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी कर दिया है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि आखिर कितनी मराठी जानना जरूरी होगी। उनका कहना है कि नियम स्पष्ट नहीं होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों के आर्थिक शोषण की आशंका बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो-टैक्सी ड्राइवर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से आते हैं। इनमें कई ड्राइवरों को मराठी नहीं आती या वे बहुत कम मराठी बोल पाते हैं। ऐसे ड्राइवरों को लाइसेंस और परमिट रद्द होने का डर है।

महुआ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

बार-बार समन के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुईं टीएमसी सांसद

एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला कथित तौर पर महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़ा है। कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट की तामील की रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है। मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए पूर्व-संज्ञान समन जारी किए थे। अदालत ने कहा कि महुआ मोइत्रा को कई बार समन भेजे गए। इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं।

बिना बीमा पेट्रोल नहीं: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश

दिल्ली से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

एजेंसी

नई दिल्ली। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऐसे पायलट प्रोजेक्ट को लागू करे, जिसमें वैध बीमा नहीं होने पर पेट्रोल पंपों से वाहन को ईंधन ही न मिले। कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत दिल्ली से की जा सकती है। बुधवार को यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के सामने आया। केंद्र की ओर से पेश वकील ने चार अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस व्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं हैं। इस पर पीठ ने साफ कहा, 'आपको इसे लागू करना होगा।' कोर्ट ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू किया जा सकता है। केंद्र के वकील ने बताया कि इसके लिए तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल पंप डीलरों के साथ बैठक करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा, 'आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें।' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक ठोस प्रस्ताव पेश करने को भी कहा है। इसमें चार अगस्त के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने की समयसीमा बतानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

चार अगस्त के फैसले में क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को दिए अपने फैसले में बिना तीसरे पक्ष के बीमा के सड़कों पर चल रहे बड़ी संख्या में वाहनों पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। इसमें वाहनों को मिलने वाले ईंधन को उनके वैध बीमा की स्थिति से जोड़ा जाए। यानी अगर किसी वाहन का वैध बीमा नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर उसे ईंधन न दिया जाए। वाहन मालिक को पहले वैध बीमा कराना होगा। इसके बाद ही उसे ईंधन मिल सकेगा।

बिना बीमा वाहनों की पहचान में मिलेगी मदद

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था के दो बड़े फायदे बताए थे। पहला, इससे बिना बीमा या बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दूसरा, वाहन मालिकों पर वैध बीमा कराने का दबाव बनेगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के प्रावधानों का जमीन पर पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए एएनपीआर यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

टोल प्लाजा पर भी ऑटोमैटिक व्यवस्था के निर्देश

चार अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों के असर पर भी ध्यान दिया था। कोर्ट ने कुछ कॉरिडोर पर पायलट प्रोजेक्ट लागू करने का निर्देश दिया था। इसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रोकने के बजाय टोल प्वाइंट से गुजरने वाले वाहनों की ऑटोमैटिक पहचान की व्यवस्था करने की बात कही गई थी।

कर्जन म्युनिसिपैलिटी में 'टेंडर राज' और करोड़ों का कमीशन मॉड्यूल

नगरपालिका में 'टेंडर राज' के आरोप: करोड़ों के कमीशन मॉड्यूल से लेकर कथित मंथली पैकेज तक, पूरे सिस्टम पर उठे सवाल

'जीरो टॉलरेंस' के दावों के बीच कर्जन में भ्रष्टाचार के आरोप, विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा

कर्जन के टेंडर विवाद की आंच गांधीनगर तक? BJP नेतृत्व के सामने जवाबदेही की चुनौती

महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

वडोदरा। गुजरात में 'करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस' के सरकारी दावों के बीच, सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है कि वडोदरा जिले की कर्जन म्युनिसिपैलिटी करप्शन, कमीशनखोरी और टेंडर सेटिंग का एक बड़ा अड्डा बन गई है। लोकल लेवल पर चल रहा यह ऑर्गनाइज्ड स्कैम BJP के 'गुड गवर्नेंस' की इमेज को बुरी तरह खराब कर रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप और दिल्ली हाईकमान को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है।

चीफ ऑफिसर और टेंडर माफिया का 'सिंडिकेट मॉडल'

कर्जन म्युनिसिपैलिटी में पब्लिक टैक्स का करोड़ों का पैसा सीधे बिचौलियों और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। नगर पालिका में टेंडर प्रोसेस अब कोई ट्रांसपेरेंट सरकारी नियम नहीं रहा, बल्कि कुछ माफियाओं को फायदा पहुंचाने का एक ज़रिया बन गया है डेटा लीक और कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन: नियमों को नज़रअंदाज़ करके, नगर पालिका का चीफ ऑफिसर बार-बार टेंडर देने वाली संस्थाओं के रेट, डॉक्यूमेंट्स और नाम-पते जैसी सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी 'टेंडर माफिया' को देता है। धमकी और दबाव की पॉलिसी: जानकारी मिलते ही, माफिया, एक ताकतवर नेता के इशारे पर, दूसरे कॉम्पिटिटर कॉन्ट्रैक्टर्स को डराता है, उन्हें कानूनी या फिजिकल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर टेंडर वापस लेने पर मजबूर करता है।

तय और बहुत ज़्यादा कीमतें: नतीजतन, बिना किसी हेल्दी कॉम्पिटिशन के कुछ एजेंसियों को ऊंचे दामों पर कॉन्ट्रैक्ट देकर करोड़ों रुपये तय किए जाते हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ़ एक रबर स्टैम्प: एक ताकतवर BJP नेता का पैरेलल राज

स्थानीय नागरिकों और नगर पालिका के अंदर के लोगों के बीच चर्चा में आई जानकारी के अनुसार, करजन नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष पूरी तरह से बेबस और मूक दर्शक बने हुए हैं। पूरा म्युनिसिपल वहीवटदार एक ताकतवर लोकल BJP नेता के इशारे पर चलता है। सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट या ब्यूटीफिकेशन का कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो – हर काम में एक तय परसेंटेज (कमीशन) तय किए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। इसी मिलीभगत की वजह से आरोप लग रहे हैं कि चीफ ऑफिसर जल्द ही करोड़ों रुपये की बेनामी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे।

सूत्रों का चौंकाने वाला दावा: 'महीने का पैकेज' ऑर्गनाइजेशन तक पहुंचता है

यह स्कैम सिर्फ करजण शहर तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस करप्शन के बावजूद लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई एक्शन न होने की मुख्य वजह 'किस्त सिस्टम' है। करजण म्युनिसिपैलिटी से कमीशन के तौर पर वसूल गए करोड़ों रुपये में से हर महीने लाखों रुपये के 'पैकेट' करजण तालुका BJP प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं। इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क ने लोकल वहीवटदार को हाथ पर हाथ धरे बैठा रखा है।

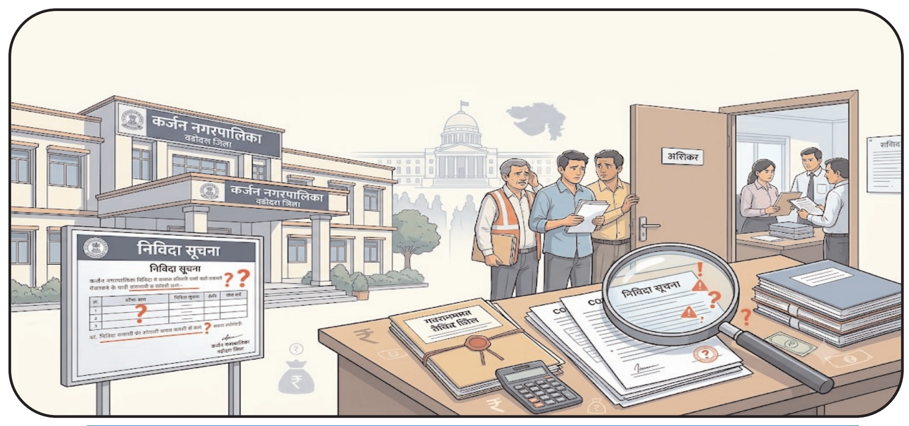

हाईकमान के लिए रेड लाइट: क्या पार्टी की इमेज खराब होगी?

गांधीनगर कमलम और दिल्ली में मौजूद BJP हाईकमान जहां करप्शन-फ्री गवर्नेंस की बात करते हैं, वहीं कर्जन म्युनिसिपैलिटी जैसी लोकल यूनिट्स में चल रहा यह 'टेंडर राज' पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और आम वोटर्स में भारी नाराजगी पैदा कर रहा है। अगर BJP हाईकमान और राज्य का विजिलेंस डिपार्टमेंट कर्जन म्युनिसिपैलिटी के सभी टेंडर्स, चीफ ऑफिसर की प्रॉपर्टीज़ और ऑर्गनाइजेशन के नेताओं की भूमिका की तुरंत निष्पक्ष जांच नहीं करता है, तो पार्टी को आने वाले लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इलेक्शन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महानगर मेट्रो न्यूज़ का अगला इश्यू देखें: किस कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट कमीशन लिया गया? सबूतों के साथ सनसनीखेज खुलासा...

E20 पेट्रोल का खेल: पुरानी गाड़ियों की 'मौत की घंटी' बज गई है, जनता की जेब पर सीधा हमला

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। देश में खाने-पीने की चीज़ों, दूध और दवाओं में मिलावट के मामले रोज़ की बात हो गए हैं, लेकिन अब सरकारी लेवल पर ही फ्यूल में कानूनी तौर पर इथेनॉल मिलाकर जनता को आर्थिक झटका देने का नया खेल शुरू हो गया है। अब तक आम आदमी को करीब 100 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला शुद्ध पेट्रोल 167 रुपये की हैरान करने वाली कीमत पर मिल रहा है। ज़्यादातर पेट्रोल पंपों से शुद्ध पेट्रोल गायब हो गया है और गाड़ी चलाने वालों को इथेनॉल मिला श्र20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और गाड़ी चलाने वालों की शिकायत है कि श्र20, श्र30 या श्र85 फ्यूल पुरानी गाड़ियों के इंजन, रबर पाइप और मेटल पार्ट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। इथेनॉल मिक्सचर ज़्यादा होने से इंजन में नमी जमा हो जाती है, जिससे फ्यूल सिस्टम में जंग और लीकेज की समस्या होती है। आसान शब्दों में कहें तो यह फ्यूल पुरानी गाड़ियों के लिए मौत की घंटी जैसा साबित हो रहा है। गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्च दोगुना हो रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन पेट्रोल से काफी सस्ता है। अगर फ्यूल में 20' सस्ता इथेनॉल मिलाया जाए, तो कंज्यूमर्स को पेट्रोल के दाम में राहत मिलनी चाहिए। इसके बजाय, शुद्ध फ्यूल 60 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। घटिया क्वालिटी और इंजन को नुकसान पहुंचाने वाला फ्यूल सप्लाई करके कंज्यूमर्स से पूरी कीमत वसूली जा रही है, जो जनता की जेब पर सीधा सरकारी तमाचा है। जहां आम नागरिक महंगाई से परेशान है, वहीं पॉलिसी फैसलों के नाम पर जनता पर पैसे का बोझ डाला जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर पर्यावरण और देश का पैसा बचाने की बात हो रही है।

पारुल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बगावत NSUI का करप्शन और ज़ुल्म के खिलाफ तीखा हमला

महानगर मेट्रो ब्यूरो

वडोदरा। मशहूर पारुल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के भंवर में घिर गई है। NSUI ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे कथित करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों और स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाने की अथॉरिटी की पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स के फायदे के लिए सड़क पर उतरे एक्टिविस्ट ने कलेक्टर ऑफिस पर जमकर हंगामा किया, जिससे कैंपस से लेकर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक भारी भीड़ लग गई। हस्तू नेताओं का सीधा आरोप है कि पारुल यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी एजुकेशन के नाम पर सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियां और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन चल रहा है। जब भी कोई स्टूडेंट या ऑर्गनाइजेशन अपने हक या सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दबाने वाली पॉलिसी अपनाकर उनकी आवाज़ दबा देता है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ हो रहे इस खुलेआम खिलवाड़ के खिलाफ अब स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी गुस्सा है।

पुलिस के साथ तीखी बहस और झड़प के सीन

आज कलेक्टर ऑफिस में प्रोटेस्ट करने पहुंचे हस्तू वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस ने भारी इंतज़ाम किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हस्तू वर्कर्स के बीच तीखी बहस और बहस के सीन बन गए। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ और एक्सटॉर्शन के खिलाफ नारे लगा रहे वर्कर्स ने ज़ोरदार नारे लगाए, जिससे पूरा कलेक्टर ऑफिस परिसर गूंज उठा। भारी पुलिस मौजूदगी और झड़प के बीच हस्तू डेलीगेशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पिटीशन दी।

किसी देश के लिए यह सबसे बड़ी शर्म की बात है कि गंदा और नकली खाना खाने से मौतें होती हैं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। भूख से जूझ रहा देश अब मिलावटी और बेकार खाने की वजह से मौत के कगार पर है! जिस देश में करोड़ों लोग आज भी दो वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं, वहां पेट भरने के लिए खाया गया खाना ही अगर किसी की जान लेने लगे तो इससे बड़ी अफ़सोस और शर्म की बात क्या हो सकती है? होटल और रेस्टोरेंट का बाहर का खाना हो या घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले, तेल या दूध... हर जगह नकली, गंदा और ज़हरीला सामान परोसा जा रहा है। खाने के नाम पर व्यापारी धीरे-धीरे जनता के पेट में ज़हर डालकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और ज़िम्मेदार प्रशासन आंखें मूंदकर तमाशा देख रहा है। बाज़ार में मिलने वाली लगभग हर खाने की चीज़ में मिलावट का भयानक खेल चल रहा है। दूध में यूरिया और डिटर्जेंट, मसालों में ज़हरीले रंग और ईंट पाउडर का इस्तेमाल होता है, जबकि सब्जियों को चमकाने के लिए केमिकल रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ, होटलों और बाहर स्ट्रीट फूड में ग्राहकों को सड़ी-गली सब्जियां, एक्सपायरी माल और बासी खाना परोसा जा रहा है। सफाई के नाम पर फफूंद लगी जगहों पर तैयार यह खाना सीधे अस्पतालों द्वारा वसूला जा रहा है। नागरिकों की सेहत की रक्षा के लिए बनाया गया 'फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट' त्योहारों के दौरान सैंपल लेने के नाटक तक ही सीमित रह गया है। कागज़ों पर बड़े रेड दिखाने और बाद में सेटिंग करने की पॉलिसी के कारण मिलावटखोर व्यापारियों को कोई डर नहीं है। सख्त कार्रवाई और उम्रकैद जैसी सज़ा के अभाव में लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर देश के नागरिकों को अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने के बाद भी शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है, तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। सिस्टम की इस आपराधिक लापरवाही और व्यापारियों के लालच ने देश को मौत के कगार पर पहुंचा दिया है। अब समय आ गया है कि नकली और खाने लायक नहीं सामान बेचने वालों पर हत्या का केस दर्ज करके जेल भेजा जाए, नहीं तो हर घर की थाली में रोटी नहीं, ज़हर परोसा जाता रहेगा।

भावनगर में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़: MP से बुलाई गई पूरी टीम

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भावनगर। एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने राज्य में शराबबंदी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां, एक लोकल बूटलेगर ने नकली शराब बनाने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, इस काले धंधे को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश से एक स्पेशल नकली शराब एक्सपर्ट टीम को भावनगर बुलाया गया था। पुलिस ने रेड करके इस स्कैम का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन भावनगर पुलिस की फिलहाल नींद उड़ी हुई है क्योंकि रेड के दौरान 170 नकली शराब की बोतलें गायब मिलीं। भावनगर के बूटलेगर ने विदेशी शराब की ज़्यादा डिमांड और कमाई के लालच में, बाहर से ब्रांडेड शराब इंपोर्ट करने के बजाय इसे लोकल लेवल पर बनाने का प्लान बनाया था। से आई टीम ने लोकल केमिकल, एसेंस और बॉटलिंग मटीरियल का इस्तेमाल करके बेबे हूबू ब्रांड की शराब जैसी नकली शराब बनाना शुरू कर दिया था। यह शराब सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक और ज़हरीली साबित हो सकती थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा और नकली शराब बनाने का सेटअप और सामान ज़ब्त कर लिया। लेकिन शुरुआती जांच का जायज़ा लेने पर पता चला कि तैयार की गई बोतलों में से लगभग 170 नकली शराब की बोतलें गायब थीं। पुलिस इस बात को लेकर बहुत सस्पेंस में है कि क्या शराब तस्कर ने इन बोतलों को मार्केट में बेच दिया है या कहीं और छिपा दिया है।

बॉस की फोटो देखकर अकाउंटेंट ने पेमेंट किए 3 करोड़ कॉन्फ्रेंस कॉल करते ही पैरों तले खिसक गई जमीन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। पास चांगोदर में 'प्योर एंड क्योर टेक्नोलॉजी' कंपनी में साइबर फ्रॉड हुआ है। ठग ने डायरेक्टर हेमंतभाई की फोटो के साथ एक फेक WhatsApp प्रोफाइल बनाई, अकाउंटेंट हार्दिकभाई को भरोसे में लिया और एक अनजान बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। 18 अगस्त को हुई इस घटना में, पेमेंट एक फेक ऑर्डर के ज़रिए किया गया था। कॉन्फ्रेंस कॉल पर असली डायरेक्टर के सामने आने पर फ्रॉड का खुलासा हुआ और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की गई। अहमदाबाद के पास चांगोदर में स्थित 'प्योर एंड क्योर टेक्नोलॉजी' नाम की कंपनी में साइबर फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शातिर ठग ने कंपनी के डायरेक्टर हेमंतभाई के नाम और उनकी फोटो के साथ एक फेक WhatsApp प्रोफाइल बनाई थी और कंपनी के अकाउंटेंट हार्दिकभाई पटेल से संपर्क किया था। ठग ने डायरेक्टर बनकर अकाउंटेंट को अपने भरोसे में लिया और एक अनजान बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। इस घटना के बारे में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। बैंक बैलेंस पूछकर 3 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया अहमदाबाद के गोटा इलाके के रहने वाले और पिछले 20 सालों से चांगोदर में इस कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे 44 साल के हार्दिकभाई पटेल 18 अगस्त की सुबह ऑफिस में काम कर रहे थे। उस समय उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज आया। जिसमें प्रोफाइल में डायरेक्टर हेमंत सर की फोटो थी। ठग ने जब कंपनी के बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछा तो अकाउंटेंट ने 13 करोड़ रुपये प्लस CC 6 करोड़ रुपये बताया। इसके बाद ठग ने 'एग्रोवेला प्राइवेट लिमिटेड' के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजकर तुरंत 3,00,00,000 रुपये देने का ऑर्डर दिया। यह मानकर कि यह डायरेक्टर का ऑर्डर है, हार्दिकभाई ने पेमेंट प्रोसेस किया, कंपनी के दूसरे पार्टनर नयनभाई से फोन पर अप्रूवल लिया और अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। सुबह 11.46 बजे बैंक से एक मेल आया जिसमें बताया गया कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। हालांकि, सुबह 11.47 बजे नयनभाई और असली डायरेक्टर हेमंतभाई के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान पता चला कि हेमंतभाई ने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। जैसे ही अकाउंटेंट को पता चला कि उसके साथ 3 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, उसने तुरंत साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कराई।

नवा वडाज में देर रात मवेशी पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान PSI और CNCD टीम के साथ युवकों ने की बदतमीज़ी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गुजरात। हाई कोर्ट द्वारा आवारा मवेशियों को लेकर सख्ती से लागू करने की आलोचना के बाद, राज्य में आवारा मवेशी पॉलिसी लागू की गई है। हालांकि पॉलिसी लागू होने के बाद अहमदाबाद शहर में सख्ती देखी गई, लेकिन पिछले एक महीने से एक बार फिर सड़कों पर मवेशी घूमते देखे गए हैं। शहर के नवा वडाज इलाके में मवेशी पकड़ने गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मवेशी डिपार्टमेंट की टीम पर हमला करने और PSI को डंडे से पीटने की कोशिश की घटना हुई है। PSI ने डंडे को रोक लिया और वे बच गए। पूरे मामले में वडाज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। अहमदाबाद शहर में कॉर्पोरेशन ने मवेशियों को सड़क पर न घूमने देने की पॉलिसी लागू की है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के CNCD डिपार्टमेंट के काम न करने की वजह से अब एक बार फिर मवेशी सड़क पर दिख रहे हैं। मवेशी मालिकों की बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि अब वे पुलिसवालों पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उन्हें कानून का कोई डर ही न हो। नवा वडज इलाके में एक घटना हुई है। वेस्टर्न ज़ोन के छन्नछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर, कर्मचारी और PSI मवेशी पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग पर निकले थे। नवा वडज में आकाशदीप अपार्टमेंट के पास पेट्रोलिंग के दौरान गायें घूमती दिखीं, इसलिए जब गायों को ट्रेलर में लोड करना का काम शुरू हुआ, तो पारस भरवाड़ और पिंटू भरवाड़ नाम के दो लोग वहां आए। उन्होंने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हें ट्रेलर में मवेशी लोड नहीं करने देंगे। उन्होंने ट्रेलर में गायों को चारा नहीं दिया और गायों पर हमला कर रहे थे, इसलिए जब वहां मौजूद PSI एस.एम. शेख ने गायों पर हमला करने से मना किया, तो युवकों ने PSI पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। तो PSI ने डंडा सीधा कर दिया और वह बच गए। आगे बहस होने पर पुलिस ने कंट्रोल रूम में फोन किया और मौके पर पहुंची। लेकिन, बहस जारी रहने पर दोनों युवकों ने कहा कि आज तो बच गए, अब यहां गायों को चारा खिलाने नहीं आ रहे हो और भाग गए। उन्होंने धमकी दी कि मवेशी यहीं रहेंगे और अगर अब आए तो तुम्हें नहीं बचाएंगे और छोड़ देंगे। CNCD डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने पिंटू भरवाड़ और पारस भरवाड़ नाम के दोनों लोगों के खिलाफ वडाज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और वडाज पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि अहमदाबाद शहर में एक बार फिर सड़कों पर आवारा मवेशी देखे जा रहे हैं। खासकर शाम और रात के समय मवेशी मालिक उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ रहे हैं, जिससे एक बार फिर सड़कों पर मवेशियों की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना है। गुजरात हाई कोर्ट के आवारा मवेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के बाद एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत काम भी हुआ है, हालांकि, अब एक बार फिर कॉर्पोरेशन के छन्नछ डिपार्टमेंट की निष्क्रियता के कारण सड़कों पर मवेशी देखे जा रहे हैं।

IKDRC में खुला घोटाले का खेल

बिना ई-टेंडर के भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दिए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

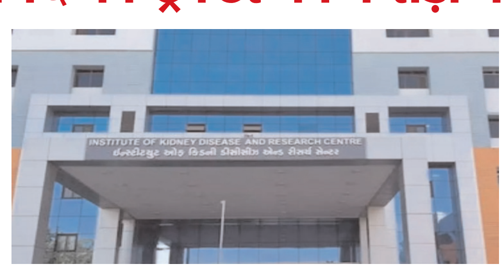

अहमदाबाद। का इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर इस समय गंभीर फाइनेंशियल गड़बड़ियों और घोटालों की वजह से विवादों के भंवर में फंसा हुआ है। CAG की साल 2023 से 2025 तक की चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ने सरकारी नियमों और ट्रांसपेरेंट ई-टेंडरिंग प्रोसेस को नज़रअंदाज़ करते हुए अपनी भरोसेमंद एजेंसियों को करोड़ों रुपये के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन डॉ. पार्थिवराजसिंह कथवाडिया ने राजीव गांधी भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि हॉस्पिटल में तलवार जैसी लय बन गई है, जहां पब्लिक के टैक्स के पैसे का खुलेआम गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ा खेल इन-हाउस लॉन्ड्री सर्विस में देखने को मिला है। अस्पताल में 11.43 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से नई लॉन्ड्री और किचन बनाया गया था। लेकिन, इस महंगे सेटअप का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। नई बिल्डिंग में तैयार मॉडर्न लॉन्ड्री धूल फांक रही है, जबकि पुरानी बिल्डिंग में चल रहा सिस्टम बंद कर दिया गया है और पूरी सर्विस आउटसोर्स कर दी गई है। इस आउटसोर्सिंग के लिए लीगल टेंडर प्रक्रिया करने के बजाय सिर्फ कोटेशन मंगाकर 36 लाख रुपये सालाना (3 लाख रुपये महीने) का ठेका दे दिया गया। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल जगह, पानी, बिजली और मशीनरी जैसी सारी चीजें खुद देता है और प्राइवेट ठेकेदार सिर्फ कपड़े धोने के नाम पर लाखों रुपये वसूल रहा है। दूसरी ओर, डायलिसिस प्रोग्राम के तहत महंगे आरओ (आरओ) सिस्टम की खरीद और रखरखाव में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। आरओ के काम के लिए ई-टेंडरिंग ज़रूरी थी। 1.19 करोड़ रुपये का मटीरियल और 14.76 लाख रुपये की सर्विस। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ तीन कोटेशन मंगाकर यह ठेका मेसर्स क्लियर आयन एक्सचेंज इंजीनियर्स को दे दिया गया और बाद में इसे अवैध तरीके से एक्सटेंशन भी दे दिया गया। एयर कंडीशनिंग (एसी) मेंटेनेंस में अनियमितताओं की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पिछले 17 सालों से एक ही भरोसेमंद कंपनी 'ईशा कूलिंग सिस्टम' को ई-मेल के ज़रिए कोटेशन मंगाकर 1.07 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। अस्पताल की कुल 416 एसी यूनिट की साधारण और केमिकल सर्विस का सालाना खर्च अधिकतम 20.80 लाख रुपये है। फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत पर सालाना 86.20 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं? इतनी रकम से हर साल 172 नए एसी खरीदे जा सकते हैं। और तो और, टेंडर में न्यूनतम अवधि 3 साल होने के बावजूद वर्क ऑर्डर में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। ये सभी तथ्य बताते हैं कि नियमों का उल्लंघन कर आईकेडीआरसी में करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। अब जनता और विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ढ्ढरूछ्रछ्व में ये लॉन्ड्री वर्कर, ऋ. वर्कर और.ष्ट वर्कर कौन हैं जिन पर मेहरबानी बरसाई जा रही है?

वटामा चौकड़ी पर गाड़ी चेकिंग के दौरान 5.78 लाख रुपये का सामान ज़ब्त किया गया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। कोठ पुलिस ने अहमदाबाद ज़िले के धोलका में वटामा चौकड़ी पर गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी शराब ज़ब्त की है। पुलिस ने कुल 3,000 विदेशी बीयर टिन और 5.78 लाख रुपये की एक पिकअप बोलेरो ज़ब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर, ळ्रछ्न84-7890 नंबर की एक पिकअप बोलेरो गाड़ी को शक के आधार पर रोका गया।

गाड़ी की अच्छी तरह से जांच करने पर उसमें अलग-अलग ब्रांड के 3,000 विदेशी बीयर टिन मिले। कोठ पुलिस ने इतनी शराब के साथ बिरसाग गुनराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कुल 5,78,340 रुपये की शराब, पिकअप बोलेरो और दूसरा सामान ज़ब्त किया गया है। शराब की मात्रा भेजने वाले दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोठ पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब की तस्करी में शामिल लोगों पर काबू पाया जा सकेगा। पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है।

'मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है

महानगर मेट्रो ब्यूरो

विवादित केपी स्वामी विवाद में हर दिन नए और चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं। अब, जैसे ही इस पूरे मामले में एक डॉक्टर का डरावना मैसेज 'मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है!' सामने आया, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। शुरुआत में रंगदारी की कहानी बनाकर मामले को घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं और रहस्यमयी चैट ने स्वामी और प्रशासन की पोल खोल दी है। केपी स्वामी ने दावा किया कि डॉक्टर कपल उनसे 5 करोड़ रुपये की भारी रकम मांग रहा था और पहले ही 2 लाख रुपये वसूल चुका था। लेकिन, यह कहानी पुलिस और आम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित डॉक्टर कपल बहुत खुशहाल, अमीर और इज्जतदार परिवार से है। जिस परिवार को कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, वह अचानक स्वामी से 2 लाख या 5 करोड़ रुपये की फिरौती क्यों मांग रहा है? ये अलग-अलग कहानियां सिर्फ यही दिखाती हैं कि असली जुर्म को छिपाने के लिए वसूली का ड्रामा रचा गया है।

महानगर मेट्रो
www.mahanagarmetro.com

DCP नकुम का बचाव करने वाले BJP नेता के खिलाफ वकील खड़े

महानगर मेट्रो ब्यूरो

देवगढ़बरिया। लोकल नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा तुरंत और पक्के समाधान की मांग लोकल नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही और लापरवाही के कारण देवगढ़बरिया शहर में सफाई अभियान के झंडे खुलेआम लहरा रहे हैं। स्मार्ट सिटी और सफाई के बड़े-बड़े दावों के बीच हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। शहर के बहुत व्यस्त और महत्वपूर्ण स्वागत हाई स्कूल के बाहर मेन रोड पर सीवेज का पानी ओवरफ्लो होने से पूरी सड़क बदबूदार गंदगी का साम्राज्य बन गई है। प्रशासन की इस सुस्त नीति से स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और वाहन चालकों में बहुत गुस्सा है। सीवर और टॉयलेट का गंदा और गंदा पानी मेन रोड पर लगातार नदी की तरह बह रहा है, जिससे पूरा इलाका मच्छरों और बैक्टीरिया का घर बन गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी रोड से हर दिन सैकड़ों स्टूडेंट स्वागत हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। मासूम बच्चे, जो भविष्य के नागरिक हैं, उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए इस असहनीय बदबू और गंदे पानी से होकर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्टूडेंट और पैदल चलने वालों को मुंह पर रूमाल या कपड़ा बांधकर निकलना पड़ रहा है। अगर स्कूल, जिसे शिक्षा का पवित्र स्थान माना जाता है, के बाहर ऐसी भयानक गंदगी है, तो कोई भी सोच सकता है कि आम इलाकों की क्या हालत होगी। सड़क पर बहते इस गंदे पानी की वजह से गाड़ियों के फिसलने और एक्सीडेंट होने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसके साथ ही, मानसून जैसे हालात बनने से आसपास के इलाके के लोगों में भयानक महामारी फैलने का डर पैदा हो गया है। लोगों की मांग है कि डायरिया, उल्टी, डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने से पहले प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे। आंगनवाड़ी और स्कूल के पास बह रहे इस गंदे पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने कई बार नगर पालिका से गुहार लगाई है। लेकिन, सोई हुई नगर पालिका प्रशासन के कानों तक लोगों की आवाज नहीं पहुंचती। प्रशासनिक सिस्टम की इस निष्क्रियता को देखकर लोग अब उग्र आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं।

फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर और महिला ड्रग इंस्पेक्टर 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भरूच। एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भरूच शहर में एक बड़ी और सफल कार्रवाई कर सरकारी अधिकारियों में भारी खलबली मचा दी है। भरूच फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर और ड्रग्स इंस्पेक्टर को पैसों की भूख भुलाकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में ACB की इस कार्रवाई से रिश्वतखोर अधिकारियों में खलबली मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, एक जागरूक नागरिक ने दवा की होलसेल बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था। इस लाइसेंस को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर

प्रकाशभाई पोसना और ड्रग्स इंस्पेक्टर सुरभिबेन देसाई ने 50,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी। शिकायत करने वाला रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने नर्मदा ACB से संपर्क किया और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, नर्मदा ACB PI डी.डी. वसावा और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की और एक मज़बूत जाल बिछाया। हंगामे के बाद, 40,000 रुपये की रकम तय की गई। ACB टीम द्वारा बिछाए गए जाल के दौरान, प्रकाशभाई पोसना और सुरभिबेन देसाई ने 40,000 रुपये की रिश्वत ली.

अहमदाबाद के सरखेज इलाके में टायर गोदाम में भीषण आग: आसमान में धुआं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। टायरों में आग लगने की वजह से कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं और काले धुएं का गुबार मीलों तक आसमान में फैल गया। घटना की खबर मिलते ही अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस टीम तुरंत हरकत में आ गई। फायरफाइटर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और वॉटर कैनन और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। टायर और रबर की बड़ी मात्रा होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है, इसलिए फायर ब्रिगेड को बड़ी कॉल की गई है और और गाड़ियां बुलाई गई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में अब तक किसी के नुकसान या घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा के तौर पर, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है और पास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी और वजह से, असली वजह फायर ब्रिगेड का काम पूरा होने और FSL जांच के बाद ही साफ होगी। फिलहाल फायर डिपार्टमेंट का पहला मकसद आग को आस-पास के दूसरे गोदामों या घरों में फैलने से रोकना है।

नकली दूध और खाने की चीज़ों में मिलावट के बारे में गुजरात सरकार और फ़ूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गुजरात। नकली या मिलावटी दूध और खाने की चीज़ों के प्रोडक्शन और बिक्री के खिलाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन समय-समय पर कड़ी चेकिंग और कानूनी कार्रवाई करता है। राज्य में फ़ूड सेफ्टी बनाए रखने और लोगों की हेल्थ की सुरक्षा के लिए, फ़ूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे राज्य में रेड, सैंपल टेस्टिंग और कानूनी दखल देता है। क्रिमिनल कार्रवाई और जांच: मिलावटी या केमिकल दूध बनाने वालों के खिलाफ़ इंडियन पीनल कोड और फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एक्ट) के तहत FIR दर्ज की जाती हैं और इसमें शामिल संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है। सैंपलिंग: FDCA टीम रेगुलर तौर पर राज्य भर में डेयरियों, चिलिंग सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट टैंकरों से दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स (घी, पनीर, बटर, चीज़) के सैंपल लेती है और उन्हें एनालिसिस के लिए सरकारी लैब में भेजती है। लैब टेस्टिंग: सैंपल की क्वालिटी वडोदरा और दूसरी सरकारी एनालिटिकल लैब में चेक की जाती है। अगर सैंपल 'अनसेफ' या 'सब-स्टैंडर्ड' पाए जाते हैं, तो संबंधित यूनिट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। छापे और ज़ब्ती: जब अशुद्ध या नुकसानदायक केमिकल वाली मात्रा पाई जाती है, तो सिस्टम मौके पर ही सामान को ज़ब्त करके नष्ट कर देता है।

नागरिकों के लिए शिकायत और संपर्क सुविधा

अगर किसी नागरिक के पास मिलावटी दूध, दूध के प्रोडक्ट या दूसरी मिलावटी खाने की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी या शिकायत है, तो वे सीधे फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क लोकल डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर से संपर्क करके शिकायत दर्ज की जा सकती है।

साबरमती में बंद घर में चल रहे शराब के काले धंधे पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक

झलड्डा कांड के बाद अहमदाबाद पुलिस एक्शन मोड में

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भावनगर। कथित लट्ठा कांड की गंभीर घटना अब अहमदाबाद शहर समेत पूरे राज्य में असर डाल रही है। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस चीफ ने शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं। यह आदेश जारी होते ही अहमदाबाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और शहर के असामाजिक तत्वों और शराब नेटवर्क पर हमला करके चौंकाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक की है।पुलिस के इस सख्त ऑपरेशन के दौरान साबरमती इलाके से शराब का एक बड़ा काला धंधा पकड़ा गया है। एक शातिर शराब तस्कर साबरमती में एक बंद घर से चुपके से शराब का धंधा चला रहा था।खास जानकारी के आधार पर पुलिस ने बंद घर पर छापा मारा और इतनी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की

शराब की मात्रा: Rs. 3 लाख रुपये की बड़ी मात्रा में 'रॉयल स्टैग' विदेशी शराब जब्त की गई। शराब तस्कर गिरफ्तार: बंद बिल्डिंग का गैर-कानूनी इस्तेमाल करके नेटवर्क चलाने वाले मुख्य शराब तस्कर को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

जांच जोरों पर: पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से आई, किसकी मदद से सप्लाई की जा रही थी और

शहर में इसे कहां पहुंचाया जाना था। ाकी वर्दी के

इस आक्रामक रूप और सख्त कार्रवाई से शहर के शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों में काफी हलचल और सन्नाटा है। अहमदाबाद पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि गैर-कानूनी कामों में लगे लोगों के खिलाफ यह अभियान आने वाले दिनों में और सख्त होगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

भावनगर ज़हर कांड के बाद जागा पुलिस सिस्टम: रंगदारी और लाशों के ढेर के बीच यह खूनी खेल कब रुकेगा?

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भावनगर। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की 'गांधी के विचार' और गुजरात में 'कानून का राज' की बातें सिर्फ़ किताबों में हैं। भावनगर में ज़हरीली नकली शराब पीने से कई बेगुनाह लोगों की भयानक मौतों के बाद, होम डिपार्टमेंट और पुलिस सिस्टम, जो आखिरकार सो रहा था, एक्शन मोड में आ गया है। राज्य के DGP जी.एस. मलिक ने पूरे गुजरात में देसी और विदेशी शराब के डिपो और स्टोरेज की जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने के लिए पूरे राज्य में एक स्पेशल पुलिस ड्राइव चलाने का आदेश दिया है। लेकिन, जनता अब पूछ रही है कि पुलिस हर बार बेगुनाहों की जान जाने, घरों में चिताएं जलने और सिंदूर जलाए जाने पर ही क्यों जागती है, क्या गुजरात में कानून लाशों के ढेर मिलने के बाद ही एक्शन में आएगा?

खाकी लाशों के ढेर के बाद ही क्यों जागती है? ड्रामैटिक 'ड्राइव' का खुलासा

जब भी गुजरात में कोई बड़ी घटना या नकली शराब कांड होता है, तो पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक तुरंत 'राज्यव्यापी ड्राइव' शुरू कर दी जाती है। लेकिन यह मुहिम लोगों का गुस्सा शांत करने, मीडिया में हेडलाइन बनाने और वाहवाही बटोरने के लिए एक नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने के बाद ही कोई एक्शन लेता है: अनगिनत लोग अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और अस्पताल मरीजों की चीखों से भर जाते हैं, तभी बड़े अधिकारी अपने‹ष्ट ऑफिस से बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 'सख्त एक्शन' के बड़े-बड़े दावे करते हैं। किश्तों के राज और सेटिंग का काला खेल: लोकल बीट जमादार से लेकर जिले के बड़े अधिकारियों तक, सबको पता है कि गुजरात के कोने-कोने में कहां-कहां शराब के अड्डे चल रहे हैं, किन गोदामों में केमिकल से नकली शराब बनाई जाती है और किस रास्ते से ड्रग्स अंदर आते हैं। फिर भी, हर महीने करोड़ों रुपये के खाकी और खादी कवर (किश्तों) देश भर में पहुंचते हैं, यह ज़हरीला धंधा पुलिस की छत्रछाया में बेरोकटोक फल-फूल रहा है। छोटे शराब तस्करों की गिरफ्तारी, सरगना सुरक्षित: एक्शन के नाम पर पुलिस सिर्फ छोटे-बड़े ढीले-ढाले लिंक या मजदूरों को गिरफ्तार करके आंकड़ों का भ्रम पैदा करती है। जबकि इस काले धंधे के मुख्य भड़काने वाले, केमिकल सप्लायर और ड्रग माफिया पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन में मौज-मस्ती करते रहते हैं।जो शराब मेथनॉल, केमिकल और ज़हर मिलाकर लोगों के घरों में परोसी जाती है, वह कोई हादसा नहीं बल्कि सीधा कत्लेआम है। सिर्फ़ शराब बेचने वाले ही नहीं, बल्कि किश्तों में पैसे लेकर इन जगहों को बढ़ावा देने वाले पुलिस अफ़सर और पॉलिटिकल बॉस भी इस ज़हरीले धंधे के लिए बराबर के ज़िम्मेदार हैं। जब तक रिश्वत लेने वाले पुलिस अफ़सरों के ख़िलाफ़ 'क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी' (सेक्शन 120B) के तहत केस दर्ज नहीं होता और उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, तब तक यह खूनी खेल कभी नहीं रुकेगा। गुजरात के लोगों का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुँच गया है। लोग ज़ोरदार मांग कर रहे हैं कि दूध पीते मासूम बच्चों को अनाथ बनाने वाले और पैसे के लालच में ज़हर बेचने वाले शराब तस्करों को सिर्फ़ जेल भेजने के बजाय फांसी दी जानी चाहिए। अगर राज्य सरकार और होम डिपार्टमेंट सच में गुजरात से ड्रग्स की बुराई को खत्म करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मल ड्राइव ड्रामे बंद करने होंगे। कागजों पर जो रोक है, उसे हकीकत में बदलना होगा। हड़पने वाले अफसरों पर बुलडोजर चलाना होगा और शराब के नाम पर पैसे ऐंठने वाले पुलिस सिस्टम पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर इंस्टॉलमेंट राज नहीं रुका, तो ऐसी ड्राइव सिर्फ धूल बनकर रह जाएंगी और बेगुनाह लोग कुर्बान होते रहेंगे।

पालिताना सरकारी अस्पताल में टैंक नहीं, फिर भी 50.43 लाख का बिल 2 इंजीनियर सस्पेंड, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होगा; घटना 13 दिन पहले मंत्री प्रफुल पंसेरिया के दौरे के दौरान हुई थी

गांधीनगर। भावनगर के पालिताना सरकारी अस्पताल में 2.55 लाख लीटर कैपेसिटी वाले अंडरग्राउंड पानी के टैंक के लिए ?50.43 लाख का बिल अप्रूवल के लिए जमा किया गया था, जबकि उस पर साइट पर काम भी नहीं हुआ था। हेल्थ मिनिस्टर प्रफुल पंसेरिया ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जिम्मेदार अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। जिसमें दो इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब हेल्थ मिनिस्टर 13 दिन पहले पालिताना सरकारी अस्पताल गए थे, तो अस्पताल के लिए अप्रूव किया गया अंडरग्राउंड पानी का टैंक साइट पर नहीं दिखा था। जांच में पता चला कि लाखों का बिल हेड ऑफिस में अप्रूवल के लिए जमा किया गया था, जबकि टैंक पर काम भी नहीं हुआ था मामले का संज्ञान लेते ही, मंत्री ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस की और पालिताना हॉस्पिटल और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के संबंधित

अधिकारियों से पूरे प्रोसेस की जानकारी ली। बिल जमा करने के प्रोसेस में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। बिल जमा करने वाले इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेहुल दवे और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एन.वी. कालिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जारी की गई है। इसके साथ ही, ड्यूटी में लापरवाही के लिए दोनों के खिलाफ सस्पेंशन/बर्खास्तगी की कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में शामिल सूरत की धर्मनंदन कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी की गई है। संबंधित अधिकारियों को कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है।ेल्थ मिनिस्टर प्रफुल्ल पंसेरिया ने साफ संदेश दिया है कि राज्य की हेल्थ सर्विसेज के लिए दिए गए पब्लिक मनी के इस्तेमाल में कोई लापरवाही, गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी हेल्थ डेवलपमेंट के कामों में क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना सरकार की प्रायोरिटी है। हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात पर सख्ती से नज़र रखेगा कि अप्रूव्ड काम असल में साइट पर पूरे हों और क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखे जाएं। फिलहाल, इस मामले में ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट, सस्पेंशन/डिसमिसल और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में सख्ती: शहर की 20 प्रॉपर्टी सील की गईं और डिफॉल्टर्स से 40 लाख वसूले गए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गांधीनगर। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल का बकाया टैक्स तय समय में न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ सीलिंग और अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सख्त अभियान के तहत, अब तक कुल 20 प्रॉपर्टी सील की गई हैं और सख्त रवैया अपनाकर 40 लाख का बकाया टैक्स वसूला गया है।

डिफॉल्टर्स के खिलाफ साफ एक्शन लेने की धमकी

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल का बकाया टैक्स देने वाले प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू किया है। आने वाले दिनों में इस बड़े अभियान को और तेज करने और दूसरे डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की

साफ धमकी दी गई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में, म्युनिसिपैलिटी को टैक्सपेयर्स से बहुत अच्छा सहयोग मिला है।अब तक कुल 1,15,288 लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी की है और 55.15 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है। इस साल कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ लोगों का झुकाव काफी देखा गया है। कुल कलेक्शन का 56.75 परसेंट यानी 31.30 करोड़ रुपये 75,191 टैक्सपेयर्स ने UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल तरीकों से जमा किया है। बकि 40,097 लोगों ने ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कैश या चेक से 23.85 करोड़ रुपये टैक्स जमा किया है, जो कुल रकम का 43.25 परसेंट है। नगर निगम ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स जमा करने की डेडलाइन सितंबर के आखिर तक दी है। इस डेडलाइन के बाद जारी किए गए बिल को फाइनल नोटिस माना जाएगा और बिना किसी पहले से नोटिस के प्रॉपर्टी सील करने का काम किया जाएगा। इंडिया पोस्ट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन पक्का किया गया है ताकि लोगों को बिल उनके घर पर मिल जाए। अगर किसी वजह से बिल नहीं मिलता है, तो लोग गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की सीलिंग, अटैचमेंट या प्रॉपर्टी ऑक्शन जैसे सख्त कदमों से बचने के लिए समय पर टैक्स भरने की अपील की गई है।

ST15 दिन के किराए में 30 दिन का सफर कराएगा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गांधीनगर। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हर दिन अप-डाउन करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 'डेली पैसेंजर पास स्कीम' में किराए में राहत बढ़ाकर यात्रियों को 50 परसेंट तक की सीधी बचत का फायदा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक, पहले मंथली पास के लिए यात्रियों से 18 दिन का किराया लिया जाता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 15 दिन का किराया कर दिया गया है। यानी यात्री सिर्फ 15 दिन का किराया देकर लगातार 30 दिन सफर कर सकेंगे। यात्रियों को क्वार्टरली पास में भी सीधा फायदा मिलेगा। पहले 90 दिन के पास के लिए 54 दिन का किराया देना पड़ता था। अब आप सिर्फ़ 45 दिन का किराया देकर 90 दिन तक यात्रा कर सकते हैं। तस्त्रक्ष्रष्ट के इस फ़ैसले से राज्य में रोज़ाना आने-जाने वाले 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों, व्यापारियों और छोटे-बड़े बिज़नेसमैन को सीधा फ़ायदा होगा। खासकर, रोज़ाना स्त्र बस में काम या बिज़नेस के लिए आने-जाने वाले यात्रियों का महीने का यात्रा खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। कॉर्पोरेशन के इस फ़ैसले से यात्रियों को पैसे की राहत मिलेगी और ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसे तस्त्रक्ष्रष्ट की तरफ़ से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और अच्छी बस सर्विस के साथ ज़्यादा फ़ायदे देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

गुजरात में कागजों पर शराबबंदी के बीच ड्रग्स का बढ़ता काला कारोबार

महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की पवित्र धरती गुजरात में दशकों से शराब और ड्रग्स पर रोक के कानून लागू हैं। राज्य सरकार की तरफ से अक्सर कानून को सख्ती से लागू करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की समुद्री सीमाओं और सड़क मार्गों से करोड़ों रुपये के ड्रग्स की लगातार तस्करी हो रही है। नतीजतन, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि गुजरात अब ड्रग माफियाओं के लिए सेफ लैंडिंग जोन बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 3 सालों में गुजरात से 65,549 द्मद्द ड्रग्स, 45,564 नशीली गोलियां और 4,841 लीटर लिक्विड ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, पिछले 2 सालों में 121 द्मद्द हाई-क्वालिटी कोकीन भी जब्त की गई है। ये चौंकाने वाले आंकड़े साफ दिखाते हैं कि राज्य में नशे का यह काला कारोबार किस भयानक लेवल तक पहुंच गया है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त होने के बावजूद, अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठे हैं। पिछले 3 सालों में पुलिस की किताबों में नशे से जुड़े कुल 1649 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, हजारों किलो ड्रग्स और करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त होने के बाद भी, कोर्ट में कुछ ही आरोपियों को दोषी पाया गया है। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को बड़ी मात्रा में जब्त करने पर तारीफ मिलती है, लेकिन जब कोर्ट में सख्त सजा दिलाने की बात आती है, तो कानूनी कार्रवाई कमजोर नजर आती है। सही सबूतों की कमी और कानूनी कमियों का फायदा उठाकर नशे के नेटवर्क के मुख्य सरगना खुलेआम घूमते हैं, सरकारी सिस्टम और जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जिलाध्यक्ष उमा चौबे ने दी बधाई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने नरोदा पुलिस स्टेशन के PI सी. वी. नायक का डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है। डिटेंशन सेंटर में काम कर रहे बी.एम. कटारिया को नरोदा पुलिस स्टेशन का PI बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने एक ही ऑर्डर में PI का ट्रांसफर किया है, जिसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताए गए हैं। हालांकि, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नरोदा पुलिस स्टेशन एरिया में स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने त्नढ्ढष्ट एरिया में विदेशी शराब काटते हुए पकड़ा। लोकल नरोदा पुलिस सोती हुई पकड़ी गई, इसलिए पुलिस कमिश्नर के अगले ही दिन ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। पिछले 15 दिनों से, स्टेट पुलिस चीफ जी.एस. मलिक की डायरेक्ट सुपरविजन में स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम अहमदाबाद शहर में शराब, जुआ और स्पा पर रेड कर रही है। जी.एस. मलिक पहले अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें अहमदाबाद में चल रही शराब और जुए की गतिविधियों के बारे में अच्छी जानकारी है, इसलिए अब जब वे पुलिस चीफ बन गए हैं, तो स्टेट मॉनिटरिंग सेल को अहमदाबाद में रेड करने के लिए बहुत एक्टिव कर दिया गया है।

20 अगस्त 2026 | आज का राशिफल

12 राशियां • दैनिक भविष्यफल

♈ मेष — आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

♉ वृषभ — नौकरी और कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी। पुराने काम में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

♊ मिथुन — नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा।

♋ कर्क — रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। भावनाओं में आकर बड़ा फैसला लेने से बचें।

♌ सिंह — कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

♍ कन्या — मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या बदलाव का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं।

♎ तुला — व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

♏ वृश्चिक — कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को आप समझदारी से संभाल लेंगे। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें।

♐ धनु — भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

♑ मकर — नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।

♒ कुंभ — नए अवसर सामने आएंगे और रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा होगी। अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

♓ मीन — मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में लाभ और नौकरी में स्थिरता के योग हैं।

आज का विशेष संदेश

"सकारात्मक सोच और सही निर्णय आज आपकी सफलता की राह आसान करेंगे।"

दैनिक राशिफल • 20 अगस्त 2026

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों भा गया भारतीय निर्वाचन आयोग?

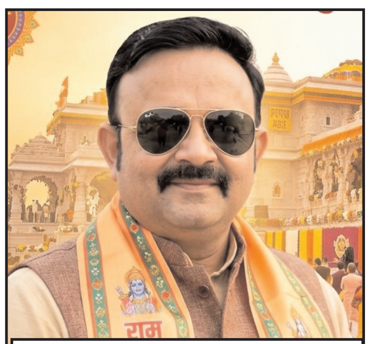

पवन माकन
ग्रुप एडिटर, महानगर मेट्रो

भारत में चुनाव कराना अपने आप में दुनिया का एक असाधारण प्रशासनिक अभियान है। करोड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना तथा परिणामों को घोषित करना–यह पूरा तंत्र विशाल स्तर पर काम करता है। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में लगभग 646 मिलियन मतदाताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय फोटो पहचान व्यवस्था को अमेरिका के संदर्भ में उपयोगी बताया। यहीं से भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ टैरिफ पर टैरिफ खेल रहे थे अचानक युद्व छोड़कर भारत की चुनाव व्यवस्था और मतदाता पहचान प्रणाली यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को पंसद कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था की तुलना भारतीय चुनाव मतदाता पहचान प्रणाली से की है। ट्रंप ने भारत के विशाल चुनावी तंत्र, फोटो पहचान-पत्र की व्यवस्था और सीमित डाक मतपत्र व्यवस्था को अमेरिका के लिए उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कथित बातचीत का भी उल्लेख किया, हालांकि इस बातचीत का स्वतंत्र सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान केवल भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा भर नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी राजनीति, मतदाता पहचान, चुनावी पारदर्शिता और आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों की राजनीति भी दिखाई देती है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत की चुनाव व्यवस्था में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति को आकर्षित कर रहा है? भारत का निर्वाचन आयोग कोई सामान्य प्रशासनिक संस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व प्राप्त है। निर्वाचन आयोग स्वयं भी इसे स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित करता है।

भारत में चुनाव कराना अपने आप में दुनिया का एक असाधारण प्रशासनिक अभियान है। करोड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना तथा परिणामों को घोषित करना–यह पूरा तंत्र विशाल स्तर पर काम करता है। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में लगभग 646 मिलियन मतदाताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय फोटो पहचान व्यवस्था को अमेरिका के संदर्भ में उपयोगी बताया। यहीं से भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। अमेरिका में चुनावों का संचालन काफी हद तक राज्यों के स्तर पर होता है और नियमों में राज्यवार अंतर दिखाई देता है। इसके विपरीत भारत में निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए व्यापक अधिकार रखता है। ट्रंप की नजर में यही केंद्रीकृत चुनाव प्रबंधन एक आकर्षक मॉडल हो सकता है। ट्रंप की टिप्पणी को समझने के लिए अमेरिकी राजनीति को समझना आवश्यक है। अमेरिका में मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। ट्रंप लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में पहचान और नागरिकता की पर्याप्त जांच होनी चाहिए।इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उनका उद्देश्य केवल भारत की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि अमेरिकी मतदाता पहचान कानूनों के पक्ष में राजनीतिक समर्थन जुटाना भी है। ट्रंप प्रशासन के माध्यम से मतदाता पंजीकरण में नागरिकता प्रमाण और देशव्यापी फोटो पहचान जैसे प्रावधानों पर जोर दे रहा है।इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि ट्रंप को भारत इसलिए भा रहा है क्योंकि भारतीय चुनाव प्रणाली का एक हिस्सा उनके घरेलू राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल दिखाई देता है।यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है–क्या ट्रंप वास्तव में भारतीय चुनाव प्रणाली को अमेरिकी चुनाव व्यवस्था का आदर्श मानते हैं या वे भारत का उदाहरण अपनी घरेलू राजनीति में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं?

भारत की चुनाव व्यवस्था की अपनी खूबियां हैं। लेकिन भारत भी पूर्ण व्यवस्था होने का दावा नहीं कर सकता। मतदाता सूची में नाम जुड? या हटने, पहचान संबंधी समस्याओं, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर समय-समय पर राजनीतिक विवाद उठते रहे हैं। हाल के वर्षों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी तीखी राजनीतिक बहस हुई है। 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष और नागरिक समूहों ने सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के भीतर काम करने का पक्ष रखा है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में भी निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने की शक्तियों को लेकर प्रश्नों पर विचार हुआ है।इसलिए ट्रंप की प्रशंसा को भारत की चुनाव प्रणाली के लिए अंतिम प्रमाणपत्र मान लेना उचित नहीं होगा।किसी भी चुनाव की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने मतदान किया। असली सफलता तब होती है जब हारने वाला उम्मीदवार और उसके समर्थक भी परिणाम को स्वीकार करें।

भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान ने उसे चुनावी प्रक्रिया की देखरेख का व्यापक अधिकार दिया है ताकि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हो सके। निर्वाचन आयोग स्वयं अपने संवैधानिक दायित्व को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से जोड़ता है।लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं बनती। वह जनता के विश्वास से बनती है। इसलिए निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि उसकी प्रत्येक कार्रवाई ऐसी हो जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से भरोसा हो।

ट्रंप के बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाने संबंधी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। यह प्रतिक्रिया बताती है कि भारत में निर्वाचन आयोग को लेकर राजनीतिक विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।यदि सरकार निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करे तो विपक्ष को संदेह हो सकता है। यदि विपक्ष आयोग पर सवाल उठाए तो सरकार इसे राजनीतिक हमला बता सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच संस्थागत निष्पक्षता का प्रश्न कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।निर्वाचन आयोग को न तो सरकार के पक्ष में दिखाई देना चाहिए और न विपक्ष के। उसे केवल संविधान के पक्ष में दिखाई देना चाहिए।

यदि अमेरिका भारत से कुछ सीखना चाहता है तो केवल मतदाता पहचान-पत्र की व्यवस्था को देखकर बात पूरी नहीं हो सकती। भारत की चुनाव प्रणाली एक पूरे संस्थागत ढांचे पर आधारित है। मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, चुनावी आचार संहिता, राजनीतिक दलों के साथ संवाद, चुनाव अधिकारियों की तैनाती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से लेकर मतगणना तक एक विस्तृत व्यवस्था काम करती है।

भारत में चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता लागू करने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 324 इस पूरे ढांचे की आधारशिला है।

अमेरिका यदि भारतीय अनुभव से कुछ ग्रहण करता है तो उसे केवल पहचान-पत्र नहीं, बल्कि चुनाव प्रबंधन की संस्थागत संरचना पर भी विचार करना होगा। यहां बात केवल अमेरिका को भारत से सीखने की नहीं है। भारत को भी अपने चुनावी तंत्र में लगातार सुधार करते रहना होगा। आज मतदाता पहले से अधिक जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में चुनावी जानकारी कुछ सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। गलत सूचना, डीपफेक, फर्जी वीडियो और डिजिटल प्रचार चुनावी वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं।ऐसे में निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और संवाद की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।मतदाता सूची में किसी नागरिक का नाम क्यों जोड़ा गया या क्यों हटाया गया, चुनावी निर्णय किस आधार पर लिया गया, राजनीतिक दलों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई–इन सभी सवालों के जवाब समय पर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना लोकतंत्र के हित में है।डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की ओर ध्यान जाना निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उदाहरण के तौर पर पेश करना भारत की संस्थागत क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है।लेकिन लोकतंत्र में बाहरी प्रशंसा से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विश्वास है।यदि भारत के नागरिक अपने निर्वाचन आयोग पर भरोसा करते हैं, यदि राजनीतिक दल चुनावी परिणामों को स्वीकार करते हैं और यदि हर मतदाता को यह विश्वास रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है तथा उसकी आवाज सुनी जाएगी, तभी चुनाव प्रणाली वास्तव में मजबूत कही जाएगी।आज आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन आयोग अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर न रुके। उसे लगातार खुद को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा।ट्रंप को भारत इसलिए भाया क्योंकि उन्हें अपनी घरेलू राजनीतिक बहस के लिए भारतीय मॉडल में कुछ उपयोगी तत्व दिखाई दिए। लेकिन भारत के लिए इससे बड़ा संदेश यह है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया के लिए उदाहरण बन सकती हैं–बशर्ते हम उनके प्रति जनता का विश्वास बनाए रखें। चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव लोकतंत्र में नागरिक और राज्य के बीच विश्वास का सबसे बड़ा सेतु है। निर्वाचन आयोग उस सेतु का प्रहरी है।

इसलिए ट्रंप की प्रशंसा अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि भारत का आम मतदाता अपने निर्वाचन आयोग के बारे में क्या सोचता है। लोकतंत्र की अंतिम कसौटी वाशिंगटन की प्रशंसा नहीं, बल्कि भारत के मतदान केंद्र पर खड़ा वह सामान्य नागरिक है जो अपने हाथ में मतदाता पहचान-पत्र लेकर यह विश्वास करता है कि उसकी एक-एक वोट की कीमत है। और यही विश्वास भारत के निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी पूंजी है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

एक खत्म, दूसरा शुरू

झारखंड में करीब 25 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विवादित कंपनी टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही घोषणा कर दी कि जेपीएससी 11 व 13 की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं के घोषित परिणाम भी रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। यानी टीडीपीएल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी चुने गए, उनका चयन भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्यारह मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। छात्र आंदोलन के दबाव में काम कर रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। दरअसल, छात्रों के कई खेमे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया,उनमें चौदहवीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और सिविल जूनियर आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया गया। वहीं दूसरी ओर सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरियां भी अब समाप्त मानी जाएंगी। सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2014 के बाद हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। यह जांच कार्य एक न्यायिक आयोग करेगा। बाकायदा एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में सुधारों के लिये एक कमेटी भी बनायी गई है। हालांकि, कुछ आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, सरकार की घोषणा के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घोषणा के बाद सचिवालय परिसर में उन नियुक्त प्रतिभागियों की भीड़ जुट गई, जो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा उतीर्ण करके नौकरी हासिल कर चुके थे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद विभिन्न चयनित प्रतिभागियों का हुजूम सचिवालय में जमा होना शुरू हुआ। उनके लिये यह खबर स्तब्ध करने वाली थी। उनका दुख और गुस्सा स्वाभाविक ही है।

बहरहाल, अब राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद हटाये गए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एक बयान देकर दो हजार लोगों को सरकारी नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? वे इसे सरकारी अन्याय बता रहे हैं। उनकी दलील है कि हम सुबह नौकरी पर थे,लेकिन शाम होते ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमें नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सितंबर 2024 में फिर से हुई। फिर पेपर लीक की आशंका के बीच मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। साथ ही तीस दिसंबर को सफल प्रत्याशियों को बाकायदा नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब सरकार द्वारा ये नियुक्तियां रद्द करने से प्रतिभागी बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों ने लोन लेकर अपना जीवन स्तर सुधारा, उनकी बैंक की किश्तें जा रही हैं। अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा है। उनकी मांग है कि सरकार कायदे से जांच कर ले, लेकिन उन्हें नौकरी से न हटाए। सभी लोग धांधली से भर्ती नहीं हुए हैं। उनका तर्क है कि भीड़ के दबाव में निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। हटाये गए कर्मचारियों की आंखें नम हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी नौकरियां छोड़कर सरकारी नौकरी के प्रलोभन में आए। दुखी व हताश हटाये गए कर्मचारी बारिश में धरने पर बैठे रहे क्योंकि उन्हें अधिकारियों ने सचिवालय से बाहर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हटाए गए कर्मियों के घर वाले भी सदमे में हैं। राज्य सरकार भी मुश्किल में है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों की दलील है कि उनका आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं सरकार के सामने हटाये गए अधिकारियों व कर्मचारियों का नया मोर्चा खुल गया है। हटाये गए कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वे सरकार के लिखित आदेश की प्रतीक्षा में हैं।

मच्छर जानलेवा है, जागरूकता और स्वच्छता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार

कांतिलाल मांडोत

मच्छर आकार में भले ही बहुत छोटा जीव है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए इसका खतरा बेहद बड़ा है। दुनिया में अनेक गंभीर संक्रामक बीमारियों के प्रसार में मच्छरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिस, जीका, पीला बुखार और फाइलेरियासिस जैसी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं। इन बीमारियों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और कई मामलों में स्थिति गंभीर भी हो जाती है। इसलिए मच्छर को केवल परेशान करने वाला कीट मानना उचित नहीं है। यह मानव जीवन के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है।

हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की ऐतिहासिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है। 20 अगस्त 1897 को रॉस ने यह महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी को फैलाने में भूमिका निभाती है। इस खोज ने मलेरिया के संक्रमण और उसके नियंत्रण को समझने की दिशा में चिकित्सा विज्ञान को नई राह दिखाई। रॉस को बाद में वर्ष 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विश्व मच्छर दिवस का उद्देश्य केवल इस वैज्ञानिक उपलब्धि को याद करना नहीं है, बल्कि लोगों को मच्छरजनित बीमारियों के खतरे और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बीमारी फैलने के बाद उपचार करने से बेहतर है कि मच्छरों के प्रजनन को रोककर बीमारी की आशंका को ही कम किया जाए।

मलेरिया मच्छर से फैलने वाली सबसे पुरानी और गंभीर बीमारियों में से एक है। यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। समय पर जांच और उचित उपचार मिलने पर मलेरिया का इलाज संभव है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में यह गंभीर और जानलेवा रूप ले सकता है।

डेंगू भी मच्छरजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों से फैलती है। तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में डेंगू गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए लगातार या तेज बुखार होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। डेंगू की रोकथाम में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में शामिल है।

चिकनगुनिया भी एडीज मच्छरों से फैलता है। इसमें बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जापानी इंसेफलाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। जीका वायरस भी एडीज मच्छरों के माध्यम से फैल सकता है और गर्भावस्था के दौरान विशेष चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा पीला बुखार और फाइलेरियासिस भी मच्छरों से फैलने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां हैं।

मच्छरों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामान्यतः मादा मच्छर ही मनुष्य और अन्य जीवों का रक्त चूसती हैं। मादा मच्छर को अंडों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। नर मच्छर मुख्य रूप से पौधों के रस और अन्य वनस्पति स्त्रोतों पर निर्भर रहते हैं। मच्छर मनुष्य तक पहुंचने के लिए सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और गंध जैसे संकेतों का उपयोग करते हैं। इसी कारण वे मनुष्यों को आसानी से खोज लेते हैं। मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियों का व्यवहार और बीमारी फैलाने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए मच्छर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपाय करना आवश्यक है।

वंदे मातरम प्रेम: हकीकत या फसाना

निर्मल रानी

राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर 2026 के नये सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाना और सभी के लिए सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही औपचारिक अवसरों पर इसके सभी छह छंदों को गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष सहित कुछ अन्य संगठन इस अनिवार्य प्रोटोकॉल को संविधान के अनुच्छेद 25 अर्थात व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हैं। बहरहाल, इन सब के बावजूद वंदेमातरम को संसद में और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लाल किले पर गाया गया क बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा1875 में मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखे इस गीत के शब्द काफी कठिन हैं। 6 छंदों पर आधारित यह गीत काफी लंबा भी है। चूँकि आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों को ही आधिकारिक तौर पर गाया जाता रहा है, इसलिए देश के अधिकांश राजनेताओं और आम नागरिकों को भी इसके बाद के 4 छंद कंठस्थ याद नहीं होते हैं। लेकिन भाजपा के मामले में यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वह अन्य दलों पर राष्ट्रगीत के अपमान का तो आरोप लगाती है, जबकि खुद उसके अपने नेता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में चूक जाते हैं।

समय-समय पर भाजपा के नेताओं की इस गीत को लेकर अज्ञानता कैमरे पर भी उजागर हुई है। एक टेलीविजन लाइव डिबेट के दौरान, जब भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह दूसरों को वंदे मातरम् गाने की चुनौती दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे स्वयं इसे गाने को कह दिया। वे अपने मोबाइल फोन में देखने के बावजूद गीत की गलत पंक्तियाँ गाने लगे और धुन भी पूरी तरह भूल गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह औलख से जब पत्रकारों ने वंदे मातरम् की कुछ पंक्तियाँ सुनाने को कहा, तो वे बेहद असहज हो गए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस समय पूरा याद नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में भाजपा के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, मंच पर राष्ट्रगीत गाते समय गलत धुन और गलत वर्जन बज गया। कांग्रेस द्वारा इस बड़ी चूक पर हमला किए जाने के बाद राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कोटा, मेरठ और ग्वालियर जैसे कई शहरों में भाजपा के स्थानीय विधायकों और सांसदों के ऐसे अनेक वीडियो सामने आ चुके हैं, जहाँ वे वंदे मातरम् और राष्ट्रगान (जन गण मन) के बीच अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं या गीत की पंक्तियों को आपस में मिला देते हैं। हाल ही में गुजरे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब वंदे मातरम् को लेकर नया कानून और राष्ट्रगीत विवाद गरमाया, तो विपक्ष ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिन्होंने वंदे मातरम् को लेकर कड़े कानून बनाये हैं, हक़ीकत यह है कि उनके अपने नेताओं और मंत्रियों को भी यह गीत पूरा याद नहीं है।

उधर मुस्लिम समुदाय के भीतर इस गीत को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण और विचार हैं। हालाँकि समग्र मुस्लिम समाज वंदे मातरम् गायन का विरोध नहीं करता है परन्तु समाज के कुछ लोग या कुछ धार्मिक संगठन इसके पूरे पाठ या कुछ विशिष्ट छंदों का विरोध करते हैं। जबकि अनेक अन्य मुस्लिम नागरिक,प्रतिष्ठित लोग और कलाकार इसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सहजता से गाते भी हैं। दरअसल मुसलमानों के एक वर्ग के वंदे मातरम् का विरोध करने के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक कारण हैं। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित इस्लाम धर्म में केवल एक अल्लाह की इबादत की अनुमति है। जबकि वंदे मातरम् का शाब्दिक अर्थ माँ, मैं आपकी वंदना/पूजा करता हूँ होता है जहाँ देश को एक देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे धार्मिक संगठनों का मानना है कि अल्लाह के अलावा किसी भी अन्य सत्ता, भूमि या मूर्ति के सामने झुकना या उसकी पूजा करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुछ इतिहासकारों और मुस्लिम विचारकों का मानना है कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि और कुछ अंशों में मुस्लिम विरोधी भावनाएं निहित थीं, जिससे इस गीत को लेकर ऐतिहासिक रूप से एक संशय पैदा हुआ। कई मुस्लिम नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों का यह तर्क भी है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 और 25 नागरिकों को अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनका कहना है कि देशभक्ति साबित करने के लिए किसी को भी ऐसा गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी धार्मिक आस्था से टकराता हो। हालांकि इस विषय पर मुस्लिम समाज भी एकमत नहीं है। कुछ उलेमाओं का मानना है कि इसके छंदों में मूर्तिपूजा और देवी स्वरूप की स्तुति शामिल है, इसलिए वे इसे गाने से परहेज करते हैं। यही वजह थी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही इस गीत के केवल शुरूआती दो छंदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। पहले दो छंदों में देश की प्राकृतिक सुंदरता (सुजलां सुफलां) का वर्णन है, जिस पर कई प्रगतिशील मुस्लिम संगठनों को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि कई उदारवादी मुस्लिम, आम नागरिक और कलाकार इसे बिना किसी धार्मिक चश्मे के केवल अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और प्रेम के रूप में देखते हैं। जैसे कि संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा गाया गया मां तुझे सलाम वंदे मातरम बेहद लोकप्रिय है। ऐतिहासिक रूप से भी, स्वतंत्रता संग्राम जैसे कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान मुस्लिम नेताओं ने इस गीत और नारे का खुलकर समर्थन किया था। इसलिए, वर्तमान में भी यह मुद्दा पूरे मुस्लिम समाज का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत धार्मिक प्राथमिकताओं और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

परन्तु आज जब देश का बड़ा वर्ग खासकर युवा शिक्षा की होती दुर्गति, पेपर लीक, भयंकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दयनीय स्वास्थ सेवाओं, बेतहाशा बढ़ती मंहगाई, मंदिर दान चोरी आदि से दुखी होकर सड़कों पर उतर रहा है। आज जब भारत में बाल कुपोष की यह स्थिति है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार हर दूसरा भारतीय बच्चा कुपोषित है,देश का गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है,खुद सरकारी दावों के अनुसार 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो मुफ़्त राशन पर आश्रित है। ऐसे में क्या वंदे मातरम गाने से लोगों को बेहतर जिन्दगी मिल सकेगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा ? या फिर भाजपा इसे अपने राजनैतिक स्वभाव के अनुरूप मात्र हिन्दू मुस्लिम के बीच का भावनात्मक मुद्दा बनाकर उछालना चाह रही है? वह भी तब जबकि इसके अपने अधिकांश सांसद व नेता न तो वंदे मातरम गा सकते हैं न ही उन्हें कंठस्थ है। दरअसल भाजपा द्वारा वंदे मातरम के प्रति प्रेम प्रदर्शन के पीछे की हक़ीकत कुछ और है और फसाना कुछ और।

सेल्समैन ने 30 फीट ऊंचे पुल से कूद 150 मीटर तैरकर बचाया, अब मिलेगा इनाम

महानगर मेट्रो ब्यूरो

विदिशा। आत्महत्या के इरादे से बेतवा नदी में कूदी एक छात्रा की जान रायसेन के रहने वाले विनोद पटेरिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाकर बचा ली। इस सराहनीय कार्य के लिए विदिशा कलेक्टर ने श्री पटेरिया को 10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है।, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इंसानियत और बहादुरी की एक बेहद प्रेरणादायक घटना सामने आई है। यहां बेतवा नदी में आत्महत्या के उद्देश्य से कूदी एक छात्रा को रायसेन के एक साहसी युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवक ने गजब की तत्परता दिखाई, जिसकी अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। विदिशा कलेक्टर ने इस बहादुरी को सम्मान देते हुए श्री पटेरिया को 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायसेन शहर के वार्ड नंबर 13, शाखा ग्राउंड के पास रहने वाले विनोद पटेरिया विदिशा में एक निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। वे रोजाना की तरह रायसेन से विदिशा अप-डाउन करते हैं। बुधवार को जब वे अपनी ड्यूटी के सिलसिले में विदिशा जा रहे थे, तो रास्ते में ग्राम सौठिया स्थित बेतवा पुल के पास उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। वे वहां घर की पूजन सामग्री विसर्जित करने के लिए रुके हुए थे। ुल के पास पहले से ही एक छात्रा संदिग्ध हालत में खड़ी हुई थी। विनोद पटेरिया की नजर जब उस पर पड़ी, तो उन्होंने सहज भाव से उससे पूछा कि वह वहां अकेली क्यों खड़ी है। हालांकि, छात्रा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ ही पलों बाद छात्रा ने अचानक बेतवा नदी में छलांग लगा दी। बिना एक पल गंवाए विनोद पटेरिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती या गहरी नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा की जान बचा ली। रायसेन निवासी सेल्स मैनेजर विनोद पटेरिया ने बेतवा नदी में कूदकर बचाई छात्रा की जान। विदिशा कलेक्टर ने साहसी युवक को 10 हजार रुपये और प्रशंसा पत्र देने का किया ऐलान। घटना बुधवार को ग्राम सौठिया स्थित बेतवा पुल के पास घटित हुई। पूजन सामग्री विसर्जित करने रुके थे विनोद पटेरिया, तभी सामने आया यह गंभीर

मामला। समय पर मदद मिलने के कारण छात्रा की सुरक्षित बचा लिया गया, पुलिस जांच जारी इस घटना की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन तक पहुंची, विदिशा कलेक्टर ने विनोद पटेरिया के इस साहसी और मानवीय कदम की जमकर तारीफ की। प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है ताकि समाज में इस तरह के प्रेरणादायक कार्यों को बढ़ावा मिल सके।

घर के बाहर खेल रहा था 2 साल का बच्चा, तभी आई कार और कुचलते चली गई - CCTV

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गाजियाबाद। उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में रविवार को घर के बाहर खेल रहे दो वर्षीय बच्चे दिवित को कार चालक ने टक्कर मार दी. हादसे में बच्चा कार के टायर के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे दिल्ली के निजी अस्पताल के पीआईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के रामप्रस्थ बी-ब्लॉक में रविवार दोपहर घर के

बाहर गली में खेल रहे दो वर्षीय बच्चे को कार चालक ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बच्चा कार के टायर के नीचे आ गया. जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल उसे दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार रामप्रस्थ बी ब्लॉक निवासी पवन सारस्वत का दो वर्षीय बेटा दिवित रविवार दोपहर घर के बाहर गली में खेल रहा था. इसी दौरान एक कार वहां से गुजरी. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कार बच्चे की ओर बढ़ती है और उसे टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद बच्चा कार के टायर के नीचे आ जाता है. कार का टायर बच्चे के ऊपर से निकलने के बाद चालक वाहन रोकता है और नीचे उतरता दिखाई देता है. वहीं हादसे के तुरंत बाद बच्चे की मां दौड़कर मौके पर पहुंचती है और सड़क पर पड़े बच्चे को उठाकर गोद में ले लेती है. इसके बाद वह बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है. सीसीटीवी फुटेज में कार चालक भी अपनी कार को पीछे करते हुए मौके से पीछे की ओर जाता दिखाई दे रहा है. परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद बच्चे को तत्काल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर चोटों के कारण उसे पीआईसीयू में रखा गया है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद परिजनों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में कार का नंबर सामने आने के बाद बच्चे के पिता पवन सारस्वत ने लिंक रोड थाने में शिकायत देकर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एसपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है.

पीलीभीत की 'कातिल' प्रेमिका: रॉड से प्रेमी का सिर फोड़ा, डीजल से नहलाया, फिर ट्रक में लगा दी आग

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पीलीभीत। थाना पूरनपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे (ह॥-730) पर जलते ट्रक में चालक बलविंदर सिंह की मौत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने शुरुआती जांच में हादसा लग रही इस घटना को सोची-समझी हत्या पाया और आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया.द्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 10 जुलाई की रात ट्रक में आग लगने से चालक व मालिक बलविंदर सिंह की जलकर मौत हो

गई थी. पुलिस जांच में यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी खौफनाक हत्या की वारदात निकली. रुद्रपुर निवासी 40 वर्षीय प्रेमिका अमनदीप कौर उर्फ अमन ने अपने प्रेमी बलविंदर सिंह से पीछा छुड़ाने के लिए केबिन में बातचीत के दौरान लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर बेहोश कर दिया. इसके बाद साक्ष्य मिटाने और दुर्घटना का रूप देने के लिए केबिन में डीजल डालकर आग लगा दी. 10 जुलाई 2026 को पूरनपुर पुलिस को बड़ी नहर, गुरुद्वारा धन्ना बाबा के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में भीषण आग लगने की सूचना मिली. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो केबिन से जला हुआ शव मिला. मृतक की पहचान रामपुर निवासी बलविंदर सिंह के रूप में हुई. भाई गुरमीत सिंह की तहरीर पर पूरनपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी महिला अमनदीप कौर को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने कबूला कि वह पिछले 2-3 वर्षों से जारी प्रेम संबंध को खत्म करना चाहती थी, जबकि बलविंदर जिद पर अड़ा था. 10 जुलाई को मुलाकात के दौरान विवाद बढ़ने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया. विवाद के दौरान महिला ने ट्रक में रखी लोहे की रॉड से बलविंदर के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया.

शिक्षकों की कमी पर भड़के Gen Alpha छात्र, स्कूल ड्रेस में सड़क किया जाम, मनाने पहुंचे डीएम और एसपी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

उन्नाव। यूपी के उन्नाव में जेन अल्फा छात्रों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी और खराब खाने के साथ तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर मोहान चौराहे की सड़क जाम कर दी है। छात्रों के प्रदर्शन की खबर सुनकर डीएम, एसपी सहित तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया और उनकी समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। यही नहीं, डीएम और एसपी ने खाने की क्वालिटी चेक

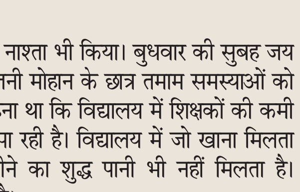

करने के लिए बच?चों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। बुधवार की सुबह जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी मोहान के छात्र तमाम समस्याओं को लेकर आक्रोशित हो गए। छात्रों का कहना था कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विद्यालय में जो खाना मिलता है उसकी भी क्वालिटी खराब है। पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है। विद्यालय परिसर में गंदगी का आलम है।

शरीर इंसान का, चेहरा कुत्ता वाला MP के खंडवा में आदमी के डॉगी बनने की कहानी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मध्य प्रदेश। खंडवा में जनसुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अनोखा विरोध देखने को मिला. नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक (मुल्लू) राठौर एक शख्स को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर कलेक्टर सभागृह पहुंचे. शरीर इंसान का, लेकिन चेहरा कुत्ते वाला... मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स डॉगी का मुखौटा पहनकर जनसुनवाई में पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया. लेकिन यह सिर्फ मजाकिया अंदाज नहीं था, बल्कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनकी नसबंदी के नाम पर खर्च हुए लाखों रुपये को लेकर विरोध का अनोखा तरीका था. डॉगी बनकर पहुंचे इस शख्स ने नगर निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि नसबंदी के बाद भी वह 6 बच्चों का पिता बन गया. दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जहां नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक (मुल्लू) राठौर एक शख्स को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर कलेक्टर सभागृह पहुंच गए. शरीर इंसान का था, लेकिन चेहरा डॉगी वाला. इस अनोखे अंदाज में उन्होंने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा अधिकारियों के सामने उठाया. ाठौर का आरोप है कि खंडवा में पिछले चार वर्षों के दौरान कुत्तों की नसबंदी के नाम पर नगर निगम ने करीब 40 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इसी अवधि में शहर में कुत्तों के काटने की 13225 घटनाएं सामने आई हैं. जनसुनवाई में उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि डॉगी की नसबंदी कराई गई, लेकिन इसके बाद भी वह छह बच्चों का पिता बन गया. इसके जरिए उन्होंने नसबंदी के काम में कथित गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, जब व्यक्ति डॉगी का ड्रेस पहनकर गया तो शुरुआत में कलेक्टर सभागृह के बाहर पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उसे अंदर जाने दिया गया. जनसुनवाई में डॉगी के रूप में पहुंचे शख्स को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. कुछ देर बाद माहौल में हंसी-मजाक भी हुआ, लेकिन

शिकायत का मुद्दा गंभीर होने के कारण अधिकारियों ने इसे गंभीरता से सुना. एडिशनल कलेक्टर काशीराम बड़ोले ने शिकायत पर नगर निगम आयुक्त से चर्चा की. उन्होंने कहा कि कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर 40 लाख रुपये के बिल निकाले जाने और काम नहीं होने की शिकायत मिली है.

DM सर, सड़क बनवा दीजिए स्कूल ड्रेस में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बच्चे, 3 KM तक कीचड़ भरे रास्ते की कहानी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गांव के बच्चे रोज करीब तीन किलोमीटर का रास्ता तय करके स्कूल जाते हैं. बारिश शुरू होते ही इस रास्ते ने उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया है. कहीं घुटनों तक कीचड़, कहीं फिसलन और कहीं ऐसा दलदल कि पैदल निकलना भी मुश्किल. इसी परेशानी को लेकर बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई. सुबह बच्चे तैयार हुए. यूनिफॉर्म पहनी. बैग उठाया. लेकिन इस बार मंजिल स्कूल नहीं थी. बच्चों का काफिला सीधे कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया. हाथों में किताबें नहीं, एक शिकायत थी. चेहरे पर मासूमियत थी, सवाल था कि जब स्कूल तक जाने वाली सड़क ही दलदल बन जाए, तो पढ़ने जाएंगे कैसे? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रम्पुरा गांव के ये बच्चे रोज करीब तीन किलोमीटर का रास्ता तय करके केरपानी गांव के स्कूल जाते हैं. लेकिन बारिश आते ही यही तीन किलोमीटर उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रह जाता. कच्ची सड़क पर पानी और कीचड़ जमा है. कई जगह रास्ता दलदल में बदल गया है. बच्चे पैदल निकलते हैं तो जूते कीचड़ में धंसते हैं, कपड़े खराब होते हैं और हर कदम पर फिसलने का डर बना रहता है. अब बच्चों ने तय किया कि अगर

सड़क स्कूल तक नहीं पहुंच रही, तो अपनी शिकायत लेकर वे खुद प्रशासन तक पहुंचेंगे. और इसलिए स्कूल ड्रेस में ही कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. रम्पुरा गांव के बच्चों का रोज का रूट तय है. घर से निकलो, करीब तीन किलोमीटर पैदल चलो और केरपानी गांव के स्कूल पहुंचो. लेकिन बारिश ने इस पूरे रास्ते का नक्शा बदल दिया. जिस जगह सड़क होनी चाहिए, वहां कीचड़ है. जहां बच्चों को पैदल चलना चाहिए, वहां पैर संभालना मुश्किल है. इसी परेशानी से परेशान होकर बड़ी संख्या में बच्चे अपनी स्कूल ड्रेस में नरसिंहपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. बच्चों ने अधिकारियों को अपनी समस्या बताई. उनका कहना था कि बारिश के बाद रम्पुरा से केरपानी तक की सड़क बेहद खराब हो गई है और रोज स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है. अब सोचिए. स्कूल घर से तीन किलोमीटर दूर हो और रास्ता पक्का हो, तो बच्चे आराम से पैदल या किसी साधन से स्कूल पहुंच सकते हैं. लेकिन वही तीन किलोमीटर अगर कीचड़ से भरे हों, तो कहानी बदल जाती है. रम्पुरा से केरपानी जाने वाली कच्ची सड़क बारिश के बाद दलदल में बदल गई है. बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है. कहीं पैर फिसलता है, कहीं जूते कीचड़ में धंसते हैं और कहीं कपड़े गंदे होने का डर. बच्चों के मुताबिक, कई बार रास्ता पार करना इतना मुश्किल हो जाता है कि स्कूल पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती बन जाता है. स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहननी होती है. लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा हो तो यूनिफॉर्म साफ कैसे रहे? एक तरफ स्कूल में शिक्षक के सामने साफ-सुथरे कपड़ों में पहुंचने की चिंता. दूसरी तरफ रास्ते में गिरने और कीचड़ में कपड़े खराब होने का डर. बच्चों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल जाने का मतलब ही कीचड़ से होकर गुजरना है. और अगर कोई बच्चा फिसल गया तो चोट लगने का खतरा अलग. यानी पढ़ाई के लिए निकलने वाले बच्चों को रास्ते में हर दिन एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बच्चों ने अपनी मांग अधिकारियों के सामने रखी कि सर, रम्पुरा से केरपानी तक सड़क बनवा दीजिए. बच्चों ने बताया कि सड़क बन जाएगी तो उन्हें स्कूल जाने में परेशानी नहीं होगी. बारिश में रास्ता दलदल नहीं बनेगा.

जिस क्लीनिक में करती थीं मरीजों का इलाज, वहीं मिला शव डॉक्टर खुशहाली की कहानी में अब तक क्या-क्या हुआ

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मेरठ। उत्तरप्रदेश के मेरठ एक कमरा था. बाहर क्लीनिक का बोर्ड लगा था. इसी जगह पर लोग इलाज के लिए आते थे. डॉक्टर खुशहाली मरीजों का इलाज करती थीं और अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिख रही थीं. लेकिन एक दिन इसी क्लीनिक का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था. खुशाली का शव फंदे से लटका मिला. जिस जगह पर कभी मरीज अपनी बीमारी लेकर पहुंचते थे, वहां एक दिन पुलिस पहुंची. ये वही क्लीनिक था, जिसे डॉक्टर खुशहाली ने अपनी नई जिंदगी और करियर के तौर पर शुरू किया था. लेकिन रविवार को इसी क्लीनिक के अंदर उनका शव फंदे से लटका मिला.

दरवाजा भीतर से बंद था. पहली नजर में पुलिस ने मामले को सुसाइड बताया. वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग और बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. इस मामले में 16 अगस्त को तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ और अब पुलिस ने खुशहाली के पति मयंक चौधरी और ससुर हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. सवाल है कि आखिर उस क्लीनिक के अंदर क्या हुआ था यह मामला मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र का है. रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में स्थित एक क्लीनिक में महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटका हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंची तो क्लीनिक का दरवाजा भीतर से लॉक था. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

लखनऊ से लापता दरोगा 7 दिन बाद प्रयागराज के होटल में मिले, सब इंस्पेक्टर बीवी से नाराज होकर घर से निकले थे

महानगर मेट्रो ब्यूरो

लखनऊ। इंदिरानगर थाने की तकरोही चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक आनंद कुमार मिश्रा के 11 अगस्त को लापता होने के बाद लखनऊ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। तेजी से चली छानबीन के बीच आखिरकार 7 दिन बाद लखनऊ से गायब दरोगा प्रयागराज के एक होटल से सकुशल बरामद हुए। आनंद मिश्रा की पत?नी अंजली तिवारी भी सब इंस?पेक?टर हैं। उनकी शिकायत पर सरोजनीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस की

कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई थीं। अंजली तिवारी सरोजनीनगर थाना क्षेत्र की विष्णु लोक कॉलोनी में रहती हैं। वह DCP सेंट्रल कार्यालय में तैनात हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 11 अगस्त की दोपहर आनंद अपनी कार घर पर ही छोड़कर कपड़ों से भरा बैग लेकर पैदल निकले थे। देर शाम तक जब वह ड्यूटी से नहीं लौटे और फोन स्विच ऑफ आने लगा तो उन्हें चिंता हुई। पुलिस टीम ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। जांच के दौरान उनकी अंतिम एक्टिव लोकेशन वाराणसी में मिली थी। इसके बाद लखनऊ कमिश्नरेट की एक विशेष टीम बनारस के रेलवे स्टेशनों और होटलों की खाक छानने भेजी गई थी। बोकारो में बेटे ने की 60 वर्षीय मां की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तारसरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेव ने बताया कि पता चला कि दरोगा प्रयागराज के एक होटल में ठहरे हैं। पूछताछ में सामने आया कि दरोगा आनंद कुमार मिश्रा पारिवारिक कलह के चलते नाराज होकर निकले थे। लखनऊ से निकलने के बाद वह सीधे वाराणसी पहुंचे और वहां दो दिनों तक ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने वाराणसी से एक प्राइवेट कार बुक की और प्रयागराज पहुंच गए, जहां एक होटल में कमरा लेकर रुक गए।

बरगी डैम के 9 गेट खुले, 0.78 मीटर ऊंचाई तक गेट खोलकर छोड़ा जा रहा 1031 क्यूमेक पानी

मानसून सीजन में पहली बार बरगी बांध के नौ गेट खोल दिए गए हैं

महानगर मेट्रो ब्यूरो

जबलपुर। जिले में स्थित रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना यानी बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद मानसून सीजन में पहली बार इसके नौ जलद्वार खोल दिए गए हैं। जलस्तर को नियंत्रित रखने और सुरक्षा के लिहाज से बांध प्रबंधन ने यह कदम उठाया है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे बांध के नौ गेटों को औसतन 0.78 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया, जिससे करीब 1031 क्यूमेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने के साथ ही नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर उठने लगा है।

निचले घाटों पर चार फीट तक बढ़ा जलस्तर

बांध से पानी छोड़े जाने का असर तुरंत जबलपुर के प्रमुख घाटों पर देखने को मिला। मंगलवार सुबह पानी छोड़े जाने के बाद गौरीघाट, तिलवारा और भेड़ाघाट सहित नर्मदा के निचले क्षेत्रों के तमाम घाटों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन घाटों पर पानी का स्तर करीब चार फीट तक ऊपर आ चुका है। पानी बढ़ने की इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और बांध प्रबंधन ने तटीय इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और सतर्कता बढ़ा दी है। बांध प्रबंधन के अनुसार, जब सुबह 11:30 बजे नौ गेटों से 1031 क्यूमेक पानी छोड़ा गया, तो बरगी बांध का वह एरिया भी पूरी तरह जलमग्न हो गया जो बारिश न होने के कारण सूखा हुआ था। इस सूखे इलाके तक आम लोग आसानी से पहुंचकर घूमा करते थे। वर्तमान में बांध का जलस्तर 421.00 मीटर दर्ज किया गया है। बांध की कुल उपयोगी क्षमता 2730 एमसीएम यानी 85.85 प्रतिशत है, जबकि पानी की औसत आवक 1200 क्यूमेक बनी हुई है। बांध से वर्तमान में 1031 क्यूमेक और पावर हाउस (आरबीपीएच) से 195 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। गौरीघाट, तिलवारा और भेड़ाघाट के निचले हिस्सों में जलस्तर चार फीट तक बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में जलभराव क्षेत्र में औसतन 7.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल आज ही के दिन बांध का जलस्तर 420.20 मीटर (78.80 प्रतिशत क्षमता) था।

AK47 जैसे हथियारों को दिल्ली पुलिस ने किया नष्ट, नरेला में गड्डें खोदकर किया तबाह

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मणिपुर। बरामद किए गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों को दिल्ली में नष्ट किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय सेना और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम के साथ मिलकर नरेला के टिकरी इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया. सुरक्षा को देखते हुए हथियारों को खुले और सुरक्षित इलाके में नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया. जानकारी के मुताबिक, नष्ट किए गए हथियारों में रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और दूसरे सैन्य स्तर के विस्फोटक शामिल थे. ये हथियार मणिपुर में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़े बताए जा रहे हैं. बरामद हथियार बेहद खतरनाक और संवेदनशील होने के कारण उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना जरूरी था. इस कार्रवाई में भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और की विशेषज्ञ टीमों ने मिलकर काम किया. टीम ने पहले हथियारों और विस्फोटकों की जांच की और इसके बाद उन्हें नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. नष्ट किए गए हथियारों में/च सीरीज के दो राइफल, एम4 कार्बाइन और एसएलआर जैसे राइफल शामिल थे., सूत्रों के मुताबिक, इन हथियारों का कनेक्शन मणिपुर में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकियों से सामने आया था. इनमें प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी यानी KCP के एक शीर्ष कमांडर के शामिल होने की बात भी सामने आई है. हथियारों की बरामदगी के बाद एजेंसियां इनके नेटवर्क और सप्लाई चैन की जांच कर रही हैं. मणिपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का अभियान लगातार जारी है. इस साल के शुरुआती छह महीनों में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1,422 हथियार और 1,137 विस्फोटक बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इनमें कितनी संख्या में हथियार नष्ट किए गए हैं, यह साफ नहीं है. जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों को वापस हासिल करने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली हुई कूड़ा-कूड़ा साथी की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी, काम का किया बहिष्कार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने का काम रोक दिया है. इसका असर अब दिल्ली की सड़कों और गलियों में साफ दिखाई दे रहा है. कई इलाकों में कूड़े के ढेर जमा हैं और तेज बदबू से लोग परेशान हैं. कुछ जगहों पर कचरे के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है. पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या के बाद सफाई कर्मचारियों की नाराजगी अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देने लगी है. कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने का काम रोक दिया है, जिसके चलते राजधानी के कई इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं. सड़कों और गलियों में फैली गंदगी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. कई स्थानों पर कूड़े से उठने वाली तेज बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सामने आई तस्वीरों में कई जगह सड़क किनारे बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा दिखाई दे रहा है. हालात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में लोगों को कूड़े के ढेर के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है. सड़कों के किनारे जमा कचरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है. लंबे समय तक कूड़ा नहीं उठने से लोगों में संक्रमण और बीमारियों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है. इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है. पूर्वी दिल्ली की कोंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने दो दिन पहले कहा था कि अगर दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जमा होता है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी. उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए थे वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें दिल्ली में कहीं कूड़ा या गंदगी दिखाई देती है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर उन्हें या अपने क्षेत्र के पार्षद को भेजें, ताकि समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. हालांकि, फिलहाल कई इलाकों की जमीनी तस्वीर सरकारी दावों से अलग नजर आ रही है. सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद उनकी नाराजगी, कूड़ा उठाने का काम बंद होना और लगातार बढ़ते कूड़े के ढेर ने दिल्ली के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है.

दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले, नागरिक आवास योजना में 1287 और फ्लैट्स शामिल; 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर होगी बुकिंग

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है जिसके तहत 1287 फ्लैट्स शामिल किए गए हैं। इनमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होगी। इन फ्लैट्स पर पहले की तरह 25 फीसदी की छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। इस योजना की कई मुख्य विशेषताएं हैं।, डीडीए ने नागरिक आवास योजना-2026 के तहत नरेला में 1,287 और फ्लैट बिक्री के लिए जोड़े हैं। इनमें 790 एमआईजी और 497 एचआईजी फ्लैट शामिल हैं। इन पर पहले की तरह 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बुकिंग 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। ये फ्लैट नरेला के पॉकेट-3 और पॉकेट-4, सेक्टर ए1-ए4 में है। पॉकेट-3 में 386 एमआईजी फ्लैट (126.1 से 140.1 वर्गमीटर) हैं, जिनकी 25' छूट के बाद कीमत 73.02 लाख से 81.12 लाख रुपये है। यहां 230 एचआईजी फ्लैटों की कीमत 100.96 लाख से 116.39 लाख रुपये के बीच है।

डीडीए नागरिक आवास योजना की मुख्य विशेषताएं

पहले आओ, पहले पाओ: फ्लैटों का आवंटन 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' (पहले आओ, पहले पाओ) के आधार पर किया जाता है। इसके तहत नरेला और अन्य क्षेत्रों में तैयार फ्लैट्स की बुकिंग कराई जाती है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली में कोई बड़ा प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए।

फ्लैट पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

डीडीए नागरिक आवास योजना के तहत एलआईजी फ्लैट्स के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है।

7 साल की सजा, जमानत भी नहीं, रक्षाबंधन से महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू, जानिए कानून में क्या-क्या

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग से 17 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह कानून 28 अगस्त 2026 से प्रभावी हो जाएगा। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके लागू होने की तारीख निर्धारित की है। सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव, धोखे, प्रलोभन या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बल, छल या लालच का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।

धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी

कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। इसके बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकार के फैसले में सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान को लेकर हो रही है, जिसमें कथित तौर पर धोखे, छल या केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह के मामलों का उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों में विवाह की वैधता और उससे जुड़े कानूनी प्रभावों पर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जानकारी के अनुसार, यदि विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया पाया जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे की धार्मिक पहचान के संबंध में मां के विवाह पूर्व मूल धर्म को आधार माना जाएगा।

संजय निरुपम ने जताई खुशी

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव और लालच के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। यह कानून रक्षा बंधन के दिन लागू होने जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में शादी के नाम पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और उनके मूल धर्म की कानूनी स्थिति की रक्षा करना है। कानून में विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों के धर्म से जुड़े प्रावधान शामिल हैं और राज्य सरकार महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बना रही है।

पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का पड़ोसी युवक गिरफ्तार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपलवंडी गांव में साढ़े 9 साल की बच्ची की कथित यौन उत्पीड़न के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय आरोपी बच्ची को अमरूद देने के बहाने खेत में ले गया था. बच्ची के लापता होने पर परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने पड़ोस में रहने वाली साढ़े 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना मंगलवार दोपहर जुन्नार तहसील के पिंपलवंडी गांव में हुई. 25 साल का आरोपी, जो दिहाड़ी मज़दूर है, उसे हिरासत में ले लिया गया है. महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इस घटना को 'बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. उन्होंने पुलिस को मामले की गहन जांच करने और दोषी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पवार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने का आग्रह करेंगी. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. गिल ने बताया कि दोपहर में जब बच्ची टीवी देख रही थी, तो वह उसके घर गया और अमरूद देने के बहाने उसे अपने साथ ले गया. वह कथित तौर पर बच्ची को पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. शाम को जब बच्ची नहीं मिली, तो उसके परिवार ने उसे ढूंढा और बाद में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने कहा कि जांच और इलाके के ष्टष्टञ्जङ्क फुटेज के विश्लेषण के दौरान पता चला कि बच्ची आरोपी के साथ थी. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. बाद में शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. गिल ने आगे कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की जांच चल रही है. डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने दोषी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने फ़ोन पर SP गिल से बात की और घटना की जांच की समीक्षा की.

दिल्ली वाले हो जाएं सावधान, महानगर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के केस

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। एमसीसीडी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास डेंगू से लड़ने के लिए दवाइयां न के बराबर हैं। यही वजह है कि डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले सप्ताह यानी 14 अगस्त तक डेंगू के 14 मामले दर्ज हो हुए थे। वेस्ट जोन और शाहदरा नॉर्थ जोन में दो-दो मामले सामने आए हैं। बाकी 10 जोनों में एक-एक मामला सामने आया है। अगर डेंगू के अब तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा 40, सेंट्रल जोन में 31, शाहदरा साउथ जोन में 24 मामलों सामने आए हैं। सूत्रों का कहना है कि पब्लिक हेल्थ विभाग डेंगू से जुड़े आंकड़ों में भी हेराफेरी कर रहा है। 11 अगस्त को डेंगू के 230 मामले बताए गए थे। वहीं, ताजा रिपोर्ट में डेंगू के 223 मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। यानी आंकड़े घट गए। पब्लिक हेल्थ विभाग में तैनात रहे एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियां फरवरी से मई के बीच शुरू हो जाती हैं।

कीटनाशकों की भारी कमी

पब्लिक हेल्थ विभाग को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से जिन 5 तरह के कीटनाशकों की जरूरत होती है, उन पांचों कीटनाशकों की भारी कमी है। सूत्रों ने बताया कि एक वार्ड में पूरे सीजन के दौरान अगर 25 किलो कीटनाशक लगता है तो उसकी जगह पांच किलो ही दिया जा रहा है।

रोकथाम की तैयारियों पर सवाल

कीटनाशकों की कमी के बीच मच्छरों की रोकथाम का काम प्रभावित होने की आशंका है। एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है, ऐसे में समय रहते पर्याप्त दवाइयों और कीटनाशकों की व्यवस्था जरूरी है। विभाग की मौजूदा तैयारियों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

दिल्ली पुलिस में फेरबदल, चौधरी को फिर ट्रैफिक, अग्रवाल को सौंपी सिक्योरिटी, कई अफसरों को दीं नई जिम्मेदारियां

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के कमान संभालने के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस में ऊपरी लेवल पर पहला फेरबदल हुआ। राजधानी में 12-13 सितंबर को होने जा रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर इसे अहम माना जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की कमान फिर से एक बार 1996 बैच के अनुभवी आईपीएस अफसर अजय चौधरी को सौंपी गई है, जो सिक्योरिटी यूनिट के स्पेशल सीपी थे। इसी बैच के अफसर स्पेशल सीपी (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार को जारी ऑर्डर के मुताबिक, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर एलजी ने मुहर लगाई है। सीपी अनुराग कुमार ने मंगलवार शाम को एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। इसके बाद गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) संतोष डी. वैद्य ने 43 आईपीएस-दानिप्स अफसरों की तैनाती का यह आदेश जारी किया। 1994 बैच की आईपीएस स्पेशल सीपी गरिमा भटनागर को आर्थिक अपराध शाखा (श्वह्लङ्ख) के साथ अब दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी प्रभार दिया गया है।

पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल, कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां

अरुणाचल से आए 1999 बैच के विवेक किशोर स्पेशल सीपी लाइसेंसिंग और SPUWAC होंगे। अंडमान-निकोबार से आईं 2001 बैच की सिंधु पिल्लई को स्पेशल सीपी (विजिलेंस) के अलावा परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।राष्ट्रपति भवन से अटैच किए गए वीनू बंसल जॉइंट सीपी SPUWAC-SPUNER का काम देखेंगे। जॉइंट सीपी (हेडक्वार्टर) सुमन गोयल वेस्टर्न रेंज, जॉइंट सीपी रजनीश गुप्ता ट्रांसपोर्ट रेंज, जतिन नरवाल स्पेशल ब्रांच, मिलिंद महादेव डुंबरे ईस्टर्न रेंज तो 2007 बैच की नुपुर प्रसाद नई दिल्ली रेंज संभालेंगी। ईस्टर्न रेंज के जॉइंट सीपी अजीत सिंगला 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।

दिल्ली पुलिस में हुए तबादले

नई दिल्ली रेंज से दीपक पुरोहित को जॉइंट सीपी लाइसेंसिंग के तौर पर भेजा गया है। गोवा से आए अजय कृष्ण शर्मा जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर होंगे। एडिशनल सीपी मोनिका भारद्वाज अब क्राइम ब्रांच तो संजय भाटिया एडिशनल सीपी होंगे। एडिशनल सीपी दिनेश गुप्ता को ट्रैफिक से DPHCL भेजा गया है। गोवा से आई वर्षा शर्मा को एडिशनल सीपी EOW होंगी। दिल्ली से बाहर जाने वालों की सूची में रही प्रतीक्षा गोदरा एडिशनल सीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर होंगी। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांठिया को टेक एंड पीआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नॉर्थ की एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट अब जिले की नई कप्तान होंगी। साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी को स्पेशल ब्रांच भेजा गया है, उनकी जगह पर 2015 बैच के आईपीएस विनीत कुमार अब जिले के नए डीसीपी होंगे। अरुणाचल से आए सत्यवान गौतम डीसीपी पीसीआर, मिजोरम से आए गौरव त्यागी डीसीपी तो एडिशनल डीसीपी (वेस्ट) सचिन सिंघल और दिल्ली सरकार की एसीबी से आईं श्वेता सिंह चौहान दोनों ट्रैफिक के डीसीपी रहेंगे।

ठाणे के सरकारी कार्यक्रम में बजाया लता मंगेशकर वाला वंदे मातरम, एकनाथ शिंदे ने दी हिदायत

महानगर मेट्रो ब्यूरो

ठाणे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के ऑफिशियल वर्जन की जगह लता मंगेशकर का गाया हुआ हिंदी गाना बजाया गया। चार मिनट के इस गाने के दौरान डिप्टी सीएम खड़े तो हुए, मगर असहज नजर आए। उन्होंने राष्ट्रगीत गाने के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया मगर बाद में भाषण के दौरान नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आयोजकों से सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही, यह पक्का करने को कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का ऑफिशियल वर्जन ही बजाया जाए। उन्होंने इस चूक के लिए माफी भी मांगी।

वंदे मातरम पर क्यों मचा घमासान

बता दें कि शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। इसके बाद गायकों ने 'वंदे मातरम' का गायन शुरू किया। बताया गया कि कांग्रेस की ओर से इस मौके पर गीत के केवल पहले दो अंतरे गाने की बात कही गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान गायकों ने 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाना जारी रखा। इसी दौरान कथित तौर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा किया और बाद में गायकों से भी बात की। आरोप है कि उन्होंने गायकों को आगे गाने से रुकने के लिए कहा। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने वंदे मातरम को लेकर मचे सियासी धमासान, महाराष्ट्र के धार्मिक स्वतंत्रता कानून और भारत के निर्वाचन आयोग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवसेना राष्ट्रवाद और देशभक्ति की विचारधारा में विश्वास करती है और पार्टी के हर कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस बयान का समर्थन करते हुए, जिसमें उन्होंने कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम से करने की बात कही थी, संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना एक राष्ट्रवादी संगठन है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण गायन के साथ होगी। यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम पूरा गाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अगर यह ग्राउंड भी गया तो फुटबॉल सितारे कहां से मिलेंगे?BMC के फैसले से खिलाड़ी निराश

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। बांद्रा स्थित ऐतिहासिक नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर बनाने की बीएमसी की योजना को हरी झंडी मिल गई है. इस फैसले से स्थानीय खिलाड़ियों, रेफरी और फुटबॉल प्रेमियों में गहरा आक्रोश है. उनका कहना है कि खेल मैदान छिनने से भारतीय फुटबॉल का भविष्य और ऐतिहासिक पहचान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे. मुंबई के बांद्रा स्थित ऐतिहासिक नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने के प्रस्ताव को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के फैसले के बाद खिलाड़ियों, रेफरी और फुटबॉल प्रेमियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि अगर यह मैदान भी खत्म हो गया तो मुंबई में फुटबॉल का भविष्य संकट में पड़ जाएगा. मैदान पर रोज अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि मुंबई में पहले ही फुटबॉल के लिए बहुत कम मैदान बचे हैं. ऐसे में नेवल डिसूजा ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलना खेल और खिलाड़ियों, दोनों के लिए बड़ा झटका है. खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें इस फैसले की जानकारी हाल ही में मिली और इसके बाद से फुटबॉल समुदाय में निराशा का माहौल है. उनका कहना है कि यह मैदान सिर्फ एक खेल परिसर नहीं, बल्कि सैकड़ों खिलाड़ियों के सपनों का केंद्र है. फुटबॉल खिलाड़ियों ने बताया कि कई दिनों से इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था. लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और याचिका दायर कर मैदान को बचाने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं. खिलाड़ियों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से इस मैदान पर खेल रहे हैं. उनके मुताबिक, यह मैदान बच्चों और युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है. यदि यह मैदान समाप्त हो गया तो नई पीढ़ी के लिए फुटबॉल में आगे बढ़ने के अवसर भी सीमित हो जाएंगे. फुटबॉल प्रेमियों ने कहा कि नेवल डिसूजा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय फुटबॉल के गौरव का प्रतीक हैं. नेवल डिसूजा पहले भारतीय फुटबॉलर थे, जिन्होंने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोलों की हैट्रिक लगाई थी. खिलाड़ियों का कहना है कि यदि यह मैदान खत्म हो गया तो सिर्फ एक खेल मैदान नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉल की एक पहचान भी खत्म हो जाएगी.खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि उनके पास अभ्यास के लिए बहुत कम विकल्प हैं.

महानगर मेट्रो

भीनमाल उपजिला अस्पताल में PMO से मारपीटः आरोपी गिरफ्तारी की मांग

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भीनमाल (मुकेश सोलंकी)। शहर के उपजिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. नेमीचंद संघवी के साथ एक व्यक्ति द्वारा मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने की घटना से चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने आरोपी वकील की तत्काल गिरफ्तारी और अस्पताल में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, घटना 18 अगस्त सुबह करीब 10 बजे की है, जब PMO डॉ. नेमीचंद संघवी अपने कक्ष में मरीजों का इलाज कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी कमलेश कुमार अस्पताल के एक संविदा कर्मचारी के मानदेय (वेतन) के सिलसिले में कमरे में दाखिल हुआ। कर्मचारी के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ. संघवी ने नियमानुसार मानदेय जारी करने में असमर्थता जताई । इसी बात से उग्र होकर कमलेश कुमार ने डॉ. संघवी का कॉलर पकड़ लिया, गाली-गलौज की और मारपीट की कोशिश की। आरोपी ने टेबल पर रखी नेमप्लेट उखाड़कर फेंक दी। मौके पर मौजूद अन्य डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने बीच-बचाव कर मामले को संभाला। पूरी घटना अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के तुरंत बाद थाने में नामजद FIR दर्ज कराई गई।? IMA पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे रहने वाले चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ इस प्रकार की हिंसा से कर्मचारियों में डर का माहौल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो संपूर्ण चिकित्सा समुदाय कार्य बहिष्कार (हड़ताल) जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर होगा । प्रदर्शन के दौरान ढ्ढरूअध्यक्ष डॉ. हिम्मत शर्मा, डॉ. प्रेमराज परमार, डॉ. भूपेंद्र चौधरी, BCMO डॉ. दिनेश जाम्भानी, डॉ. रमेश देवासी, डॉ. बाबूलाल चौधरी, डॉ. नेमीचंद संघवी, डॉ. भगवानाराम जांगिड़, डॉ. रवि परमार, डॉ. अक्षय बोहरा, डॉ. विनोद कुमार वारडे, नरेंद्र सिंह गोहिल, संजीव माथुर, डॉ. जुगमलराम चौधरी, डॉ. सुरेश विश्नोई, डॉ. अनिल बिश्नोई, ललित कुमार, जितेंद्र कुमार, भिखाराम सहित भारी संख्या में नर्सिंग व अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहा।

शिनोर की चेतनाबेन पटेल को मुख्यमंत्री के हाथों वडोदरा ज़ोन का राज्य-स्तरीय माता यशोदा अवॉर्ड मिला

महानगर मेट्रो ब्यूरो

वडोदरा। आज, 15 अगस्त को, शिनोर तालुका की सबसे अच्छी मुख्य सेविका के तौर पर राज्य-स्तरीय माता यशोदा अवॉर्ड पाने वाली चेतनाबेन घनश्यामभाई पटेल को वडोदरा जिला-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में डिप्टी मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सम्मानित किया और सम्मान पत्र दिया। शिनोर तालुका के टिंबरवा गांव की रहने वाली चेतनाबेन घनश्यामभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 7 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने घर पर 17 साल की सेवा के बाद सबसे अच्छी हेड नर्स के तौर पर उनकी बेहतरीन सेवा के लिए राज्य-स्तरीय माता यशोदा अवॉर्ड, एक यादगार निशानी और 61000 रुपये का चेक दिया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के तहत हेड नर्स के तौर पर उनकी बेहतरीन सर्विस के लिए उन्हें सरकार ने सम्मानित भी किया था। और अभी वे शिनोर तालुका में सुपरवाइज़र के तौर पर बेहतरीन सर्विस दे रही हैं। और उनके पास इंचार्ज CDPO का चार्ज भी है।

रानपुर के खास गांव में अलाव रोड पर एक खेत के शेड के पास मेटल के तार से करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नानिवावाड़ी। गांव के दोनों युवकों की बिजली के शॉर्ट सर्किट से मौत ने परिवार को तबाह कर दिया हैः दो बेटों के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया, जबकि एक बेटी 11 साल की उम्र में नोटरी बन गई बोटाद जिले के रानपुर तालुका में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। रानपुर तालुका के नानिवावाड़ी गांव के दो युवकों की रानपुर के खास गांव में अलाव रोड पर एक खेत के शेड के पास मेटल के तार से करंट लगने से मौत हो गई। रानपुर तालुका के नानिवावाड़ी गांव के दो युवकों की चौंकाने वाली मौत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जब ये दोनों युवक शॉर्टकट लेने के लिए खेत से गुजरे, तो खेत के शेड के पास रखे खुले मेटल के तार से करंट लग गया। दोनों युवकों की मौत हो गई। जब लोगों को पूरी घटना का पता चला, तो लोग मौके पर पहुंचे और दोनों मृतकों को रानपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, नानीवावडी गांव के दोनों युवक विजयभाई नाजाभाई चावड़ा और नानजीभाई धनजीभाई पिपलिया, रानपुर तालुका के खास गांव के बाहरी इलाके में अलवना रोड पर खेत से शॉर्टकट रोड से गुजर रहे थे।

राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दें, तब कांग्रेस में शामिल होऊंगा

पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले की वजह खुलकर आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों को बताया है, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में किया था। हालांकि, भाजपा ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

पूनावाला ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को कोई वेतन नहीं देते, जबकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे मकान किराया आदि का भुगतान करना होता है। उन्होंने कहा, मेरा मकान मालिक घर इसलिए मुफ्त में नहीं दे देगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं। वहां हर महीने की 1 तारीख को किराया मांगता है। उन्होंने जोड़ा कि किसी राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना नौकरी नहीं है, बल्कि यह विचारधारा, व्यक्ति या संगठन के प्रति प्रेम का परिणाम होता है। उन्होंने बताया कि वह 2024 से ही इस्तीफे पर विचार कर रहे थे और इस दौरान कई नेताओं ने उनसे संपर्क भी साधा था।

कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर पूनावाला ने भले ही सीधे इंकार किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो अवास्तविक लगती हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में तभी शामिल हो सकते हैं, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दिया जाए और नेहरू के कार्यों के लिए माफी मांगी जाए। खास बात यह है कि पूनावाला स्वयं 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वैचारिक निष्ठा दिखाकर कहा कि पीएम मोदी से बड़ा नेता इस देश में न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय भारत की सबसे अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद वह किसी अन्य पार्टी से जुड़ने के बारे में नहीं सोचते। उनके त्याग पत्र में भी आर्थिक मजबूरियों का हवाला देकर मोदी जी के विजन के समर्थन की बात कही गई है।

हरियाणा में अग्निवीरों को तोहफा : 6 सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण

गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने सेना से लौटे अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है, इसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से लागू होगी, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सम्मान देना और उनके लिए नई राहें खोलना है। सबसे बड़ा लाभ पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्य जीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक सहित छह महत्वपूर्ण पदों पर मिलेगा, जहाँ अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), अन्य अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), बीसी–ए (3 प्रतिशत), बीसी–बी (2 प्रतिशत), ईडब्ल्यूएस (2प्रतिशत) और अनारक्षित श्रेणियों (9 प्रतिशत) के लिए कोटा निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य ग्रुप–सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप–बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं पुलिस कांस्टेबल और अन्य संबंधित पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से उन्हें छूट दी जाएगी। ग्रुप–सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही, सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विशेषज्ञता वाले पदों पर कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट प्राप्त होगी। हालांकि, इन सभी छूटों के बावजूद, विज्ञापित पद के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा देना पूर्व अग्निवीरों के लिए अनिवार्य रहेगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी इन दिशा–निर्देशों ने सरकार के पुराने आदेशों को रद्द किया है, इससे अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एक सुव्यवस्थित और प्राथमिकता आधारित प्रवेश मिल सकेगा।

डीजेबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

-वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की शृंखला उजागर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ व पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी संस्थाओं और कंपनियों के मालिकों नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरर एवं पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी प्रमुख एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त विक्रमजीत सिंह के बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां एफआईआर के बाद की गईं थीं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पीएस भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटीडी में पंजीकृत है। जांच में सामने आया कि एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी शर्तों और नियमों में जानबूझकर फेरबदल किया गया था। टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए और एक खास निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी 'मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित पायलट स्टडी को पूरा न करना, तकनीकी मापदंडों में बदलाव और उपचारित पानी के जरुरी मानकों को हटाना जैसी अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि टेंडर की शर्तें तय करने और संशोधन जारी करने में निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित साठगांठ थी, ताकि टेंडर केवल पसंदीदा कंपनी को ही मिले। वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की पूरी श्रृंखला उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोटेक कंपनी से जुड़ी संस्थाओं से फंड नागेंद्र यादव की प्रोप्राइटरशिप फर्म 'ए एन एंटरप्राइजेस और 'सृजनहार के जरिये हस्तांतरित किया गया। इस माध्यम से तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी गई, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। इन सभी दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के बाद एसीबी ने 18 अगस्त 2026 को छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच एजेंसियां अपराध की पूरी कमाई और इस साजिश में शामिल अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।

अखिलेश चुनाव में हार से बचने कांग्रेस को 300 सीटें देने का बना रहे प्लान

–बीजेपी और एनडीए सहयोगियों ने सपा प्रमुख पर किया जोरदार हमला

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव बीजेपी और एनडीए सहयोगियों- आरएलडी, अपना दल और सुभासपा और निषाद पार्टी पर हमलावर हैं। इस बीच अब बीजेपी ने सपा प्रमुख पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश चुनाव में हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस को करीब 300 सीटें देने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा अपना दल नेता आशीष पटेल ने भी सपा पर निशाना साधा है।

बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश के पारिवारिक विवाद ने समाजवादी पार्टी की गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, इसलिए सपा कांग्रेस को करीब 300 सीटें सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि हार का मेडल राहुल गांधी के सिर बंधे और अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाएं।

इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए सूत्रों के हवाले से एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला साझा किया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी पीडीए के दबाव में रालोद को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना बना रही है। अखिलेश ने कहा था कि यह योजना पीडीए की जनसंख्या अनुपात से बहुत कम है और पूरी तरह विफल साबित होगी।

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा-परीक्षा घपलों, फर्जी मुकदमों, बुलडोजर कार्रवाई और 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित करने जैसी नीतियों से जनता त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना लाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने और संविधान बदलने की साजिश करने वालों को जनता नकार चुकी है। उन्होंने नारा दिया कि आज हर जन कह रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए।

वहीं, अखिलेश के एनडीए के सीट बंटवारा फॉर्मूले पर अपना दल ने भी पलटवार किया। अपना दल नेता आशीष पटेल ने सपा प्रमुख के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती है। वह जमीन पर जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करते हैं। पटेल ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और इसी हकीकत से परेशान होकर सपा नेता दूसरों के शब्दों को अफवाह बताते-बताते खुद अफवाहों के वाहक बन रहे हैं।

सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके : रेणुका

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, वंदे मातरम विवाद और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल किए। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय को क्लीन चिट देने पर कहा कि ये पहले ही अपेक्षित था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों को कुर्बान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हमें पहले से पता था कि यही होने वाला है। छोटे–मोटों को कुर्बान कर देंगे और चंपत राय को बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके। ये भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से खिलवाड़ करेंगे तो ये बच जाएंगे। उनका श्राप इनको ही लगा है। बता दें मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने 27 जून को अपने–अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंदिर में दान प्रबंधन और संग्रह से संबंधित जांच के लिए एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मातरम के पूरे गीत को राजनीतिक और हिंदू–मुस्लिम से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस समय जो माहौल था, उस कारण से फैसला हुआ था। आज ये लोग किस कारण से कर रहे हैं, वही जानें और भगवान जाने। वैसे तो भगवान राम भी इनसे हटकर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि एक लोकतंत्र में हम कोई हाथ–ज्योतिषी बनकर नहीं कह सकते हैं।

सीएम विजय का ऐलानः हर विधायक को मिलेगी नई कार

विधायकों की मांग पर टीवीके सरकार का फैसला, क्षेत्र में दौरे और विकास कार्यों की निगरानी में मिलेगी मदद

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में रहना जरूरी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वाहन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सरकार का यह फैसला विधानसभा में विधायकों के लिए वाहनों और जरूरी लॉजिस्टिक्स की सुविधा का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है। वीसीके विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में कहा था कि यदि विधायकों को जरूरी संसाधन और वाहन उपलब्ध नहीं होंगे तो वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री विजय ने विधायक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों के लिए नई कार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहन सुविधा मिलने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और जनता से सीधे संवाद के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

जनता से संपर्क में आसानी होगी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार की ओर से सभी विधायकों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आने-जाने वाले विधायकों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में तेजी ला सकेंगे। विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में अपने क्षेत्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए वाहनों को जरूरी सुविधा बताया था। उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री विजय द्वारा लिया गया यह फैसला सरकार और विधायकों के बीच बुनियादी संसाधनों को लेकर उठाए गए मुद्दे के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

आँख की रोशनी गायब, शरीर में छर्रों का दद... लेकिन दीपके ने नहीं ली कोई खबर

-संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों का दर्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन घटना में पैलेट गन के छर्रे लगने से घायल हुए छात्रों के जख्म अभी भी ताजा हैं। पीड़ितों को इस बात की टीस ज्यादा है कि जिस कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया था, वह अब उनका हाल भी नहीं पूछ रही है।

नजफगढ़ के छात्र साहिल लोचव की दूसरी सर्जरी के बावजूद दाईं आंख की रोशनी वापस नहीं लौट सकी है। 19 वर्षीय साहिल की आंख में पैलेट के छर्रे लगने से कॉर्निया में छेद हुआ था। उसकी मां ज्योति बताती हैं कि 20 जुलाई की घटना में साहिल की आंख और हाथ में छर्रे लगे थे, जिसमें से सभी अब तक नहीं निकाले जा सके हैं। इससे उसका एक हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में आंख की सर्जरी और बाद में लेंस डालने के बावजूद रोशनी नहीं लौटी है। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती है।

वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी इरशाद मंसूरी के चेहरे, आंख के पास, छाती और शरीर के कई हिस्सों में पैलेट गन के करीब 40 छर्रे लगे थे। 21 जुलाई को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कर कुछ छर्रे निकाले गए, लेकिन कई अभी भी शरीर में मौजूद हैं। गुरुग्राम की कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत इरशाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं और घाव नहीं भरने के कारण ड्यूटी जॉइन नहीं कर सके हैं। बिहार के 25 वर्षीय छात्र प्रशांत के हाथ, छाती और कमर में पैलेट के छर्रे लगे थे, जिससे उनका दायां हाथ कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गया था। डॉक्टरों ने कुछ छर्रे निकाले, लेकिन कई छोटे छर्रे मांसपेशियों में गहराई तक धंसे हैं, जिन्हें निकालने से और अधिक घाव होने का डर है। प्रशांत अब नौकरी की तैयारी करते हुए भी पहले जैसा सामान्य महसूस नहीं कर रहे हैं। साहिल की मां और प्रशांत दोनों ने बताया कि घटना के बाद से सीजेपी की तरफ से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जख्मी प्रदर्शनकारियों में अब यह कड़वाहट साफ दिखती है कि राजनीतिक दल ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है।

चाणोद के पवित्र मंदिर में शीतला के साथ नर्मदा में डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

चाणोद। मशहूर मल्हारराव घाट पर शीतला माता की पूजा करने के बाद भक्तों ने खुद को धन्य महसूस किया आज शीतला सातम के मौके पर डभोई तालुका के चाणोद के पवित्र मंदिर के स्नान घाट पर भक्तों की भीड़ देखी गई। हिंदू धर्म में शीतला सातम पर ठंडा खाना खाने की महिमा बताई गई है। शीतला सातम के दिन घर का चूल्हा नहीं जलाया जाता। पूजा करते हैं और ढांढा रखते हैं। रिसर्च बहनें छठ के दिन खाना बनाती हैं, वड़ा पूरी दूध बसुदी श्रीखंड वहीदा शहीद की डिश बनाती हैं। रात में चूल्हे और रसोई को पानी से धोकर ठंडा और साफ किया जाता है और पूजा की जाती है। दीये जलाते हैं। फिर अगले दिन गैस स्टोव और अंगीठी नहीं जलाई जाती। इस दिन, यानी शीतला के साथ, उस दिन बनी स्वादिष्ट डिश का ठंडा खाना हेल्दी होता है। शीतला सतम की सुबह लोग नई नर्मदा नदी में नहाने जाते हैं। चाणोद और आस-पास के इलाकों से गांव के लोग नर्मदा में नहाने और मां की पूजा करने के लिए आते हैं।

महानगर मेट्रो
www.mahanagarmetro.com
अहमदाबाद, (गुरुवार)
20 अगस्त 2026

सोने-चांदी में नरमी

मुम्बई ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी में तेज गिरावट रही। ये गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते आई है। सुबह सोने के वायदा भाव में 362 रुपये जबकि चांदी में 2,418 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड का 19 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना रहा। हालांकि, फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम होने के कारण सोना और चांदी के लिए एक सकारात्मक कारक बना हुआ है, जो भविष्य में कीमतों को सहारा दे सकता है।वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर, सोना 4,410 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था जबकि चांदी 63 प्रति औंस के करीब थी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, सोने के वायदा भाव 1,54,200 रुपये के स्तर पर थे जबकि चांदी के भाव करीब 2,30,250 के आसपास थे। एमसीएक्स पर सोने के अक्टूबर अनुबंध की शुरुआत 362 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,900 पर हुई। इसका पिछला बंद भाव 1,54,262 रुपये था। दिन के कारोबार के दौरान, यह अनुबुंध 69 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,193 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसने दिन में कीमतें 1,53,900 रुपये के निचला स्तर और 1,54,326 के उच्च स्तर पर पहुंची। इस साल सोना 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। वहीं चांदी के सितंबर अनुबंध की भी कमजोर शुरुआत रही उसमें 2,418 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई और यह 2,30,001 पर खुली। इसका पिछला बंद भाव 2,32,419 रुपये था। कारोबार के समय यह अनुबंध् 2,181 की गिरावट के साथ ही 2,30,238 रुपये पर था, जिसने दिन के दौरान 2,29,666 रुपये का निचला और 2,30,528 रुपये का उच्च स्तर हासिल किया। चांदी इस साल 4,20,048 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंची। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोने के वायदा भाव 4,391.40 डॉलर प्रति औंस पर खुले, जो अपने पिछले बंद भाव 4,420.60 से कम थे। कारोबार के दौरान यह 11.20 रुपये की गिरावट के साथ 4,409.40 प्रति औंस पर थे। इस साल सोने ने 5,586.20 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर देखा। इसी तरह, कॉमैक्स पर चांदी के वायदा भाव 63.42 डॉलर पर खुले, जो पिछले बंद भाव 64.03 डॉलर से नीचे था।

बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह

लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मिल रहे मजबूत संकेत

नई दिल्ली,। बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने जा रहे हैं। कंपनी के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है। 17 अगस्त को शेयर आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की नजर लिस्टिंग पर है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बुधवार सुबह शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 133 रुपए चल रहा था। कंपनी ने आईपीओ में शेयर का ऊपरी मूल्य बैंड 285 रुपए तय किया था। इस हिसाब से संभावित लिस्टिंग कीमत करीब 418 रुपए होती है यानी इश्यू मूल्य के मुकाबले करीब 46.67 फीसदी प्रीमियम पर शेयर सूचीबद्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेत होता है और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।बेहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 301.62 करोड़ रुपए था। इसमें 93 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए गए, जबकि 208.62 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 271 से 285 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। निवेशकों को न्यूनतम 52 शेयरों के लिए आवेदन करना था। ऊपरी मूल्य बैंड के आधार पर खुदरा निवेशकों का न्यूनतम निवेश 14,820 रुपए था। बता दें कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। यह लौह और इस्पात से जुड़े उत्पादों के अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है। इसके उत्पादों में मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, फोर्जिंग इंगोट्स और फोर्ज्ड शाफ्ट शामिल हैं।31 मार्च 2026 तक कंपनी के ग्राहक आधार में भारत और विदेशों के 1,825 ग्राहक शामिल थे। इसकी विनिर्माण इकाइयां पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में हैं। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास करीब 178.57 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग के दौरान ग्रे मार्केट में दिख रहा उत्साह कितना बरकरार रहता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 325, निफ्टी 76 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। वहीं गत दिवस भी ये गिरा था। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेज की कीमतें बढ़ने से भी घरेलू बाजार पर दबाव पड़ा है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।

आज कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईटीसी के शेयर गिरे हालांकि, कुछ आईटी शेयरों ने बाजार की इस गिरावट को थामा।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 325.78 अंक की गिरावट के साथ ही 76,909.68 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 76.60 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,078.30 अंकों पर बंद हुआ।

बाजार की व्यापक स्थिति कमजोर रही। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से केवल 8 के शेयर ही लाभ के साथ बंद हुए। वहीं 21 अन्य में गिरावट रही। इसी तरह, निफ्टी की 50 कंपनियों में से 34 के शेयर नीये आये जबकि केवल 16 में तेजी दर्ज की गई।

सरकारी बिजली कंपनी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.00 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो सेंसेक्स के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके विपरीत, आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक का शेयर 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा

गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस , एलएंडटी , आईटीसी , हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि रहे जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा , टाइटन , टीसीएस , इन्फोसिस और ट्रेंट के शेयरों में तेजी रही। बजाज फिनसर्व के शेयर बिना किसी बदलाव के सपाट रहे।

इससे पहले आज सुबह

सेंसेक्स करीब 94.57 अंक की गिरावट के साथ 77,140.89 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि 50 शेयरों वाल एनएसई निफ्टी50 भी 38.30 अंक फिसलकर 24,116.60 पर पहुंच गया।वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट 1.33 फीसदी और एसएंडपी 500 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी लगभग 0.2 फीसदी नीचे बंद हुआ।दूसरी ओर एशियाई बाजारों में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा हुआ था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 4.2 फीसदी तक गिर गया।

कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी

मुम्बई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की बढ़ती कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में अभी पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की जगह बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ किसी भ्री तरह से बातचीत करने से इंकार करने के बाद से ही करने के बयान के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतें 91 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। आज सुबह कच्चा तेल 38 सेंट चढ़कर 91.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि डब्लयूटीआई क्रूड 45 सेंट की बढ़त के साथ ही 85.30 डॉलर प्रति बैरल पर था। कच्चे तेल की कीमतों में आये इस उछाल से ईंधन की कीमतें बढ़ना तय है।

एक अनुमान के मुताबिक, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का नुकसान होता है।

वहीं देश में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। इसके साथ ही, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

बाल यौन शोषण सामग्री कानून का उल्लंघन, मेटा से बातचीत के बाद सरकार सख्त

नई दिल्ली।

अमेरिकी कंपनी मेटा के साथ सरकार की बातचीत के बाद बाल यौन शोषण सामग्री के मुद्दे पर कार्रवाई में तेजी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने साफ कर दिया है कि ऐसी सामग्री कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन होने पर 'सेफ हार्बर' का संरक्षण नहीं मिलेगा। 'सेफ हार्बर' एक कानूनी प्रावधान है जो इंटरनेट मध्यस्थों और सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा 'पोस्ट' की गई सामग्री के लिए कानूनी जिम्मेदारी या मुकदमों से बचाता है।सूत्रों ने बताया कि सरकार का मकसद 'सेंसरशिप' या किसी भी तरह से 'कवरेज' को सीमित करना नहीं है, बल्कि भारतीय कानूनों और नियमों का पालन तय करना और सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि संदेश पहुंच गया है। आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मेटा ने सीएसएएम पर बढ़ी हुई संवेदनशीलता और सावधानी दिखाई है और हालिया चर्चाओं के बाद सरकार को कंपनी द्वारा कुछ कार्रवाई होती दिख रही है। सूत्रों ने इस प्रतिक्रिया को 'महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय' बताया। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बातचीत में मेटा ने बताया कि उसके 'एल्गोरिदम' और प्रणालियां कैसे काम करती हैं।

एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना बंद- बॉन्ड बाजार पर दबाव, यील्ड में वृद्धि

नई दिल्ली,।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समय से पहले बंद होने से बॉन्ड बाजार पर, विशेषकर अल्पावधि बॉन्ड खंड पर दबाव बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 6.44 प्रतिशत से बढ़कर 6.46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

बीते दो कारोबारी सत्रों में पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड में करीब 10 आधार अंक की वृद्धि दर्ज की गई। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी 6.81 प्रतिशत से बढ़कर 6.83 प्रतिशत पर बंद हुई। डीलरों का अनुमान है कि अगस्त के अंत तक यह 6.85 प्रतिशत के करीब पहुंच सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई की योजना ने पहले अल्पावधि बॉन्ड को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की थी।

बाजार के जानकारों के अनुसार, कारोबारियों ने एफसीएनआर (बी) के तहत 3 से 5 साल की अवधि के लिए आने वाली जमा की उम्मीद में पांच वर्षीय बॉन्ड में बड़ी पोजीशन बनाई थीं। योजना के अचानक बंद होने से इन पोजीशन को समाप्त किया जा रहा है, जिससे कम अवधि वाले बॉन्ड खंड पर

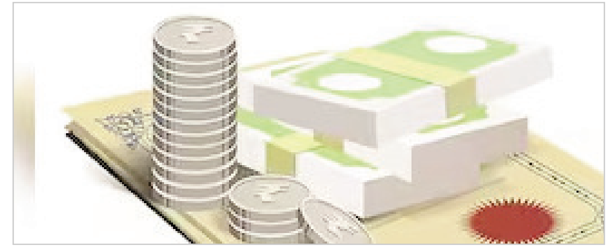

अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। प्राइमरी डीलरशिप के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, कारोबारियों ने 5 वर्षीय बॉन्ड में ज्यादा पोजीशन बनाई थीं और अब उन्हें खत्म किया जा रहा है। एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समाप्त होने के साथ ही, बाजार का ध्यान अब फिर से वैश्विक कारकों, विशेष तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों पर केंद्रित हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीएनआर (बी) सुविधा बॉन्ड बाजार के लिए एक सकारात्मक कारक थी और इसने बाजार को स्थिरता बनाए रखने में मदद की थी।

भारत में डीपटेक फंडिंग का बोलबाला, 11.4 अरब डॉलर का आंकड़ा पार

पिछले छह सालों में आया 85 फीसदी से ज्यादा निवेश

नई दिल्ली।

इंडियन वेंचर ऐंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डीपटेक सेक्टर में वर्ष 2015 से अब तक कुल 11.4 अरब डॉलर का भारी निवेश आया है। इस फंडिंग का 85 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा पिछले छह सालों में ही जुटाया गया है, जो देश के डीपटेक इकोसिस्टम के तेजी से परिपक्व होने और वाणिज्यिक सफलता की ओर बढ़ने का स्पष्ट संकेत देता है। आईवीसीए के आंकड़ों के मुताबिक डीपटेक सेक्टर में निवेश में अभूतपूर्व उछाल आया है। वर्ष 2025 फंडिंग के लिहाज से अब तक का सबसे सफल साल रहा, जब डीपटेक स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड 189 राउंड में 2.9 अरब डॉलर जुटाए। वर्ष 2026 में भी यह गति जारी है और कंपनियों ने 103 राउंड में लगभग 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है।

2021 के बाद से फंडिंग में आई यह तेजी साफ तौर पर दर्शाती है कि डीपटेक कंपनियां अब शुरुआती चरण से निकलकर वाणिज्यिक मजबूती की ओर अग्रसर हैं।

इस तेजी का प्रमाण हाल के उदाहरणों में देखा जा सकता है, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट का सफल लॉन्च और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेसा का 1.2 अरब डॉलर का फंडिंग राउंड, जिसने उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिलाया। 2015 से 2026 के बीच ब्लूम वेंचर्स (51 सौदे), स्पेशल इन्वेस्ट (50 सौदे) और एक्सेल इंडिया (48 सौदे) सबसे सक्रिय डीपटेक निवेशक रहे। इसी अवधि में, डीपटेक कंपनियों ने 61 सौदों के माध्यम से वेंचर ऋण के रूप में कुल 54.4 करोड़ डॉलर की पूंजी भी जुटाई। हालांकि, निवेश से बाहर निकलने (एक्जिट) के लिए विलय एवं अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा सेकंडरी बिक्री (56 फीसदी) ही देखने को मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 62 प्रतिशत फंडों ने एक्जिट की स्पष्टता को एक बड़ी चुनौती माना है।

आईपीओ भी एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए ग्रोथ-स्टेज कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है।

पिछले साल 18 बिकवाली सौदों से 60 करोड़ डॉलर मिले, जबकि 2024 में 7 एक्जिट से 15.2 करोड़ डॉलर जुटाए गए। डीपटेक स्टार्टअप वे उद्यम हैं जो नई वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित समाधान विकसित करते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस-टेक, रक्षा और एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नॉलजी और अन्य उन्नत क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं।

भारत का डीपटेक सेक्टर भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.57 पर बंद हुआ। वही गत दिवस रुपया 95.74 पर बंद हुआ। आज सबह रुपया 95.72 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 फीसद टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है।

ओपनएआई ने किशोरों के लिए शुरु किया नया चैटजीपीटी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की कर सकेंगे निगरानी

नई दिल्ली,।

ओपनएआई ने 13 से 17 साल की उम्र के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी सेवा शुरू की। कंपनी के मुताबिक इसमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अभिभावकों के नियंत्रण की सुविधा होगी यानी वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। यदि चैटजीपीटी के सिस्टम को शक होता है कि उपयोगकर्ता की उम्र 18 साल से कम है, तो यह नया फीचर अपने आप सक्रिय हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऐसे उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से किशोरों के लिए चैटजीपीटी अनुभव में रखा जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा तय की जा सके।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपनएआई ने कहा कि किशोरों के लिए चैटजीपीटी फीचर सीखने और सुरक्षा सुविधाओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य कक्षा के बाहर सक्रिय और सहयोगात्मक सीखने में मदद करना और एआई के ज्यादा सोच-समझ कर और उम्र के अनुरूप उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में ऐसी सामग्री से सुरक्षा शामिल है, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाने, हिंसा, खतरनाक गतिविधियों या किसी भी तरह की यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का चित्रण हो। ओपनएआई

इंडिया में स्ट्रैटजी और वैश्विक मामलों की प्रमुख ने यह जानकारी दी।

टाटा संस एजीएम स्थगित- जल्द होगा अगली बैठक का ऐलान

मुंबई।

टाटा संस को अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को उसकी सालाना आम बैठक (एजीएम) आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या (कोरम) पूरी न होने के कारण स्थगित की गई। कंपनी के 1917 में स्थापित होने के बाद से यह पहली बार है कि उसकी एजीएम न छूटी है और न ही स्थगित हुई है, जिससे समूह के नेतृत्व को लेकर पहले से बनी अनिश्चितता और बढ़ गई है।

एजीएम स्थगन का मुख्य कारण सर रतन टाटा ट्रस्ट्स (एसआरटीटी) पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा इस साल की शुरुआत में लगी रोक थी, जिससे इसके नामित निदेशकों की भागीदारी प्रभावित हुई। सूत्रों के अनुसार, टाटा संस का बोर्ड अब जल्द ही, संभवतः एक सप्ताह के भीतर, बैठक बुलाएगा।

इसमें स्थगित हुई एजीएम की नई तारीख तय होगी और मौजूदा कानूनी गतिरोध के समाधान पर वरिष्ठ विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

इस संभावित बैठक में चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन के 12 अगस्त के पत्र पर भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 20 फरवरी 2027 को अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए खुद को आगे नहीं रखने वाले है। हालांकि, एक सूत्र के मुताबिक, बोर्ड इस बैठक में अपनी पहले की राय दोहरा सकता है कि चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। मंगलवार को एजीएम के लिए चेयरमैन चंद्रशेखरन और कुछ बोर्ड सदस्य मुंबई में मौजूद थे, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा सहित कई अन्य निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए थे।

परंतु, कोरम पूरा न होने से बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद स्थगित कर दी गई।

डिजिटल भुगतान की बढ़त के बीच नगदी के प्रचलन में नहीं आई गिरावट

आरबीआई ने छह मूल्य वर्गों में सालाना 28 से 30 अरब बैंक नोटों की छपाई की

नई दिल्ली,।

डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच व्यक्तिगत लेन-देन में नकदी की हिस्सेदारी भले ही कम हो रही है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा दो अंकों की दर से लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि इससे न केवल भविष्य के लिए नकदी की मांग का अनुमान लगाना कठिन हो गया है बल्कि बैंक नोटों के उत्पादन एवं वितरण क्षमता के लिए आरबीआई की योजना भी जटिल होती जा रही है।

मुर्मू ने कहा कि पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाना क्रांतिकारी रहा है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा में कोई गिरावट नहीं आई है। ऐसा खास तौर पर ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में, कम आय वाले लोगों, बुजुर्गों और छोटे कारोबारियों के बीच देखा जा रहा है। मुर्मू ने बताया कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने छह मूल्य वर्गों में सालाना 28 से 30 अरब बैंक नोटों की छपाई की है और सालाना करीब 21 अरब बैंक नोटों का निपटान किया है। फिलहाल देश में 176 अरब बैंक नोट प्रचलन में हैं। इसके मुकाबले पिछले साल के आखिर में करीब 56 अरब डॉलर बिल और 30 अरब यूरो के बैंक नोट प्रचलन में थे।

उन्होंने कहा कि भारत में यह संख्या कुछ हद तक कम मूल्य वाले नोटों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से है। इसका मतलब साफ है कि समान मूल्य के लेनदेन के लिए ज्यादा नोटों का आदान-प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के 1 अरब पॉलिमर बैंक नोट लाने को मंजूरी दे दी है। अगर फील्ड ट्रायल और परिचालन संबंधी आकलन के नतीजे संतोषजनक रहे तो आरबीआइ वित्त वर्ष 2028 की शुरुआत से परीक्षण के आधार पर पॉलिमर बैंक नोटों को प्रचलन में लाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय बैंक ने पॉलिमर सबस्ट्रेट की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन आरबीआइ बड़े पैमाने पर जारी करने का फैसला लेने से पहले भारतीय जलवायु और उपयोग की परिस्थितियों में इन नोटों का परीक्षण करेगा। आरबीआई अपने वितरण नेटवर्क को अनुकूलित करके और बैंक नोट ब्रिगेट के निपटान के तरीके में सुधार के जरिये नकदी चक्र में कार्बन की मौजूदगी को कम करने के लिए भी काम कर रहा है।

मुर्मू ने कहा कि डिजिटल भुगतान में तेजी के बावजूद नकदी प्रबंधन केंद्रीय बैंकों के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी बनी हुई है।

इससे भौतिक मुद्रा में जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व का पता चलता है।

दुबई का कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हुआ

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई

नई दिल्ली,।

दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार ने 2026 की पहली छमाही में मजबूती दिखाई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद दुबई में वाणिज्यिक संपत्तियों के लेनदेन का मूल्य बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट लेनदेन का मूल्य सालाना आधार पर 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हो गया। सौदों की संख्या करीब 13 फीसदी बढ़कर 6,487 हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में लेनदेन का मूल्य करीब 200 फीसदी बढ़कर 15.81 अरब दिरहम हो गया। ऑफिस सेगमेंट में लेनदेन की संख्या भी सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़कर 2,571 हो गई। वहीं, ऑफिस की औसत कीमत 85 फीसदी बढ़कर 3,202 दिरहम प्रति वर्ग फुट पहुंच गई।

एनारॉक समूह में खुदरा और यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मुख्य कार्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रमुख कारोबारी जिलों और फ्री जोन में सीमित आपूर्ति के बीच ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग को दर्शाता है। खुदरा संपत्तियों के कारोबार में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई। लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 853 हो गई।

पालमपुर के पास में स्थित इन शानदार हिल स्टेशन को बनाएं डेस्टिनेशन पॉइंट, बिताएं सुकून के पल

बहुत कम लोग पालमपुर को हिल स्टेशन मानते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पालमपुर के आसपास में स्थित कुछ शानदार हिल स्टेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आप सुकून के कुछ पल बिताने के लिए पहुंच सकते हैं।

पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक फेमस और खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यह जगह अपनी खूबसूरती के अलावा हरे-भरे चाय के बागानों और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के लिए भी जाना जाता है। पालमपुर अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस शहर को बहुत कम लोग हिल स्टेशन मानते हैं। इसलिए लोग पालमपुर के आसपास हिल स्टेशनों की तलाश करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पालमपुर के आसपास में स्थित कुछ शानदार हिल स्टेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आप सुकून के कुछ पल बिताने के लिए पहुंच सकते हैं।

धर्मशाला

अगर आप भी पालमपुर के पास किसी शानदार हिल स्टेशन घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले धर्मशाला का रुख करते हैं। वहीं अगर आप धर्मशाला घूमने जा रहे हैं, तो यहां से करीब 5 किमी दूर स्थित मैक्लोडगंज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गर्मियों में यहां पर देश के कोने-कोने से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

मुख्य आकर्षण – भागसू वाटरफॉल, धर्मकोट, धर्मशाला टी गार्डन, बीर बिलिंग

समुद्र तल से करीब 2 हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह सबसे ज्यादा पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से पर्यटक यहां पर पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते हैं। यहां पर आप पहाड़ों में ट्रेकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग का शानदार लुत्फ उठा सकते हैं।

मुख्य आकर्षण – चोकलिंग मठ, गुनेहर वॉटरफॉल, बीर सनसेट पॉइंट, बरोट हिल स्टेशन

बरोट हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में स्थित छिपा खजाना माना जाता है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे बादलों से ढके पहाड़, देवदार के बड़े-बड़े पेड़, झील-झरने और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवाओं में लोग पार्टनर, परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।

मुख्य आकर्षण– बरोट मंदिर, लापस वॉटरफॉल, बाडा ग्रान ट्रेक, कुल्लू

कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत जिला और हिल स्टेशन है। बता दें कि यह मंडी-मनाली राजमार्ग पर पड़ता है। कुल्लू अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको घास के मैदान, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और झील-झरनों के लिए जाना जाता है। कई पर्यटक वीकेंड पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं।

मुख्य आकर्षण – फ्रेंडशिप पीक, नग्गर कैसल, भृगु झील

इतिहास, विरासत और हथकरघे की नगरी है चंदेरी

चंदेरी का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यह नगर विभिन्न राजवंशों— जैसे प्रतिहार, गुर्जर, सुल्तान, मुग़ल, बुंदेला और मराठा — के अधीन रहा है। यहां की वास्तुकला में हिन्दू, इस्लामी और जैन प्रभावों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

मध्य प्रदेश की मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर बसा चंदेरी (ष्द्धड्डद्वस्त्रद्गह्मद्ब) एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने भव्य किलों, प्राचीन स्मारकों, जैन मंदिरों और विश्वप्रसिद्ध चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर न केवल इतिहास प्रेमियों, बल्कि कला, संस्कृति और पारंपरिक वस्त्रों के शौकीनों के लिए भी एक आकर्षक पर्यटन स्थल है।

चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व

चंदेरी का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यह नगर विभिन्न राजवंशों— जैसे प्रतिहार, गुर्जर, सुल्तान, मुग़ल, बुंदेला और मराठा — के अधीन रहा है। यहां की वास्तुकला में हिन्दू, इस्लामी और जैन प्रभावों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

पारंपरिक व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण यह नगर व्यापार, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग, का एक बड़ा केंद्र रहा है।

प्रमुख दर्शनीय स्थल

1. चंदेरी किला

बंदरगढ़ पहाड़ी पर स्थित यह भव्य किला 13वीं शताब्दी में बना था और चंदेरी के इतिहास की रक्षा करता प्रतीत होता है। यहां से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। किले में कौशक महल नामक भव्य महल भी है, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर के समय में बनवाया गया था।

2. जौरी की मस्जिद और बड़ी मस्जिद

चंदेरी की मस्जिदें अपनी मुगलकालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था और ये आज भी अपनी भव्यता और शांति के लिए जानी जाती हैं।

3. कटी घोड़ी

यह दो स्तंभों पर खड़ी एक अनूठी संरचना है, जो देखने में एक घोड़े के कटे हिस्से जैसी प्रतीत होती है। यह चंदेरी की पहचान बन चुकी है।

4. जैन मंदिर और नालगिरी पर्वत

यहां प्राचीन जैन मंदिरों की श्रृंखला है और नालगिरी पर्वत पर स्थित विशाल जैन तीर्थ क्षेत्र एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है।

चंदेरी की साड़ियाँ

चंदेरी की पहचान सबसे अधिक उसकी चंदेरी साड़ियों से है। ये साड़ियाँ अपनी हल्के वजन, चमकदार कपड़े और पारंपरिक बूटियों के लिए प्रसिद्ध हैं। रेशम और सूती धागों से बनी ये साड़ियाँ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। चंदेरी शहर के विभिन्न बुनकर मोहल्लों में आज भी पारंपरिक हथकरघा तकनीक से इन साड़ियों का निर्माण होता है।

कैसे पहुँचे ?

निकटतम रेलवे स्टेशनः ललितपुर (36 किमी) और अशोकनगर (38 किमी)

निकटतम हवाई अड्डाः ग्वालियर (200 किमी) और भोपाल (215 किमी)

सड़क मार्गः चंदेरी झांसी, ललितपुर, शिवपुरी और सागर जैसे शहरों से सड़क द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

ठहरने की व्यवस्था

चंदेरी में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल भी हैं जो आरामदायक और सुविधाजनक ठहराव प्रदान करते हैं।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

चंदेरी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। सर्दियों में मौसम सुहावना रहता है और विरासत स्थलों की यात्रा अधिक सुखद होती है।

चंदेरी एक ऐसा नगर है जहां इतिहास की गलियों में कदम रखते ही समय ठहर जाता है। किले, महल, मस्जिदें, जैन मंदिर और हथकरघे की कला— यह सब मिलकर चंदेरी को एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। यदि आप भारतीय संस्कृति, शिल्प और इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं, तो चंदेरी की यात्रा अवश्य करें।

भीमबेटकाः जहां 30,000 साल पुराना इतिहास आज भी जीवंत है

भीमबेटका की गुफाएं करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। यहां की चट्टानों पर बने शैलचित्र प्रागैतिहासिक युग, मिजोलिथिक, नवपाषाण और ऐतिहासिक काल तक फैले हुए हैं।

भारत की धरती प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है, और मध्य प्रदेश का भीमबेटका (Bhimbetka) इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्थल न केवल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास, कला और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। भीमबेटका की गुफाएँ मानव सभ्यता की सबसे पुरानी झलकियों में से एक प्रस्तुत करती हैं।

भीमबेटका का इतिहास

भीमबेटका शैलाश्रय समूह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में रायसेन ज़िले में स्थित है। इसका नाम महाभारत के भीम पात्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान पांडवों के वनवास काल के दौरान उनका विश्राम स्थल रहा था।

भीमबेटका की गुफाएं करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों (UNESCO World Heritage Sites) में शामिल हैं। यहां की चट्टानों पर बने शैलचित्र प्रागैतिहासिक युग, मिजोलिथिक, नवपाषाण और ऐतिहासिक काल तक फैले हुए हैं।

शैलचित्रों की विशेषताएं

भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाने वाले चित्र मुख्यत : लाल, सफेद और कभी-कभी पीले और हरे रंग में बने हुए हैं। इन चित्रों में शिकारी, नर्तक, जानवर, युद्ध दृश्य, सामाजिक गतिविधियाँ और धार्मिक प्रतीक शामिल हैं। यह चित्र मानव जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, उनकी जीवनशैली और संस्कृति को उजागर करते हैं।

यहां करीब 750 गुफाएँ हैं, जिनमें से लगभग 15-20 को ही आम पर्यटकों के लिए खोला गया है। सबसे प्रसिद्ध गुफा है फ्रज्योति स्थलफ्र, जहाँ मानव आकृतियाँ नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं।

पर्यटक अनुभव

भीमबेटका आने वाले पर्यटक एक अनोखे अनुभव का आनंद लेते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और गुफाओं की जटिल कलाकृति एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जंगलों से घिरे हुए यह शैलाश्रय सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसे हुए हैं, जो खुद में एक रोमांचक यात्रा बन जाती है।

कैसे पहुँचे?

निकटतम हवाई अड्डाः भोपाल (45 किमी)

रेल मार्गः भोपाल रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी है।

सड़क मार्गः भोपाल से टैक्सी या बस के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है।

ठहरने की व्यवस्था

भोपाल शहर में पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के होटल उपलब्ध हैं — बजट से लेकर लक्ज़री तक। भीमबेटका में ठहरने की सुविधा नहीं है, अत : भोपाल में रुकना अधिक सुविधाजनक होता है।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

भीमबेटका की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम सुहावना और यात्रा के अनुकूल होता है।

भीमबेटका केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के उद्भव और विकास की कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यह उन यात्रियों के लिए एक जरूरी स्थल है, जो इतिहास, संस्कृति और कला में रुचि रखते हैं। एक बार भीमबेटका की यात्रा करना, जैसे समय की सुरंग में प्रवेश कर मानव विकास की प्राचीन यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखना है।

मिनी पहलगाम के नाम से फेमस है नॉर्थ बंगाल का माझीधुरा, प्रकृति प्रेमियों के लिए है स्वर्ग

दार्जिलिंग और दीघा बीच के अलावा हिमालय की तलहटी में स्थित माझीधुरा एक ऐसी हसीन जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह जगह अपनी खूबसूरती और शानदार नजारों के कारण मिनी पहलगाम के नाम से भी जाना जाता है।

हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ पश्चिम बंगाल एक बेहद खूबसूरत और प्रमुख राज्य है। यह राज्य बंगाल की खाड़ी के किनारे में स्थित दीघा, ताजपुर बीच या उदयपुर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ठीक उसी तरह हिमालय में स्थित सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के लिए भी जाना जाता है। दार्जिलिंग और दीघा बीच के अलावा हिमालय की तलहटी में स्थित माझीधुरा एक ऐसी हसीन जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह जगह अपनी खूबसूरती और शानदार नजारों के कारण मिनी पहलगाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको माझीधुरा की खासियत और यहां पर घूमने वाली कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

माझीधुरा

माझीधुरा दार्जिलिंग से करीब 11 किमी दूर पहाड़ी पर स्थित एक शांत और सुरम्य पहाड़ी गांव है। यह जगह दार्जिलिंग से 11 किमी दूर और सिलीगुड़ी से 74 किमी और पश्चिम बंगाल के मिरिक से करीब 7-8 किमी दूरी पर स्थित है।

क्यों फेमस है ये जगह

समुद्र तल से करीब 4 हजार से अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित माझीधुरा बंगाल का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। यहां पर आपको चारों ओर हरियाली, बादलों से ढके ऊंचे-ऊंचे पहाड़, चाय के बागान देखने को मिलेंगे।

माझीधुरा में अल्पाइन के बड़े-बड़े पेड़, घास के मैदान और झील-झरनों के कारण इस जगह को मिनी पहलगाम के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यह पहाड़ी गांव अपनी स्थानीय परंपरा के लिए भी फेमस है। माझीधुरा को पशु-पक्षियों का घर भी कहा जाता है।

पर्यटकों के लिए है खास

दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और मिरिक जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जबकि माझीधुरा शांत और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पर न तो गाड़ी हॉर्न और न होटलों में भीड़ दिखाई देगी। यहां पर आपको सिर्फ प्रकृति और ठंडी-ठंडी हवाओं की आवाजें सुनाई देंगी।

माझीधुरा अपनी खूबसूरती के अलावा एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। यहां पर सुकून के पल बिताने के लिए पर्यटक कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाईकिंग का लुत्फ उठाते हैं। माझीधुरा में गर्मी से लेकर सर्दी तक में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे में पहली बार झटके 7 विकेट

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान की टेस्ट टीम तो इंग्लैंड के दौरे पर है. मगर उस टीम से बाहर चल रहे शाहीन शाह अफरीदी के पुराने तेवर लगता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में लौट चुके हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में जब मैटर सबसे बड़ा दिखा, तो शाहीन वहां शहंशाह की तरह अपनी टीम के लिए खड़े दिखे. उन्होंने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में ना सिर्फ हैट्रिक ली है, बल्कि गेंद से ऐसी आग बरसाई कि वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन ही कर डाला. नतीजा, ये हुआ कि उनकी टीम टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई.

शाहीन अफरीदी ने टीम को फ्रंट से किया लीड

नेशनल चैंपियंस कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन की टीमें आमने-सामने थी. इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान थे.उनकी टीम ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 340 रन बनाए. मतलब बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था. अब बारी गेंदबाजों की थी. स्ट्राइक गेंदबाज होने के नाते कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इस काम में अपनी टीम पाकिस्तान गोल्ड को फ्रंट से लीड किया.

टीम को बनाया चैंपियन

शाहीन ने गेंद से उगली आग!

पाकिस्तान ग्रीन के सामने पहले से ही 341 रन जैसा बड़ा लक्ष्य था. मगर उसे और भी विकराल बना दिया शाहीन शाह अफरीदी की आग उगलती और विरोधी बल्लेबाजों से सवाल पूछती शाहीन की गेंदों ने. पाकिस्तान ग्रीन के बल्लेबाजों के पास शाहीन की गेंदों का कोई जवाब नहीं था. ऐसे में वो बस एक-एक दम उनके आगे दम तोड़ते दिखे.

शाहीन अफ्रीदी की हैट्रिक

शाहीन अफरीदी की हैट्रिक में पाकिस्तान ग्रीन के जो बल्लेबाज फंसे, उनमें मेहरान मुमताज, सलमान मिर्जा और मोहम्मद हसनेन का विकेट शामिल रहा. शाहीन के इस हैट्रिक के साथ ही पाकिस्तान ग्रीन की पारी का भी अंत हो गया.

टीम को चैंपियन बनाकर हीरो बने शाहीन अफरीदी

शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में अपने वनडे यानी लिस्ट ए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8.3 ओवर में 36 रन देकर कुल 7 विकेट लिए और अपनी टीम पाकिस्तान गोल्ड को चैंपियन बनाया. 341 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ग्रीन पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकी और 37.3 ओवर में सिर्फ 239 रन पर ऑल आउट हो गई. इस तरह पाकिस्तान गोल्ड ने फाइनल मुकाबला 101 रन के बड़े अंतर से जीत लिया, जिसके हीरो खुद उसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बने.

पहले 6 ओवर में 3 विकेट, फिर अगली 15 गेंदों में 4 विकेट

शाहीन अफरीदी ने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में डाले अपने पहले 6 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. लेकिन, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ग्रीन का और बुरा हाल किया. वो और भी ज्यादा मानो खतरनाक हो गए. उन्होंने अगली 15 गेंदों पर 7 रन देकर 4 और विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल रही.

संक्षिप्त समाचार

जब गोल्ड जीतने पर राष्ट्रगान बजा, वह पल शानदार था

एरोबिक जिम्नास्टिक्स में इतिहास रचने के बाद अरिहा ने साझा किए अनुभव

मुंबई, एजेंसी। भारतीय एयरोबिक जिम्नास्ट अरिहा पंगमबम ने कुछ हफ्तों पहले एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था, जिसके साथ वह एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। फिलीपींस में हुए फाइनल में उन्होंने 19.100 अंक हासिल किए, जिसमें आर्टिस्ट्री (कलात्मकता) में 8.650, एग्जीक्यूशन (प्रदर्शन) में 7.600 और डिफिकल्टी (कठिनाई) में 2.850 अंक शामिल थे। इस उपलब्धि के बाद अरिहा ने कहा, जब मुझे यह गोल्ड मेडल मिला, तो वह पल बहुत शानदार था। मैं इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जब मैंने पोडियम पर अपने देश का राष्ट्रगान बजते हुए सुना, तो उस पल मुझे गर्व भी महसूस हुआ क्योंकि मैं कुछ हासिल कर पाई थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए। वह बहुत शानदार अनुभव था और मैं उस समय बहुत खुश थी।

22 वर्षीय जिम्नास्ट ने कहा, हम डबल फ्लेक्स फ्लोर, यानी लकड़ी का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं। भारत में उत्तराखंड में एक फ्लोर है जो हमें नेशनल गेम्स के दौरान मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से, न सिर्फ मैं, बल्कि पूरे भारत के ज्यादातर जिम्नास्ट उस पर ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए। हम आमतौर पर रबड़ इंटरलॉकिंग मैट पर ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए सिर्फ एक दिन में तालमेल बिठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रतियोगिता से पहले हमें खुद को ढालने के लिए एक दिन की पोडियम ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हममें से ज्यादातर जिम्नास्ट को मुश्किल होती है, क्योंकि हमें उस फ्लोर पर कभी ठीक से ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला। यही वह मुश्किल थी जिसका हमने सामना किया।

World Championship

बिना मैच खेले ही प्री क्वार्टरफाइनल में पहुंचे सात्विक-चिराग

नई दिल्ली, एजेंसी। सात्विक-चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस भारतीय जोड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू नहीं किया है। सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सात्विक-चिराग को शुरुआती मैच में वॉकओवर मिला था।

पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी विश्व चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीत चुकी है। पहले दौर में बाई मिलने के बाद सात्विक-चिराग को दूसरे दौर में स्कॉटलैंड के एलेक्सजेंडर डुन और एडम प्रिंजल का सामना करना था। हालांकि, स्कॉटलैंड की जोड़ी आखिरी मिनटों में हट गई जिससे सात्विक-चिराग बिना मैच खेले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए।

इंडिया-श्रीलंका टेस्ट

मानव सुथार-पडिकल बने जीत के हीरो

सीरीज में 1-0 की बढ़त

गॉल में टीम इंडिया की महाजीत

भारत 600वें टेस्ट में जीता

श्रीलंका 165 रन से हारा

मानव सुथार ने मैच में 10 विकेट लिए

देवदत्त पडिक्कल का शतक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर अपना 600वां टेस्ट जीत लिया है। गॉल में 372 रन के टारगेट का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ऑलआउट हो गई। पहले टेस्ट में भारत की जीत के हीरो मानव सुथार रहे। उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। राजस्थान के सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर श्रीलंका की पारी समेट दी। पहले उन्होंने सोनल दिनूषा को 84 रन पर आउट किया, फिर प्रभात जयसूर्या को पहली गेंद पर बोल्ड किया और अगली गेंद पर लहिरू कुमारा को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका 284 रन पर ऑलआउट हुआ। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रन का टारगेट दिया। भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की दूसरी पारी 77.4 ओवर में 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने केशरा नुवान्था को बोल्ड कर श्रीलंका की पारी खत्म की और मैच में 10 विकेट पूरे किए।

सुथार ने एक ओवर में 3 विकेट लिए

मानव सुथार ने श्रीलंका की दूसरी पारी के 75वें ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया। उन्होंने पहले सोनल दिनूषा को 84 रन पर आउट किया। इसके बाद सुथार ने प्रभात जयसूर्या को पहली ही गेंद पर बोल्ड किया और अगली गेंद पर लाहिरू कुमारा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। यह टेस्ट में सुथार का लगातार दूसरे मैच में दूसरा 5 विकेट हॉल है।

Football

क्या 2026 विश्व कप की सनसनी केप वर्डे से भिड़ेगी भारतीय टीम?

सितंबर-अक्तूबर में दौरा प्रस्तावित

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत सितंबर-अक्तूबर के बीच केप वर्डे की मेजबानी कर सकता है, दोनों टीमों के बीच दोस्ताना मुकाबले की बातचीत जारी है। केप वर्डे ने 2026 फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार नॉकआउट दौर में जगह बनाई थी। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए आने वाले महीनों में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, भारत सितंबर के अंत से अक्तूबर की शुरुआत के बीच हाल में 2026 फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली केप वर्डे की मेजबानी कर सकता है। प्रस्तावित मुकाबला 30 सितंबर से 6 अक्तूबर के बीच खेले जाने की संभावना है। हालांकि, मैच की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 'बातचीत जारी है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि, इस बात की काफी संभावना है कि भारत 30 सितंबर से 6 अक्तूबर के बीच केप वर्डे की मेजबानी करेगा।'

सूत्र ने कहा, 'मैच का आयोजन स्थल और तारीख आधिकारिक तौर पर फैसला होने के बाद तय किए जाएंगे। इससे जुड़ी प्रक्रियाएं और विचार-विमर्श जारी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।'

'विराट बस एक फोन कॉल दूर हैं'

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली के साथ बिताए समय और उनसे मिली सीख को लेकर बड़ा खुलासा किया है. कॉक्स ने बताया कि कोहली उनके लिए सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह रहे हैं. जब भी उन्हें किसी सलाह या मदद की जरूरत होती है, विराट हमेशा फोन के दूसरी तरफ मौजूद रहते हैं. जॉर्डन कॉक्स आईपीएल में आरसीबी टीम का हिस्सा हैं. कॉक्स ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली के साथ करीब चार महीने भारत में बिताए.

इस दौरान वह कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उनके अनुभव से सीखने में सक्षम रहे. हालांकि कॉक्स ने दोनों के बीच हुई हर बातचीत का खुलासा नहीं किया, लेकिन डेब्यू से पहले कोहली की दी गई सलाह को उन्होंने बेहद खास बताया।

दिल्ली प्रीमियर लीग:

सार्थक नंबर 1

यश ढुल को छोड़ा पीछे, दिल्ली प्रीमियर लीग में छठा पचासा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे सार्थक रंजन का तूफान जारी है। इस लीग के अपने 7वें मैच में सार्थक ने छठी बार अर्धशतक ठोका है। वहीं वह यश ढुल को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल 2026 में केकेआर के स्क्वाड का हिस्सा रहे सार्थक रंजन को एक भी मैच में जगह नहीं मिली थी।

अब इस फॉर्म से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सार्थक ने पुरानी दिल्ली के खिलाफ 32वें मैच में 51 गेंद पर 78 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी शानदार पारी के बावजूद उनकी टीम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को जीत नहीं मिल पाई। इस मैच में 20 रन से जीत के साथ पुरानी दिल्ली 6 ने अंकतालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली। सार्थक रंजन ने 100, 64, 95, 65, 57, 59, 10, 78 की पारियां अब तक खेली हैं। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 30 रन से मात दी। इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली के दोनों इन फॉर्म ओपनर्स सिद्धार्थ जून और यश ढुल खाता भी नहीं खोल सके।

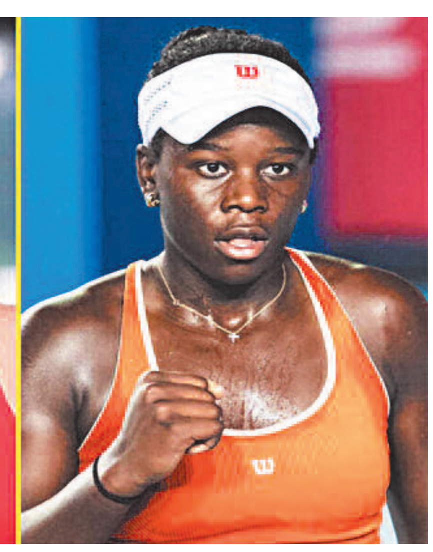

सिनसिनाटी ओपन:

सबालेंका, एंड्रीवा, और गॉफ ने चौथे राउंड में जगह बनाई

सिनसिनाटी, एजेंसी । आर्यना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। सबालेंका ने 54 मिनट तक चले मुकाबले में सबालेंका ने वांग शिन्यु को 6-1, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ, सबालेंका अब अपने करियर में 45 डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट्स में राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। उनकी इस जीत ने सिनसिनाटी में जीत के मामले में उन्हें सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे आगे कर दिया है। सबालेंका के नाम अब डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट्स में 50 करियर जीत है। सबालेंका 2009 में इस फॉर्मेट के शुरू होने के बाद से ऐसा करने वाली सेरेना विलियम्स (104) और इगा स्वियाटेक (58) के बाद तीसरी खिलाड़ी हैं।

इस बीच, नंबर 5 सीड मीरा एंड्रीव नंबर 32 सीड जेनिस त्जेन को हराकर चौथे राउंड में पहुंच गईं। एंड्रीव ने 1 घंटे 42 मिनट तक चले इस मैच में 6-1, 7-6(5) से जीत दर्ज की। एंड्रीवा, जो 2024 में टूर्नामेंट में अपनी पिछली एकमात्र उपस्थिति में सिनसिनाटी में क्वार्टर फाइनलिस्ट थीं, ने जून में रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद पहली बार लगातार मैच जीते हैं।

अब उनका सामना इस साल चौथी बार नंबर 10 सीड मार्टा कोस्त्युक से होगा। कोस्त्युक उनके हेड-टू-हेड में 2-1 से आगे हैं, हालांकि पिछली मुलाकात में एंड्रीवा ने रोलैंड गैरोस सेमीफाइनल में कोस्त्युक को हराया था। 2023 की चैंपियन कोको गॉफ ने भी साथी अमेरिकन एन ली पर 6-1, 7-6 (3) से जीत हासिल करके 2026 सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।

गॉफ अब अपने करियर के 36वें डब्ल्यूटीए 1000 चौथे राउंड में हैं, जिसमें इस सीजन के छह शामिल हैं। सिनसिनाटी एकल में हिस्सा लेने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में सिर्फ एरिना सबालेंका (44), कैरोलिन प्लिसकोवा (44), एलिना स्वितोलिना (43), इगा स्वियाटेक (38) और जेसिका पेगुला (38) के नाम उनसे ज्यादा हैं।

महानगर मेट्रो
www.mahanagarmetro.com
अहमदाबाद, (गुरुवार)
20 अगस्त 2026

व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मामले में जान्हवी कपूर को राहत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम सहूलियतें दी हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। एआई के जरिए किसी की तस्वीरों व वीडियो आदि से छेड़छाड़ कर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। इसके नुकसान को लेकर फिल्मी सितारे काफी सतर्क हैं और उन्होंने अदालत का रुख किया है। बीते दिनों तब्बू ने कोर्ट का दरवाजा खटखाया था। कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी। इसके बाद जान्हवी कपूर ने भी अपने व्यकित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की।

जान्हवी कपूर ने क्या मांग की?

जान्हवी कपूर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।अभिनेत्री ने 5,000 से अधिक वेबपेज, पोस्ट और एआई कंटेंट हटाने की मांग की थी। साथ ही फैन पेज पर रोक लगाने की भी मांग की। बीते दिन मंगलवार को कोर्ट ने जान्हवी से जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया। अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने 5,000 से अधिक वेबपेज, सोशल मीडिया पोस्ट, एआई-जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, फर्जी अकाउंट, नकली बुकिंग एजेंसियों और चैटबॉट्स को हटाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत और दलीलें व्यापक हैं। अदालत ने जान्हवी कपूर के वकील को उन वेबपेजों की सूची देने को कहा गया, जिन पर स्पष्ट रूप से अश्लील कंटेंट है अथवा उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की जा रही है। हालांकि, अदालत ने फैन पेज हटाने से इनकार कर दिया है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया।

तब्बू ने भी खटखटाया था दरवाजा

इससे पहले व्यक्तिव अधिकारों को लेकर तब्बू ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने अभिनेत्री को राहत दी। कोर्ट ने तब्बू के नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति व्यावसायिक या अनुचित इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ अदालत ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया गया है कि वे तब्बू से जुड़े एआई जेनेरेटिड, डीपफेक, अपमानजनक व आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाएं।

ये सितारे भी पहुंचे अदालत की शरण में

इससे पहले बीते महीने ही अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपनी एआई से बनीं डीपफेक तस्वीरों और मॉर्फ्ड कंटेंट के खिलाफ अदालत का रुख किया। उन्होंने याचिका दायर कर इस किस्म के कंटेंट पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। इस मामले में उन्हें भी अदालत से राहत मिली। पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इनके अलावा ऋतिक रोशन, करण जौहर, अक्षय कुमार, कुमार सानू और अक्किनेनी नागार्जुन समेत तमाम सितारे अपने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत की शरण में पहुंच चुके हैं।

द डिप्लोमैट के बाद फिर साथ काम करेंगे जॉन अब्राहम और शिवम नायर?

फिल्म 'द डिप्लोमैट' के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर शिवम नायर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसी चर्चा है कि दोनों ने आगामी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों जिस एक्शन थ्रिलर फिल्म पर काम कर रहे हैं, उसका अभी कोई नाम नहीं रखा गया है। इसमें दो मेल लीड होंगे।

जॉन को तुरंत पसंद आया फिल्म का कॉन्सेप्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन की अगली फिल्म एक कमर्शियल एंटरटेनर होगी। इसे शिवम नायर के अब तक के सबसे मेनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में से भी एक बताया जा रहा है। हालांकि, फिल्म की बाकी कास्ट और दूसरे हीरो को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, शुरुआती बातचीत के दौरान ही जॉन अब्राहम को यह प्रोजेक्ट पसंद आ गया। पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जॉन इस कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत इसके लिए तैयार हो गए'। जॉन की इस फिल्म को लेकर खबर है कि मेकर्स इस साल के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आने वाले महीनों में प्रोडक्शन शेड्यूल तय होने की उम्मीद है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 2027 के आखिर में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। मेकर्स की ओर से आधिकारिक एलान होने के बाद ही फिल्म के टाइटल, कास्ट और प्रोडक्शन के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

फिल्म 'द डिप्लोमैट' साल 2025 में आई

जॉन अब्राहम और शिवम नायर ने पहली बार फिल्म 'द डिप्लोमैट' में साथ काम किया था। यह फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। 2025 में आई यह फिल्म उज्मा अहमद की असल जिंदगी की कहानी और पाकिस्तान में बंधक बनाए जाने के बाद भारत लौटने की उनकी कोशिशों पर आधारित थी। जॉन ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जे पी सिंह का किरदार निभाया।

जॉन अब्राहम के कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं

शिवम नायर की फिल्म के अलावा जॉन अब्राहम के पास कई और प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आगामी फिल्मों में 'फोर्स 3' शामिल है। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 19 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जॉन मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक से भी जुड़े हैं, इसका नाम अभी तय नहीं है। रोहित शेट्टी इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगे।

तकनीक कभी भी कला की जगह नहीं ले सकती

अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश इन दिनों वेब गेमिंग रियलिटी शो 'प्लेग्राउंड' के 5वें सीजन में जज और मेंटोर के रूप में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का मानना है कि एआई किसी भी इंसानी चीजों की जगह नहीं ले सकता है। गेमिंग शो के प्रमोशन के दौरान मुंबई में अभिनेत्री ने बातचीत की। इस दौरान अभिनेत्री से पूछा गया कि क्या तकनीक कला को खत्म कर रही है। इस सवाल का जवाब अभिनेत्री ने बड़ी सहजता से दिया। उन्होंने कहा, 'तकनीक कभी भी असली आर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी ऐसे शो हों, जिनमें एआई का इस्तेमाल किया गया हो। हमने अपने शो में एक एआई कॉन्सेप्ट भी शामिल किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस शो में एआई को मेंटर बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है।'

हालांकि, अभिनेत्री ने भी माना कि कुछ हद तक, विजुअल एंटरटेनमेंट में, एआई बेहतर बनाने के लिए एक कारगर टूल हो सकता है। बता दें कि अभिनेत्री इन दिनों अरुष भोला, एल्विश यादव के साथ गेमिंग रियलिटी शो में मेंटोर के रूप में नजर आ रही हैं। ये तीनों इस सीजन में अलग-अलग टीमों का नेतृत्व करते नजर आएंगे। इसके अलावा, इस शो के मुख्य फाउंडर्स और निर्माताओं (जैसे कैरी मिनाटी, मोर्टल और ट्रिगर इनसान) भी अलग-अलग रूपों में इस सीरीज से जुड़े हुए हैं। शो की बात करें, तो यह भारत का पहला गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स रियलिटी शो है, जो एंटरटेनमेंट, कंपटीशन और इन्फ्लुएंसर कल्चर को एक साथ मिलाकर बना शो है। यह शो वर्चुअल प्लेग्राउंड के कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। इसमें यंग क्रिएटर्स, गेमर्स और इंटरनेट की मशहूर हस्तियां एक साथ आती हैं। इसमें अलग-अलग चैलेंज में हिस्सा लिया जाता है और साथ ही दोस्ती, दुश्मनी और टीम वर्क को भी मैनेज किया जाता है। यह शो प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जा रहा है।

अब खुद को निर्दोष साबित करना चाहती हूं

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती 'द ट्रेटर्स' सीजन 2' का हिस्सा हैं। इस शो में एक बातचीत के दौरान रिया ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपने ऊपर हुई जांच-पड़ताल के बारे में बात की है। रिया ने कहा... शो 'द ट्रेटर्स 2' में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने कहा कि कई साल तक शक के दायरे में रहने के बाद अब वह लोगों के नजरिए में निर्दोष साबित होना चाहती हैं। रिया ने कहा मैं कई साल तक संदेह के घेरे में रहने के बाद खुद को निर्दोष साबित करना चाहती हूं। कई साल मैंने लोगों के शक में रहकर गुजारे हैं। मैं अब इसे खत्म करना चाहती हूं। मुझे इस साल क्लीन चिट मिल चुकी है। मैं चाहती हूं कि सब मुझे बेगुनाह समझें।

क्या है 'द ट्रेटर्स 2'

द ट्रेटर्स की कहानी दो ग्रुप्स के इर्द-गिर्द घूमती है। इस ग्रुप में इनोसेंट्स को मिलकर छिपे हुए गद्दारों की पहचान करनी होगी और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होने से पहले ही खत्म करना होगा। वहीं, गद्दार अपनी पहचान छिपाते हुए चुपके से दूसरों के खिलाफ साजिश रचते हैं।

इमरान हाशमी ने ली आवारापन से 10 गुना ज्यादा फीस!

इमरान हाशमी की कल्ट क्लाकिस फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म में दिशा पटानी और शबाना आजनी भी अहम किरदारों में है। इन एक्टर्स ने फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज की है। फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है। फिल्म की रिलीज से पहले अब इसकी स्टारकास्ट की कथित फीस को लेकर भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी को 'आवारापन 2' में अपने आइकॉनिक किरदार शिव पंडित को दोबारा निभाने के लिए करीब 12 करोड़ रुपये फीस दी जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फीस उन्हें 2007 में आई पहली फिल्म 'आवारापन' के लिए मिली रकम से करीब 10 गुना ज्यादा है।

दिशा पटानी की फीस कितनी

फिल्म में दिशा पाटनी भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें 'आवारापन 2' के लिए करीब 5 करोड़ रुपये फीस मिल रही है। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी 'आवारापन 2' का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म में अहम भूमिका निभाने के लिए उन्हें करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच फीस दी गई है। फिलहाल ये सभी फीस के आंकड़े रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और मेकर्स या कलाकारों की तरफ से इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रुक्मिणी वसंत ने शुरू की अपनी अगली फिल्म शूटिंग की

रुक्मिणी वसंत का करियर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा! एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स के साथ अब एक्ट्रेस ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, यानी उनकी बढ़ती-चढ़ती फिल्मोग्राफी में एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई है। हाल ही में रुक्मिणी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के क्लैपबोर्ड की एक झलक शेयर करते हुए शूटिंग शुरू होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। इस अनटाइटल्ड मलयालम फिल्म में रुक्मिणी के साथ मलयालम स्टार निन पाउली नजर आएंगे। यानी साउथ के दो टैलेंटेड स्टार्स का ये कॉम्बिनेशन पहले से ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेट से एक झलक शेयर करते हुए रुक्मिणी ने लिखा, 'और बस, ये सफर शुरू हो गया।

किसी ऐसी जगह का हिस्सा बनना, जिसे आपने इतने लंबे समय तक दूर से निहारा और सराहा हो, अपने आप में बेहद खास एहसास है। और अब उसी जगह का एक छोटा सा हिस्सा बन पाना मेरे लिए वाकई बहुत स्पेशल फर्स्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए दिल से शुक्रगुज़ार हूँ '। अब फिल्म की टीम भी इसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है। इस प्रोजेक्ट को चार्ली और नयट्ट जैसी शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर मार्टिन प्रक्कट का सपोर्ट मिला है। वहीं जय जय जय जय जय हे के राइटर्स में शामिल रहे नाशिद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। रुक्मिणी वसंत और निन पाउली के साथ इन नामों का जुड़ना हक्क1 को मलयालम सिनेमा की मोस्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग फिल्मों में से एक बना रहा है। सप्त सागरदाचे एलो और कंतारा जैसी फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से रुक्मिणी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी सिर्फ एक प्रॉमिसिंग कन्नड़ टैलेंट के तौर पर देखी जाने वाली रुक्मिणी अब धीरे-धीरे पूरे साउथ इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा डिमांड वाली यंग एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बना चुकी हैं। रुक्मिणी अब टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स को लेकर भी तैयार हैं। इसके अलावा उनके खाते में मच-अवेटेड बिग-टिकट फिल्म ड्रैगन भी है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान बनाने की मांग, पूर्व पीएम देउबा के बयान से क्यों गरमाई सियासत

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने देश की राष्ट्रीय पहचान को सनातन धर्म से जोड़ने की बात कही है। उनके नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस गुट के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को राजनीतिक ताकत मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। देउबा ने सम्मेलन के समापन समारोह में खुद को हिंदू बताते हुए अपनी राजनीतिक सोच भी साफ की। पारित प्रस्ताव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें सनातन धर्म के साथ हिंदू, बौद्ध और किरात परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही सभी धर्मों और समुदायों की धार्मिक आजादी, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही गई है। यानी प्रस्ताव में नेपाल की पारंपरिक धार्मिक पहचान को मजबूत करने के साथ दूसरे समुदायों के अधिकारों की बात भी शामिल है। नेपाली कांग्रेस के दूसरे गुट ने सम्मेलन में पारित प्रस्तावों और दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता विनोद चालिसे ने कहा कि सम्मेलन में हुए काम और नेताओं के बयानों पर पार्टी की नजर है। इससे साफ है कि सनातन धर्म और राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा केवल नेपाल की व्यापक राजनीति में ही नहीं, बल्कि नेपाली कांग्रेस के भीतर भी मतभेद का कारण बन सकता है।

लहरों में फंसे भारतीय मूल के बच्चे को बचाने वाले 16 साल के किशोर से मिले ट्रंप, किया सम्मानित; मामला क्या

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 25 जुलाई को 10 वर्षीय भारतीय मूल का बच्चा नाथनियल राय समुद्र की तेज लहरों में फंस गया था। वह सांता क्रूज के सीब्राइट बीच पर पानी में था। इसी दौरान उसने अपना संतुलन खो दिया और लहरों की चपेट में आ गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद 16 वर्षीय लाइफगार्ड राइडर विलियम्स ने बच्चे को मुश्किल में देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। विलियम्स ने बताया कि उसने बच्चे को लाइफगार्ड टावर से करीब 20 गज दूर टखने तक पानी में अपना संतुलन खोते देखा था। खतरा समझते ही वह उसकी तरफ दौड़ा। उसने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में लाइफगार्ड अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं। उसका पूरा ध्यान बच्चे को जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकालने पर था। बचाव की यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बचाव का वीडियो सामने आने के बाद ट्रंप की भी इस घटना पर नजर पड़ी। उन्होंने लाइफगार्ड विलियम्स और उसके परिवार को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया।

खूंखार आतंकी संगठन अल-शबाब का हमला नाकाम, सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 30 आतंकी ढेर

जाम्बिया, एजेंसी। अफ्रीकी देश जाम्बिया में राष्ट्रपति हकाइंदे हिचिलेमा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। जाम्बिया के निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त, 2026 को इसकी घोषणा की। उन्हें 14 अगस्त को हुए राष्ट्रपति चुनाव का सीधा विजेता घोषित किया गया। हिचिलेमा ने 51 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए। आयोग के अनुसार, हिचिलेमा को 2,965,326 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रायन मुंडुबिले को 1,856,217 वोट प्राप्त हुए। आयोग की अध्यक्ष म्वांगाला ज़ालूमिस ने हिचिलेमा को राष्ट्रपति-निर्वाचित घोषित किया। मतगणना 15 अगस्त को मतदान अधिकारियों पर हमले और मतपत्रों की चोरी के कारण निलंबित हुई, फिर कड़ी सुरक्षा में शुरू की गई।

बिग बेंड नेशनल पार्क में सीमा नहीं बनेगी, ट्रंप प्रशासन ने विवादित परियोजना रोकी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने बिग बेंड नेशनल पार्क में एक विवादास्पद सीमा परियोजना का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय एजेंसी प्रमुख के टेक्सास दौरे के बाद जमीनी मूल्यांकन के लिए लिया गया है। यह परियोजना दक्षिणी टेक्सास में राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरनी थी। इस परियोजना को आलोचकों के कड़े द्विदलीय विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि यह क्षेत्र एक प्राचीन पर्यावरणीय इलाका है। उनके अनुसार, यह परियोजना इस क्षेत्र को खराब कर रही है। उनका तर्क है कि क्षेत्र का कठिन और दूरस्थ इलाका पहले से ही प्रवासियों और तस्करों को रोकता है।

दक्षिण कोरिया को छोड़ उत्तर कोरिया के करीब क्यों जा रहे ट्रंप अमेरिका के सहयोगियों की बढ़ी चिंता

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को कम करने का फैसला किया है। इससे केवल लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे दक्षिण कोरिया को ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अमेरिका के सुरक्षा हितों को लेकर भी बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

ट्रंप ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग-थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। ट्रंप अक्सर विदेश नीति में फायदे-नुकसान और व्यक्तिगत रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं। यही उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की एक खास पहचान रही है।

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में यूरोपीय मामलों के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैन फ्राइड ने कहा, मुझे इसमें अमेरिका का कोई हित नजर नहीं आता। किसी भी स्तर पर यह समझ में नहीं आता। इससे दक्षिण कोरिया कमजोर होता है, जापान कमजोर होता है, ताइवान डरता है, नाटो चिंतित होता है और चीन को हौसला मिलता है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया का भी हौसला बढ़ता है। ओबामा प्रशासन में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैनी रसेल ने कहा कि उत्तर

कोरिया के पक्ष में ट्रंप का फैसला ऐसी श्रेणी में आता है, जिसमें यह समझना मुश्किल है कि इससे स्थिति और खराब कैसे हो सकती है। उत्तर कोरिया हर साल होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, यह दुखद रूप से पूरी तरह उलटा है। ट्रंप एक सहयोगी को सजा दे रहे हैं और एक विरोधी को बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रसेल ने कहा, ट्रंप अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की कीमत पर किम जोंग उन को नाराज होने से बचा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया को इससे क्या संदेश जाता है : रविवार को ट्रंप ने अमेरिकी सेना को 11 दिन चलने वाले उलची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आकार छोटा करने का आदेश दिया। यह सैन्य अभ्यास सोमवार को तय समय पर शुरू हो गया। हालांकि, यह साफ नहीं था कि अभ्यास के किन-किन हिस्सों को कम किया जाएगा। ट्रंप के इस एलान से दक्षिण कोरिया में बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिण कोरिया दशकों से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि उसके सामने परमाणु हथियार रखने वाले उत्तर कोरिया का खतरा मौजूद है।

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में कई डेमोक्रेट सांसदों ने भी तुरंत ट्रंप की आलोचना की। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद और विदेश मामलों की समिति में सबसे बड़े डेमोक्रेट नेता ग्रेग मीक्स ने एक बयान में कहा, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के साथ विरोधी जैसा व्यवहार करने से हमारे गठबंधन कमजोर होते हैं और चीन तथा उत्तर कोरिया को फायदा मिलता है। सोमवार को ट्रंप ने अपने फैसले का फिर समर्थन किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की फोन पर बात करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान काम कर चुके सेवानिवृत्त अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बेहद अहम हैं। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से दूरी बना रखी है और उसने हथियारों का परीक्षण भी तेज कर दिया है। वुड ने कहा, हम यह भी नहीं चाहते कि दक्षिण कोरिया यह निष्कर्ष निकाले कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास परमाणु हथियार हासिल करना ही एकमात्र गारंटी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरह के प्रशासन में रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े पदों पर रह चुके मैथ्यू क्रोनिग ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई लोगों में अपने परमाणु हथियार विकसित करने के विचार का समर्थन लगातार बढ़ा है। क्रोनिग ने कहा, अमेरिका दक्षिण कोरिया को यह भरोसा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करता रहा है कि वह सुरक्षित है। अब वाशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से जुड़े क्रोनिग ने कहा कि सैन्य अभ्यासों का आकार कम करने से संभवतः इस भरोसे को नुकसान पहुंचता है।

ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा दक्षिण कोरिया : ट्रंप ने यह फैसला तब लिया, जब दक्षिण कोरिया उन्हें खुश करने और उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रहा था। दक्षिण कोरिया व्यापार और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अमेरिका का साथ चाहता था। पिछले साल नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग जब ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले वहां की शानदार सजावट की तारीफ की। ओवल ऑफिस को सुनहरे रंग की सजावट से सजाया गया था। ली ने ट्रंप की इस बात का भी समर्थन किया कि अगर वह 2020 में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाते, तो किम जोंग उन परमाणु हथियार बनाने की अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाते। ली ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाया जा सकता है।

एफबीआई मुख्यालय अब कहां बनेगा: ट्रंप प्रशासन को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, हेडक्वार्टर की शिफ्टिंग पर लगाई रोक

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के एक जज ने सोमवार को एफबीआई के मुख्यालय को वॉशिंगटन की एक फेडरल ऑफिस बिल्डिंग में ले जाने की योजना पर रोक लगा दी। जज ने पाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मैरीलैंड में पास की गई एक नई बिल्डिंग बनाने की योजना को गैर-कानूनी तरीके से रद्द कर दिया था।

यह फैसला देश की प्रमुख कानून लागू करने वाली एजेंसी का मुख्य कार्यालय कहां बनाया जाए, इस पर बरसों से चल रही लड़ाई में एक नया घटनाक्रम है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट में एक जगह चुनी गई थी, लेकिन ट्रंप की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने पिछले साल उस फैसले को पलटने की कोशिश की।

ट्रंप प्रशासन क्या चाहता था : वे चाहते थे कि एफबीआई के मौजूदा मुख्यालय से कुछ ब्लॉक दूर स्थित फेडरल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाए।

जिला जज चुआंग ने क्या फैसला सुनाया : राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से नियुक्त अमेरिकी जिला जज थियोडोर डी. चुआंग ने फैसला सुनाया कि यह कदम कानून के मुताबिक नहीं था। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को एफबीआई को रीगन बिल्डिंग में ले जाने के लिए उसकी मरम्मत करने या फंड का दोबारा इस्तेमाल करने से रोक दिया। मुकदमा किसने दायर किया था न्याय विभाग और एफबीआई के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यह मुकदमा मैरीलैंड राज्य और प्रिंस जॉर्ज काउंटी ने दायर किया था।

मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा : मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन (जो डेमोक्रेट हैं) ने एक बयान में कहा, मैरीलैंड और प्रिंस जॉर्ज काउंटी ने एफबीआई मुख्यालय हासिल करने के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक काम किया है। इसके साथ ही करोड़ों डॉलर देने का वादा किया। एफबीआई को रीगन बिल्डिंग में ले जाने और इस प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस द्वारा अलग रखे गए फंड को दूसरी जगह लगाने की ट्रंप प्रशासन की गैर-कानूनी कोशिश को रोककर, कोर्ट ने ग्रीनबेल्ट लौटने का रास्ता साफ कर दिया है।

एफबीआई का मौजूदा मुख्यालय कहां है : एफबीआई का मौजूदा मुख्यालय, पेन्सिलवेनिया एवेन्यू पर स्थित जे. एडगर हूवर बिल्डिंग में 1975 में खोला गया था। मुख्यालय को दूसरी जगह ले जाने के पक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि ब्रूटलिस्ट-शैली की यह इमारत अब जर्जर हो चुकी है। इसके चारों ओर पैदल चलने वालों को गिरते मलबे से बचाने के लिए जाल लगे हैं। दोनों राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद, पास के वर्जीनिया के बजाय मैरीलैंड वाली जगह को चुना गया था।

भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के दावे पर घिरे पीएम बालेन; 26 अगस्त को संसद में विपक्ष करेगा सवालों की बौछार

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अगले सप्ताह प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का सामना करेंगे। सदन के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे सवाल-जवाब का सत्र 26 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष ने सदन को बताया कि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2026 के अध्याय-9 के तहत प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर सत्र निर्धारित किया गया है। इस दौरान सदन में मौजूद प्रत्येक राजनीतिक दल से कम से कम एक सांसद प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकेगा। अध्यक्ष ने सांसदों से अपने सवाल संक्षिप्त रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री शाह के संसद में आने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब विपक्ष लंबे समय से उनके एक बयान पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। दरअसल, 31 मई को संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान शाह ने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है कि नेपाल ने भारत के क्षेत्र में भी 'अतिक्रमण' किया है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से इस बयान को स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की बात कही गई है तो प्रधानमंत्री को उसके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए या फिर अपना बयान वापस लेना चाहिए। विपक्ष की लगातार मांगों के बाद प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल ने प्रधानमंत्री को सदन में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए कहा। संसद सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ने उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है जो उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं। आर्याल ने कहा कि सांसद लंबे समय से प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण विषयों और उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों पर सवालों का जवाब देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने उसकी अलग व्याख्या पेश की थी। मंत्रालय ने कहा था कि शाह की टिप्पणी दोनों देशों के बीच 'नो-मैन्स लैंड में अतिक्रमण' और 'सीमा पार कब्जे' से जुड़ी थी, न कि किसी क्षेत्र पर औपचारिक दावा करने के संदर्भ में। इसके बावजूद विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री से सदन में सीधे स्पष्टीकरण की मांग करते रहे।

दो बंदूकें लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, पहले टीचर पर चलाई गोली फिर साथी छात्र की हत्या कर की खुदकुशी

मनीला, एजेंसी। दक्षिणी फिलीपींस में एक हाई स्कूल में मंगलवार को दो बंदूकें लिए एक छात्र ने अपने ही एक साथी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फिर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

जाम्बोआंगा शहर के मेयर खाइमर अदान ओलासो ने कहा कि हमलावर ने शायद हमले की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए बॉडी कैमरा पहना हुआ था। यह हमला उनके शहर में एटेनिओ डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी कैंपस के हाई स्कूल में हुआ। उन्होंने बताया कि दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

मेयर ने क्या बताया : ओलासो ने रेडियो नेटवर्क को बताया कि हमलावर ने पहले एक टीचर पर गोली चलाई, लेकिन यह साफ नहीं है कि टीचर को

गोली लगी या नहीं। इसके बाद उसने अपने एक साथी छात्र को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसने खुद को गोली मार ली।

छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया : हाई स्कूल की बिल्डिंग में गोली चलने की आवाज के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह बिल्डिंग एक सुरक्षित कैंपस में है, जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस से अलग है। उस बड़े कैंपस में यूनिवर्सिटी के कॉलेज और प्रोफेशनल स्कूल हैं, जो जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर में स्थित हैं।

पुलिस ने क्या कहा : गोलीबारी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों से शांत रहने और बच्चों को ले जाने के लिए हाई स्कूल की सलाह और व्यवस्थाओं का पालन करने को कहा।

पुलिस ने जनता से क्या अपील की : नेशनल पुलिस चीफ जनरल जोस मेलेंसियो नार्टाटेज जूनियर ने कहा, अधिकारी अभी घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगा रहे हैं। पुलिस सही समय पर पक्की जानकारी देगी और जनता से अपील करती है कि वे ऐसी बिना पुष्टि वाली खबरें, तस्वीरें या वीडियो शेयर न करें जिनसे बेवजह चिंता पैदा हो सकती है। नार्टाटेज ने कहा, नेशनल पुलिस जनता को भरोसा दिलाती है कि स्कूल समुदाय की सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिकता है। हम स्कूल प्रशासन, माता-पिता, अभिभावकों और समुदाय का उनके धैर्य, सहयोग और समझदारी के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अधिकारी स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं। यह गोलीबारी तब हुई जब पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि देश भर के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले जून में मध्य टैकलोबन शहर में हुई गोलीबारी में तीन हाई स्कूल छात्र मारे गए थे और कम से कम 20 अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने उस गोलीबारी को अंजाम देने के आरोप में 14 और 15 साल के दो छात्रों को गिरफ्तार किया था। फिलीपींस में बंदूक के इस्तेमाल से जुड़े अपराध आम हैं, जिसका एक कारण बिना लाइसेंस वाली बंदूकों का बड़ी संख्या में होना है, लेकिन स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं।

बच्चों को अकेले खेलने की आजादी पर अमेरिका में बदली सोच, देश के 13 राज्यों ने क्यों दी कानून में ढील

इयान फ्रिश, एजेंसी। अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से बनाए गए सख्त नियमों पर अब बहस तेज हो रही है। कई जगह अभिभावकों को बच्चों को अकेले पार्क भेजने, आसपास खेलने देने या छोटी दूरी पर अकेले जाने देने पर कार्रवाई का डर रहता था। अब इस सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। 13 अमेरिकी राज्यों ने बाल-उपेक्षा से जुड़े नियमों में ढील दी है, ताकि बच्चों को उम्र के हिसाब से कुछ स्वतंत्रता देने पर माता-पिता को कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। अटलांटा में एक छह साल के बच्चे के अकेले पार्क में खेलने का मामला इस बहस का उदाहरण बना। बच्चे को पार्क में अकेले देखकर एक महिला ने बाल

कल्याण विभाग में उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत कर दी। इसके बाद मैलरी शर्ली और उनके पति क्रिस्टोफर प्लेसेंट्स से पूछताछ हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपील के बाद दंपती को आरोपों से बरी कर दिया गया। इस मामले ने सवाल खड़ा किया कि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें स्वतंत्रता देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

13 राज्यों ने नियमों में ढील क्यों दी : अमेरिका में फ्री-रेंज किड्स आंदोलन को मिल रहे समर्थन के बीच 13 राज्यों ने अपने बाल-उपेक्षा कानूनों में बदलाव किया है। इसका मकसद यह स्पष्ट करना है कि बच्चों को उनकी उम्र और समझ के मुताबिक अकेले बाहर खेलने या आसपास जाने की अनुमति देना अपने आप में उपेक्षा नहीं माना जाए। समर्थकों का तर्क है कि बच्चों को हर समय निगरानी में रखने के बजाय सीमित स्वतंत्रता देना उनके आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर सकता है। बच्चों की स्वतंत्रता को लेकर सोच में बदलाव के बीच आंकड़े भी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। द ब्रिटिश चिल्ड्रन प्ले सर्वे के अनुसार, पिछली पीढ़ी के बच्चों को औसतन 8.9 वर्ष की उम्र में अकेले बाहर खेलने की अनुमति मिल जाती थी। आज यह उम्र बढ़कर औसतन 10.7 वर्ष हो गई है। यानी बच्चों को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति अब करीब दो साल देर से मिल रही है। वहीं करीब 34 फीसदी बच्चे स्कूल के बाद बाहर खेलने नहीं जाते हैं। बच्चों के लिए खेलना केवल मनोरंजन नहीं है। इससे उनका शारीरिक विकास होता है और वे दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना, छोटे फैसले लेना और परिस्थितियों को समझना सीखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पांच से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को रोज करीब 60 मिनट खेलना-कूदना चाहिए।

भारत के चुनावी मॉडल के मुरीद हुए ट्रंप, अमेरिका में वोटर आईडी अनिवार्य करने की मांग क्यों हुई तेज

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में हर मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की अपनी मांग फिर दोहराई है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने भारत की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका को भी चुनाव में पहचान और नागरिकता से जुड़े नियम कड़े करने चाहिए।

भारत के चुनाव को लेकर ट्रंप ने क्या दावा किया : ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक मतपत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अमेरिका में अनिवार्य फोटो पहचान की जरूरत के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना है कि इससे चुनाव में धोखाधड़ी की आशंका को कम किया जा सकता है।

सेव अमेरिका एक्ट में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं : ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजीबिलिटी एक्ट है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका में मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा देशभर में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। कानून

डाक से मतदान की सुविधा पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में है। ट्रंप इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी कदम बताते हैं।

क्या अमेरिका में इस कानून को लेकर सहमति है : सेव अमेरिका एक्ट को लेकर अमेरिका में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद हैं। ट्रंप लगातार कानून पारित कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीनेट में इसे आगे बढ़ाने को लेकर अब तक ठोस कदम नहीं उठे हैं। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट पांच सप्ताह के अवकाश पर चली गई थी और कानून को लेकर कोई अंतिम प्रगति नहीं हुई। ट्रंप का तर्क है कि मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका में भी ऐसे नियम लागू करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए सेव अमेरिका एक्ट पारित करना चाहिए। हालांकि, कानून को लेकर राजनीतिक मतभेद अभी कायम हैं। भारत का उदाहरण देकर ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में पहचान पत्र और नागरिकता के सवाल को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

इमरान खान की आंखों में कितना सुधार हुआ? जेल प्रशासन ने सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में दी पूरी जानकारी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों को लेकर जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को अहम जानकारी दी है। रावलपिंडी की अदियाला जेल की ओर से अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी नजर अब 'लगभग सामान्य' हो गई है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने की मांग की है। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी आंख की बीमारी जनवरी के अंत में सामने आई थी। उन्हें दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी सीआरवीओ की समस्या बताई गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीआईएमएस कई बार ले जाया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक, पीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुहम्मद आरिफ खान और रावलपिंडी के अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के विट्रियॉ-रेटिनल विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम कुरैशी ने उनका इलाज किया।

जेल प्रशासन ने इमरान की सेहत को लेकर क्या दावा किया : जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, इलाज के बाद इमरान खान की आंख में काफी सुधार देखा गया और उनकी नजर लगभग सामान्य हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनकी सेहत की नियमित निगरानी की जा रही है। जेल के चिकित्सा अधिकारी दिन में तीन बार उनकी जांच करते हैं। इस दौरान उनके भोजन की निगरानी के साथ रक्तचाप, हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर जैसे जरूरी स्वास्थ्य मानकों की भी जांच की जाती है। प्रशासन ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी लगातार रखा गया है।

क्या इमरान खान को जेल में पर्याप्त इलाज मिल रहा : जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पर्याप्त स्वास्थ्य

सुविधाएं दी जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने भी दोनों की स्वास्थ्य जांच की है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान की इलाज संबंधी याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। उसका कहना है कि इमरान को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी आंख की हालत में सुधार इसका प्रमाण है।

इमरान खान की पार्टी इस रिपोर्ट पर क्या कह रही : जेल प्रशासन के दावे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की ओर से इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मेडिकल रिपोर्ट में इमरान का रक्तचाप अधिक पाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इमरान के निजी डॉक्टरों ने पहले उनका रक्तचाप सामान्य पाया था। अफरीदी के अनुसार, इमरान के परिवार, कानूनी टीम और निजी डॉक्टरों को 2 दिसंबर 2025 से उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में कब होगी इमरान की याचिका पर सुनवाई : इमरान खान की इलाज संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। तीन सदस्यीय पीठ इसकी सुनवाई करेगी। पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद करेंगे। इसमें न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने अदालत से इमरान की याचिका को खारिज करने की मांग की है। वहीं पीटीआई का कहना है कि इमरान को किसी विशेष रियायत की मांग नहीं है, बल्कि उन्हें कानून के अनुसार उचित इलाज और न्याय मिलना चाहिए।

फेंटेनाइल पर विवादास्पद रणनीति की समीक्षा, न्यू मेक्सिको ने मुकदमे की धमकी दी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी न्याय विभाग के आंतरिक निगरानीकर्ता ने ष्ठश्व की विवादास्पद रणनीति की समीक्षा की घोषणा की है। इस रणनीति में बड़े मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मामले बनाने के लिए फेंटेनाइल को सड़कों पर जाने दिया गया। वर्तमान और पूर्व एजेंटों ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जुआ बताया है। व्हाइट हाउस ने फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया है। यह समीक्षा एसोसिएटेड प्रेस की उस जांच के बाद आई है, जिसमें ष्ठश्व एजेंटों ने न्यू मैक्सिको में फेंटेनाइल खेपों की निगरानी की पर उन्हें जब्त नहीं किया। व्हिसलब्लोअर डेविड हॉवेल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने न्यू मैक्सिको में 卐समुदाय को जहर दिया卐। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज़ ने न्याय विभाग पर मुकदमा करने की धमकी दी है। दो अन्य व्हिसलब्लोअर भी सामने आए हैं।

Printed, Published and Owned by SARABJIT MAKAN and Printed by ILEVAN HASMUKHRAI THAKAR Printed at Jay Graphics & Printers, C/15, Vikram Chambers, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. and published from F/1 first floor, rajas apartment, near old railway crossing, maninagar east maninagar, Ahmedabad, Gujarat-380008. Editor SARABJIT MAKAN, Mo.: 9638877700, 9662420070.